www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

अब वालंटियर्स सरकार के निशाने पर हैं

पेज-3

मायावती के मुक़ाबले उमा भारती

पेज-4

सरकार एजेंट की भूमिका निभा रही है

पेज-5

वन्यजीवों को बचाने की मुहिम

पेज-7

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 19 दिसंबर-25 दिसंबर 2011 | मूल्य 5 रुपये

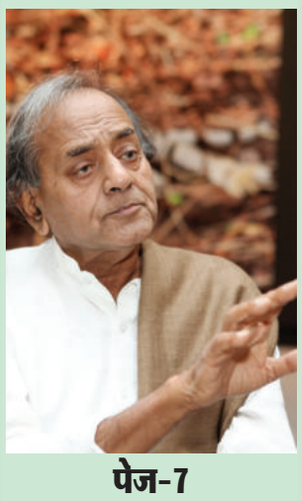

नीतीश जी सुशासन कहां है

सरोज सिंह

बिहार को आगे बढ़ाने और संवारने का सपना न केवल नीतीश सरकार ने देखा है, बल्कि यह सपना हर एक बिहारी के दिल में पिछले छह सालों से पल रहा है. न्याय की पटरी पर तेजी से विकास की दौड़ती गाड़ी देखना एक ऐसा ख्वाब है, जिसे हर बिहारी संजोए हुए है और चाहता है कि यह जितनी जल्दी हो, हक़ीक़त का लबादा पहन आम लोगों को दिखने लगे. लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है कि भ्रष्टाचार की जंजीरें विकास की गाड़ी का पहिया पूरे बिहार में रोक रही हैं. बिना परीक्षा के बहाल ज़्यादातर शिक्षक एप्पल की स्पेलिंग छात्रों को बताते हैं-ए, सट्टल सट्टल पी, एल और ई. दिमाग़ी बुखार से दो सौ से अधिक बच्चे मुज़फ्फरपुर और गया में मर जाते हैं, पर सरकार संजीदा नहीं हो पाती. जब राजधानी पटना में लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है तो पूरे सूबे की बात करना ही बेकार है. बिजली एवं उद्योग के मामले में राज्य सरकार केंद्र की ओर से भेदभाव का रोना रो रही है. निराश करने वाली बात तो यह है कि पहले कार्यकाल की दो उपलब्धियों, सड़कों एवं क़ानून व्यवस्था की चमक फीकी पड़ने लगी है. महिला सशक्तिकरण की बात तो की जा रही है, पर उनके अपहरण और हत्या के मामले काफी बढ़ गए हैं. नक्सलियों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और यह बात सामने आ गई है कि सूबे में विकास का पहिया नक्सलियों द्वारा हरी झंडी दिखाए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है.

शुरुआत महिला सशक्तिकरण के बड़े-बड़े दावों से करते हैं. सरकार कहती है कि पंचायतों में आरक्षण देकर महिलाओं को आगे आने का मौक़ा दिया गया. इसके अलावा महिलाओं के कल्याणार्थ बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, लेकिन महिलाओं पर हुए अत्याचारों के सरकारी आंकड़ों पर ही नज़र डाली जाए तो सही तस्वीर सामने आ जाएगी. सूचना के अधिकार के तहत शिव प्रकाश राय द्वारा मांगी गई सूचना में अपराध अनुसंधान विभाग ने बताया कि सूबे में महिलाओं के अपहरण व दहेज हत्या के मामले काफी बढ़ गए हैं. 2005 में महिलाओं के अपहरण के 854 व दहेज हत्या के 1044 मामले दर्ज किए गए. इसी तरह 2006 में अपहरण के 925 व दहेज हत्या के 1006, 2007 में अपहरण के 1184 व दहेज हत्या के 1091, 2008 में अपहरण के 1494 व दहेज हत्या के 1233, 2009 में अपहरण के 1997 व दहेज हत्या के 1188, 2010 में अपहरण के 2552 व दहेज हत्या के 1307 मामले और 2011 के अगस्त माह तक अपहरण के 1856 व दहेज हत्या के 953 मामले दर्ज हो चुके हैं. ये तो सरकारी आंकड़े हैं. सूबे के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहां आधे से अधिक मामले दर्ज होते ही नहीं है. खासकर महिलाओं से जुड़े मामले तो और भी दर्ज नहीं हो पाते हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट (भारत में अपराध-2010) के मुताबिक़ भी बिहार में अपहरण की वारदातें बढ़ी हैं. नक्सलियों का दबदबा इतना बढ़ गया है कि बिना लेवी दिए निर्माण कार्य शुरू करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती. अभी हाल में ही जमुई ज़िले में 15 मज़दूरों को नक्सली इसलिए उठा ले गए कि उन्हें इस काम की लेवी नहीं मिली थी. मज़दूरों को छुड़ाने के सारे प्रशासनिक प्रयास धरे रह गए और लेवी पर समझौता हो जाने के बाद ही मज़दूरों को छोड़ा गया. बिहार के 20 से ज़्यादा ज़िले नक्सल प्रभावित हो गए हैं. नक्सलियों के बंद के दौरान कई ज़िलों में कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो जाती है. आम आदमी के लिए ज़रूरी सुविधाओं की बात करें तो सड़क, बिजली, पानी एवं स्वास्थ्य को लेकर स्थिति मुस्कराने वाली नहीं है. सरकार के लाख दावों के बावजूद जन कल्याण की कई योजनाओं में कई छेद हैं.

वैश्वीकरण के दौर में आज बिहार का गया-बोधगया शहर विदेशियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में जाना जाता है. चाहे वे हिंदू धर्मावलंबी हो या बौद्ध धर्मावलंबी. हिंदुओं के बीच गया पितरों (पूर्वजों) के मोक्ष धाम के रूप में प्रसिद्ध है. सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार, पूरी दुनिया में गया ही एकमात्र ऐसा स्थान है, जहां पितरों को मोक्ष की प्राप्ति श्राद्ध या पिंड दान करने से होता है. यही कारण है कि देश-विदेश के सनातन धर्मावलंबी वर्षपर्यंत गया आते हैं. इसी प्रकार पूरी दुनिया के बौद्ध धर्मावलंबी गौतम बुद्ध की तपोभूमि एवं ज्ञान भूमि होने के कारण बोधगया आते हैं. इन सबके बावजूद इन शहरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. नागरिक सुविधाओं के नाम पर सिर्फ़ कुछ सड़कें ठीकठाक नज़र आती हैं. बहुत सारी सड़कें जर्जर हैं. शहर के सीवरेज सिस्टम और बिजली आपूर्ति की हालत बहुत दयनीय है. बताया जाता है कि गया शहर का ड्रेनेज सिस्टम जितना अच्छा था, उतना किसी शहर में नहीं था. अंग्रेज अभियंताओं ने साहेबगंज के नाम से जब गया

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बिजली

कांटी बिजली घर का भविष्य अधर में

बिजली को चुनावी मुद्दा बनाने के बावजूद सरकार बिजली उत्पादन को लेकर बहुत संजीदा नहीं दिखती. कभी वह संसाधनों के अभाव का रोना रोती है तो कभी केंद्र की उपेक्षा का. कांटी एवं बरौनी थर्मल को फिर से चालू कराने के सारे प्रयास अभी तक केवल काग़ज़ों में दिखते हैं. मुज़फ्फरपुर के कांटी में नया बिजली घर बनाने की योजना पिछले 20 वर्षों से पूरी नहीं हो पाई. इस परियोजना को केंद्र सरकार की हरी झंडी 1990 में ही मिल गई थी और अगले एक वर्ष के अंदर स्वीकृति की तमाम औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गईं. बावजूद इसके दो दशक बीत गए, परियोजना धरातल पर नहीं आ पाई, पर, कसरत जारी है. परियोजना कब तक ज़मीन पर दिखेगी, कोई नहीं जानता. बिहार बिजली बोर्ड के तत्वावधान में कांटी में पहले चरण के तहत 250 मेगावाट का बिजलीघर बनना था और दूसरे चरण के तहत विस्तार करते हुए उसकी क्षमता 500 मेगावाट किया जाना था. इसके लिए 152 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई और 10वीं से 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसे तैयार कर लेना था. राज्य सरकार से आधिकारिक स्वीकृति के बाद 500 मेगावाट क्षमता के इस बिजलीघर को वर्ष 1990 में पर्यावरण स्वीकृति और 1991 में नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी क्लीयरेंस मिल गया. इसी साल एसपीसीबी से एनओसी मिल गया. ज़मीन और पानी की भी व्यवस्था हो चुकी थी. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से मई 1993 में टेक्नो इकोनॉमिक क्लीयरेंस मिलने के बाद 1995 में योजना आयोग ने भी परियोजना को हरी झंडी दे दी. इतना सब कुछ होने के बावजूद बिजलीघर बनाने की तमाम कोशिशें काग़ज़ से बाहर नहीं आ पाईं. नियमित मॉनिटरिंग और धन के अभाव के कारण परियोजना वहीं अटकी रही. इस विलंब के कारण राज्य बिजली संकट से जूझता रहा, वहीं अब अचानक उसे 110 मेगावाट का झटका लग गया है. एयरपोर्ट अथॉरिटी की आपत्ति के बाद कांटी बिजलीघर की क्षमता में 110 मेगावाट की कटौती हो गई है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 18 वर्षों के बाद 16 जुलाई, 2008 को इसकी चिमनी की ऊंचाई को लेकर आपत्ति की और उसे कम करने के लिए कहा. लिहाज़ा सुरक्षा की दृष्टि से चिमनी की ऊंचाई घटाई गई, जिससे बिजलीघर की क्षमता भी घटानी पड़ी और इसमें 55-55 मेगावाट की कमी हो गई. अब वहां 195-195 मेगावाट की दो यूनिटों का निर्माण होगा. हालांकि नीतीश सरकार ने वहां इतनी ही क्षमता की तीसरी यूनिट भी बनाने की योजना बनाई है. इस बिजलीघर का बजट तीन करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

अपराध

पटना अपराध के लिहाज़ से अव्वल रहा. ज़िले में हत्या की 304, अपहरण की 283 और दुष्कर्म की 50 घटनाएं दर्ज की गईं. दुष्कर्म की सबसे ज़्यादा घटनाएं कटिहार में दर्ज हुईं तो अपहरण के लिहाज़ से पटना और मुज़फ्फरपुर अव्वल रहे.

श्रेणी	2010	2009	2004
संज्ञेय अपराध	1,27,453	1,22,931	1,08060
हत्या	3,362	3,152	3,948
हत्या का प्रयास	2,915	3,068	2,995
दुष्कर्म	795	929	1,390
अपहरण	3,674	3,222	3,413
डकैती	644	654	1,319
दंगा-फ़साद	8,809	8,554	9,733

(स्रोत-नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो)

टॉप टेन ज़िले (हत्या के दर्ज मामले)

पटना (304), मोतिहारी (169), मुजफ्फरपुर (148), गया (139), रोहतास (132), वैशाली (128), बेगूसराय (126), समस्तीपुर (119), नालंदा (117) और सारण (112).

आंकड़े थोड़ा-बहुत ऊपर-नीचे होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अब संगठित अपराध में कमी आई है. पहले राज्य में संगठित तरीके से फिरौती के लिए जो अपहरण होते थे, उनमें कमी आई है. अपहरण के पीछे निजी दुश्मनी भी एक बड़ा कारण है.

-अभयानंद, पुलिस महानिदेशक

हत्या की वजह (2010)

संपत्ति विवाद	916
निजी दुश्मनी	441
लाभ के लिए	352
सेक्स संबंधी	187
दहेज	168
राजनीतिक	24
उग्रवादी हिंसा	22

उद्योग

बंद चीनी मिलों का ताला कब खुलेगा

चीनी उद्योग के मोर्चे पर राज्य सरकार अब तक कुछ खास नहीं कर पाई. बंद चीनी मिलों को दोबारा चालू करने के लिए निजी कंपनियों के 32 प्रस्ताव आए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है. ये मिलें पिछले 15 सालों से बंद पड़ी हैं. इस दिशा में सरकार के तीन प्रयास बेनतीजा रहे हैं. उद्योग विभाग के प्रधान सचिव सी के मिश्रा ने बताया कि चौथी बिडिंग में क़रीब 32 कंपनियों के प्रस्ताव आए हैं. जिन बंद मिलों के लिए निविदाएं मांगी गई थीं, उनमें बनमनखी, फतुहा, वारसलिगंज गुरारू, गोरौल, सीवान, न्यू सावन, समस्तीपुर एवं लोहट आदि शामिल हैं. राज्य चीनी मिल निगम की ये मिलें 1994-95 से बंद पड़ी हैं. नीतीश सरकार ने सत्ता संभालने के बाद इन मिलों को दोबारा चालू करने की दिशा में पहल करते हुए इन्हें निजी हाथों को सौंपने का निर्णय लिया. तीन राउंड की निविदा के बाद मात्र छह मिलों के लिए निजी कंपनियां सामने आईं, जिनमें लौरिया, सुगौली, मोतीपुर, रैयाम, बिहटा एवं सकरी चीनी मिलें शामिल हैं. एचपीसीएल, इंडिया पोटाश लिमिटेड, तिरहुत इंडस्ट्रीज एवं प्रिस्टान नामक कंपनियों को उक्त मिलें लीज के आधार पर सौंपी गई हैं. शेष नौ मिलों के लिए तीन राउंड की बिडिंग में कामयाबी न मिलने के बाद गन्ना उद्योग विभाग ने हाल में चौथे राउंड की निविदा आमंत्रित की. इस बार स्थिति बदली हुई नज़र आई. निजी कंपनियों ने काफी दिलचस्पी दिखाई और उनके 32 प्रस्ताव आए. देखना है कि बंद चीनी मिलों का ताला खुल पाता है या नहीं.

वित्त मंत्रालय ने इस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के आरोप को कचरा बताया. इससे कुछ लोगों को हैरानी हुई.

दिल्ली का बाबू

बाबुओं को डीओपीटी का निर्देश

नेता ख़ुद तो अपने क्षेत्र के लोगों की शिकायतें सुनने में लापरवाही करते हैं, लेकिन जब बाबू उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते या आदर नहीं देते तो उन्हें काफी दु:ख होता है. नेताओं की ओर से बाबुओं के विरुद्ध ऐसी कई शिकायतें आने के बाद डीओपीटी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मानक नियम बनाया है कि जनप्रतिनिधियों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाए. इसे सभी मंत्रालयों, विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास भेज दिया गया है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव अलका सिरोही ने बाबुओं को सलाह दी है कि जनप्रतिनिधियों की बातों को तवज्जो दी जाए . कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों की शिकायतों–अर्जियों पर 15 दिनों के अंदर सुनवाई हो जानी चाहिए. अब देखना यह है कि बाबुओं द्वारा डीओपीटी के इस नियम का कितना पालन हो पाता है.

अनीता चौधरी की परेशानी

केंद्रीय सचिवालय, गृह और रक्षा मंत्रालय के कई महत्वपूर्ण पदों की ज़िम्मेदारी संभालने वाली हरियाणा कैडर की आईएएस अधिकारी अनीता चौधरी इन दिनों कुछ परेशान हैं. 1976 बैच की इस अधिकारी को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव नियुक्त किया गया था. इस मंत्रालय में महिला अधिकारी बहुत कम नियुक्त की जाती हैं, लेकिन अनीता को नियुक्त किया गया. पिछले साल उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग में सचिव बनाया गया, लेकिन जब केंद्रीय स्तर पर फेरबदल हुआ तो अनीता को किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं रखा गया. एक साल के भीतर उन्हें उनके पद से भी हटा दिया गया. उनकी जगह उन्हीं के बैच के अधिकारी सुब्रह्मण्यम विजय कुमार को नियुक्त कर दिया गया. सरकार के इस फ़ैसले से बाबू आश्चर्य में हैं. सभी जानते हैं कि इसके पीछे राज क्या है, लेकिन कोई बता नहीं रहा है.

बाबू की असावधानी

किसी वरिष्ठ मंत्री और उसके चहेते सलाहकार पर आरोप लगाकर कोई बाबू चैन से कैसे रह सकता है. कुछ ऐसा ही केरल कैडर के अधिकारी एवं सेबी के पूर्व सदस्य के एम अब्राहम के साथ हुआ. कुछ महीने पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, उनकी सलाहकार ओमिता पॉल एवं सेबी प्रमुख यू के सिन्हा कुछ कारपोरेट्स के प्रति नरम रुख़ अख्तियार करते हैं. मंत्रालय ने इस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के आरोप को कचरा बताया. इससे कुछ लोगों को हैरानी हुई. सूत्रों के अनुसार, अब्राहम को उनके होम कैडर भेजा जा रहा है, साथ ही उनकी शिकायत केरल के मुख्य सचिव पी प्रभाकरन से की गई है कि इस अधिकारी पर सेवा नियमों के उल्लंघन के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. आगे देखते हैं कि अब्राहम को और क्या–क्या सहना पड़ता है.

दिलीप चेरियन
dilipcherian@gmail..com

नीतीश जी, सुशासन कहां है

पृष्ठ एक का शेष

शहर बसाया था तो पूरी तैयारी के साथ शहर की विभिन्न योजनाओं का निर्माण कराया गया था. ड्रेनेज सिस्टम, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी. पूरे शहर में ट्राम की तरह कूड़े–कचरे के लिए गाड़ियां चला करती थीं, लोग उनमें ही कूड़ा–कचरा फेंका करते थे और शहर सुंदर और साफ नज़र आता था, लेकिन आज गया में नगर निगम होने के बाद भी सारे सिस्टम फेल हो गए हैं. बिना योजना के रोज बन रहे मकानों– कॉलोनियों में ड्रेनेज सिस्टम के अभाव, सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में कमी एवं बिजली आपूर्ति न होने के चलते पूरा शहर अस्त–व्यस्त नज़र आता है. गया नगर निगम के सक्रिय रहने के बावजूद शहर के सभी 53 वार्डों के अधिकांश छोटे–बड़े नाले जाम रहते हैं, जिससे कई मुहल्लों में नाले का पानी सड़कों–गलियों में पसरा रहता है. मगध के अन्य शहरों औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, शेरघाटी, टिकारी, दाऊद नगर, अरवल आदि शहरों में नगर परिषद या नगर पंचायत होने के बावजूद स्थिति नारकीय है. पेयजल आपूर्ति व्यवस्था आज़ादी के बाद भी ठीक नहीं हो पाई. जो थोड़ा–बहुत काम हुआ, वह ज़रूरत के हिसाब से ऊंट के मुंह में जीरे के समान है.

बिजली आपूर्ति व्यवस्था में भी कोई खास सुधार नहीं हुआ. विभिन्न योजनाओं के तहत खंभे गाड़े गए, तार खींचे गए, लेकिन हालत जस की तस है. शहरों में हर खंभे पर विद्युत तारों का जाल फैल गया है, जिसे बदलने या सुधारने

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

का कोई प्रयास आज तक नहीं किया गया. बिजली आपूर्ति की स्थिति बहुत ख़राब है. गया शहर को प्रतिदिन 50 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, लेकिन इस पर्यटन सीजन में भी मात्र 25 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है. गया–बोधगया में बिजली मिल भी रही है, मगध प्रमंडल के अन्य शहरों की हालत तो कहने लायक़ नहीं है. बिजली घंटे–दो घंटे ठहर जाए तो लोग बिजली विभाग नहीं, भगवान को धन्यवाद देते नज़र आते हैं. कथित सुशासन में मगध प्रमंडल के लोगों को नागरिक सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. सरकारी महकमे और अधिकारी चाहे जितनी लंबी–चौड़ी बातें कर लें, लेकिन धरातल पर कुछ ठोस नज़र नहीं आता. शेखपुरा ज़िले की कई प्रमुख सड़कें जर्जर हैं और कई बनने के साथ ही टूट गईं. प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनने वाले सड़कों का हाल और भी ख़राब है. शेखपुरा–मेहूस मार्ग का निर्माण कार्य पिछले चार सालों से अधूरा पड़ा है, यहां सिर्फ़ पत्थर बिछाकर छोड़ दिया गया. ज़िले की पहचान सामस विष्णु धाम होते हुए नालंदा को जोड़ने वाले नेमदारगंज–कोन मार्ग का भी यही हाल है. पिछले चार सालों में इस मार्ग पर महज गिट्टी बिछाने का काम हुआ है. मुख्यमंत्री को बेलाब गांव में सेवा यात्रा के तहत भोजन करना था. बभनबीघा–खलीलचक मार्ग बेहद जर्जर होने की वजह से उन्हें सामस होते हुए दस किलोमीटर घूमकर वहां जाना पड़ा. वहीं नालंदा से शेखपुरा होते हुए पटना ज़िले के मोकामा तक जाने वाला एनएच–82 भी पिछले पांच सालों से निर्माणाधीन है. सीमांचल की हालत इससे ज़्यादा ख़राब है. अररिया, कटिहार और किशनगंज में सिर्फ़ छह से आठ घंटे बिजली मिल रही है.

स्वास्थ्य विभाग तो लगता है अपनी मर्जी से चल रहा है. पूर्णिया के सिविल सर्जन पर तमाम आरोप हैं, पर वह ठाठ से नौकरी कर रहे हैं. किशनगंज एवं अररिया के ज़िला अस्पतालों में सभी ज़रूरी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं. जो उपलब्ध हैं, उन्हें हासिल करने के लिए लोगों को सोलह जतन करने पड़ते हैं. सहरसा इस बरसात में भी टापू बना, क्योंकि पुल एवं सड़कें टूट जाने के कारण वह पटना से केवल रेल मार्ग से ही कई दिनों तक जुड़ा रहा. मुंगेर एवं भागलपुर की बात करें तो बिजली और पानी को लेकर यहां बवाल ज़्यादा है. मांग की तुलना में कम आपूर्ति ने यहां लोगों को परेशान कर रखा है. जनता ने कई बार सड़कों पर उतर कर विरोध जताया. सरकार के लाख दावों के बावजूद यहां पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है. जमालपुर में कई नई सड़कों की हालत ख़राब है. सारण प्रमंडल में नक्सलियों के बढ़ते क़दमों ने नई मुसीबत पैदा कर दी है. सरकार दावा करती है कि सूबा न्याय के साथ विकास कर रहा है. सभी चाहते हैं कि ऐसा हो, पर केवल कहने से काम चलने वाला नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

शिक्षा इंजीनियरिंग कॉलेज: टीचर कम, लैब नहीं, हॉस्टल नदारद

छात्रों को तकनीकी शिक्षा बिहार में ही मिल सके, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2009–10 में चार नए शहरों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए. वर्तमान में छह इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन उनमें बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. सरकार का दावा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं. मुज़फ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा, मोतिहारी, गया एवं दरभंगा में राज्य सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं. सभी को मिलाकर एक सत्र में 1,390 छात्रों का नामांकन विभिन्न संकायों (ट्रेड) में होता है. चार वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगभग पांच हज़ार विद्यार्थी इन इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं. छात्रों की शिकायत है कि न पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं और न लैब. हॉस्टल न होने के कारण छात्रों को कॉलेज आने–जाने में परेशानी होती है. सूत्रों की मानें तो जिस समय कॉलेज खोले गए, उस समय भवन निर्माण भी शुरू नहीं हुआ था. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत चल रहे इन कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छात्रों की हालत अच्छी नहीं है. छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री से मिलकर गुहार लगा चुका है, पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. विभागीय अधिकारी स्वीकार करते हैं कि कॉलेजों में नियमित शिक्षकों की संख्या 60 से भी कम है, लेकिन ठेके पर 300 से अधिक शिक्षकों की बहाली की गई है. विजिटिंग प्रोफेसर भी समय–समय पर बुलाए जाते हैं. पढ़ाई के स्तर को लेकर भी छात्रों को शिकायत है. विभागीय अधिकारी स्वीकार करते हैं कि 15 हज़ार रुपये मानदेय के कारण बेहतर शिक्षकों को खोजने में परेशानी हो रही है. मानदेय 25 हज़ार रुपये करने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है. विजिटिंग प्रोफेसर को 400 रुपये प्रति क्लास दिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 600 रुपये करने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है. विजिटिंग प्रोफेसरों को कॉलेज आने–जाने का किराया देने का भी प्रस्ताव है. उन्हें 25 क्लास लेने की अनुमति रहेगी.

इंजीनियरिंग कॉलेज	सीट
मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	290
भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	200
नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	240
मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	180
गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	240
दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	240

इंजीनियरिंग कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं बहाल करने की कोशिश की जा रही है. आने वाले दिनों में इसका सकारात्मक परिणाम दिखेगा.

अरुण कुमार, प्रधान सचिव, *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग*

साउथ ब्लॉक

सुरेश पांडा अतिरिक्त सचिव बने

1981 बैच के आईएएस अधिकारी सुरेश चंद्र पांडा को गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं एफए बनाया गया है. वह विश्वपति त्रिवेदी की जगह लेंगे, जिन्हें खनिज मंत्रालय में सचिव बनाया गया है.

गजाला संयुक्त सचिव बनीं

1995 बैच की आईए एंड एएस अधिकारी गजाला मीनाई को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. उन्होंने पी पी मित्रा की जगह ली.

अविनाश गृह मंत्रालय में

1991 बैच के आईआरएसआईटी अधिकारी अविनाश मिश्रा को गृह मंत्रालय भेजा गया है. वह इससे पहले चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक थे.

दीप्ति विलास बनेंगे एएस

1981 बैच के आईएएस अधिकारी डेवराकोंडा दीप्ति विलास को जल्द ही अतिरिक्त सचिव बनाया जाएगा. वह अभी गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं. उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय भेजे जाने की उम्मीद है.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 41
दिल्ली, 19 दिसंबर–25 दिसंबर 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)
सी–20, ट्रांस यमुना, एनएच–2, आगरा
फोन : 0526–4064901, 9837082462

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीतावर्डी, नागपुर–440012
फोन नं : 0712–2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा एक और अहम मुद्दा है. केंद्र सरकार मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट (एससी) का दर्जा देने से बच रही है.

टीम अन्ना

अब वालंटियर्स सरकार के निशाने पर हैं

दिल्ली में रोज़ाना लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है, उसके लिए पुलिस किसी के ख़िलाफ़ एफआईआर नहीं दर्ज करती, लेकिन ट्रैफिक जाम का कारण बताकर दिल्ली पुलिस ने अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े वालंटियर्स के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर ली. आख़िर, क्या है इस मजबूरी के पीछे की कहानी?

शशि शेखर

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. अन्ना हजारे ने कहा है कि वह इन पांच राज्यों का दौरा करेंगे और मज़बूत लोकपाल बिल नहीं आया तो कांग्रेस के ख़िलाफ़ प्रचार भी करेंगे. 29 नवंबर से पहले यह ख़बर आ चुकी थी कि स्टैंडिंग कमेटी ने लोकपाल के जिस स्वरूप पर अपनी मुहर लगाई है, वह टीम अन्ना की मांग या कहें कि लोकपाल के कहीं आसपास भी नहीं फटकती. नतीजतन, अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े हज़ारों वालंटियर्स (स्वयंसेवक) जनता के बीच यह संदेश लेकर पहुंचने लगे कि सरकार फिर से लोकपाल के नाम पर धोखा देने जा रही है. 29 नवंबर को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस थाना क्षेत्र में कुछ वालंटियर्स एक मज़बूत लोकपाल बिल के लिए शांतिपूर्ण तरीक़े से जनता को जागरूक करने का काम कर रहे थे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक़, यहां धारा 144 लागू थी और वालंटियर्स सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कर रहे थे. बार-बार चेतावनी देने के बाद भी वे नहीं हटे. नतीजतन, कनाट प्लेस के भीतरी हिस्से में ट्रैफिक जाम हो गया. इसी आधार पर पुलिस ने चार वालंटियर्स के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली.

यह पूरा मामला उतना सीधा भी नहीं है, जितना दिख रहा है. टीम अन्ना के लगभग सारे सदस्यों पर आरोप लग चुके हैं. कई पर केस दर्ज हो चुके हैं. उन्हें बदनाम करने की सरकारी और ग़ैर सरकारी कोशिश की जा चुकी है, सीडी बनाकर, नोटिस भेजकर. बावजूद इसके आंदोलन की धार कुंद होने के बजाय और तेज होती चली गई. आख़िर क्यों? दरअसल, अन्ना हजारे के आंदोलन की रीढ़ हैं उससे जुड़े हज़ारों युवा वालंटियर्स. कोर कमेटी के सदस्य सिर्फ़ रणनीति बनाते हैं, उस रणनीति को सफल बनाने का काम करते हैं ये वालंटियर्स. दिनोंदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है. अगर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर की कॉपी ध्यान से पढ़ी जाए तो बहुत सी बातें समझी जा सकती हैं. उसमें लिखा है कि 100 से 125 लोगों का एक ग्रुप, जिसके नेता अरविंद गौड़ और स्वाति थे. कनॉट प्लेस के इनर सर्किल और सेंट्रल पार्क के पास ये लोग जन लोकपाल के समर्थन में अन्ना हजारे जिंदाबाद और सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे. चेतावनी के बावजूद ये प्रदर्शन करते रहे और पुलिस ने शांति व्यवस्था बरक़रार रखने के लिए बल प्रयोग नहीं किया. एफआईआर में लिखा है कि इस प्रदर्शन में इनके दो नेता सचिन तोमर और नीरज भी दिखे. ग़ौरतलब है कि नीरज ही वह वालंटियर है, जो अन्ना हजारे के आंदोलन के लिए दिल्ली पुलिस और अन्य विभागों से क्लीयरेंस या अनुमति हासिल करने जैसी कार्यवाही से जुड़ा हुआ है. चौथी दुनिया को मिली जानकारी के मुताबिक़, एक तथ्य यह भी है कि जिस वक़्त कनाट प्लेस में वालंटियर्स अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, उस वक़्त नीरज दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के साथ मीटिंग में था.

आज युवा शक्ति राहुल गांधी के बजाय बूढ़े अन्ना हजारे के साथ जाना पसंद कर रही है. जन लोकपाल आंदोलन से जुड़े वालंटियर्स हर राज्य में हैं और अच्छी-खासी संख्या में हैं. कांग्रेस सहित किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह शुभ संकेत नहीं है. चुनाव सिर पर हैं और लोकपाल का मुद्दा इन चुनावों को भी प्रभावित करेगा. ज़ाहिर है, यह स्थिति कांग्रेस के लिए असुविधाजनक है.

यह बिल्कुल बेबुनियाद और इलीगल एफआईआर है. यह वालंटियर्स को तंग करने के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई है. पुलिस ख़ुद क़ानून का उल्लंघन कर रही है. हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए वह नई दिल्ली के इलाक़ों में धारा 144 लगा देती है. क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना अपराध है?

-अरविंद केजरीवाल, सदस्य, टीम अन्ना

हमारे ख़िलाफ़ एफआईआर असल में हज़ारों वालंटियर्स को डराने-धमकाने की एक कोशिश है, ताकि वे इस आंदोलन से अलग हो जाएं और आंदोलन कमज़ोर हो जाए. हमें पता है कि भविष्य में इस एफआईआर का इस्तेमाल हमें परेशान करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं.

-नीरज, वालंटियर्स.

आज युवा शक्ति राहुल गांधी के बजाय बूढ़े अन्ना हजारे के साथ जाना पसंद कर रही है. जन लोकपाल आंदोलन से जुड़े वालंटियर्स हर राज्य में हैं और अच्छी-खासी संख्या में हैं. कांग्रेस सहित किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह शुभ संकेत नहीं है. चुनाव सिर पर हैं और लोकपाल का मुद्दा इन चुनावों को भी प्रभावित करेगा. ज़ाहिर है, यह स्थिति कांग्रेस के लिए असुविधाजनक है. ऐसे में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अन्ना हजारे से जुड़े वालंटियर्स के ख़िलाफ़ केस दर्ज करना एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हो.

shashishekhar@chauthiduniya.com

मुस्लिम आरक्षण और राजनीति

रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट कहां है

उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है, सो मुस्लिम आरक्षण के बहाने राजनीतिक दलों ने अपने-अपने वोट बैंक की जांच-परख शुरू कर दी है. अपना वोट बैंक बढ़ाने और दूसरों का घटाने का खेल भी शुरू हो गया है, लेकिन इस खेल में रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट शामिल नहीं है. आख़िर क्यों?

यह चुनावी चिंता का ही असर था. वरना कोई कारण नहीं था कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को मुस्लिम आरक्षण लागू करने के लिए पत्र लिखतीं और न सलमान खुर्शीद एक बार फिर पिछड़े मुसलमानों को ओबीसी कोटे में से आरक्षण देने जैसे मुद्दे को अपने बयानों से गरमाते. अगर यह कहा जाए कि मुस्लिम आरक्षण के मसले पर बसपा और कांग्रेस दोनों के बयान पूरी तरह चुनावी स्टंट थे तो कोई ग़लत नहीं होगा. लोकसभा के गलियारों में पिछले दो सालों से धूल फांक रही रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट कहां है, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इस मुद्दे पर न बसपा बात कर रही है, न कांग्रेस और न कोई अन्य राजनीतिक दल. रंगनाथ मिश्र आयोग ने अल्पसंख्यकों (बौद्ध और सिख के अलावा) को 15 फ़ीसदी आरक्षण देने की अनुशंसा की थी. केंद्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने कई बार कहा और अब फिर कह रहे हैं कि सरकार ओबीसी कोटे में से ही पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देने पर विचार कर रही है, लेकिन यहां एक पेंच है. पिछड़े मुसलमान पहले से ही ओबीसी कोटे में हैं यानी मंडल आयोग के 27 फ़ीसदी में शामिल हैं. 27 फ़ीसदी में से 3 फ़ीसदी आरक्षण पहले से ही पिछड़े मुसलमानों को मिल रहा है. सरकार लगभग 8.4 फ़ीसदी आरक्षण देने की बात कर रही है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पिछड़े मुसलमानों को ओबीसी कोटे से ही आरक्षण दिया जाएगा तो अन्य धर्मों के जो लोग ओबीसी में आते हैं, क्या वे ऐसा होने देंगे? क्या यहां राजनीति नहीं होगी?

दरअसल, कांग्रेस की नज़र उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं पर है, जिनकी संख्या अच्छी-खासी है. वहां क़रीब 19 फ़ीसदी मुस्लिम वोट हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में वहां 13 मुस्लिम पार्टियां मैदान में उतरी थीं. मुस्लिम मतदाता किसी एक पार्टी को ही अपना वोट देंगे या किस पार्टी के साथ जाएंगे, यह स्पष्ट नहीं है. नतीजतन, सभी राजनीतिक दल मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं. मुलायम सिंह यादव भी आरक्षण की मांग कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं. साथ ही वह कांग्रेस की पहल को दिखावा बता रहे हैं. सरकार मुसलमानों को आरक्षण देने के मसले को अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए एक अवसर के तौर पर देख रही है, लेकिन कांग्रेस के इस फ़ैसले का विरोध होगा. भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बनाकर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी और उसे उन सभी पार्टियों का समर्थन मिलेगा, जो ओबीसी वर्ग से आती हैं या उस वर्ग के समर्थन के सहारे ही जिनकी राजनीतिक दुकान चलती है.

मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा एक और अहम मुद्दा है. केंद्र सरकार मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट (एससी) का दर्जा देने से बच रही है. जबकि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट साफ-साफ बताती है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर देश के मुसलमानों की हालत दयनीय है. रंगनाथ मिश्र आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों में से ज़्यादातर लोगों की हालत हिंदू दलितों से भी बदतर है. आयोग ने संविधान से पैरा 3 हटाने की भी सिफारिश की है. दरअसल, संविधान के पैरा 3 में राष्ट्रपति के आदेश 1950 का उल्लेख है, जिसके मुताबिक़ हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है. बाद में बौद्धों और सिक्खों को भी एससी का दर्जा दिया गया, लेकिन मुस्लिम, ईसाई, जैन और पारसी धर्म के लोगों को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा नहीं मिल सकता. एससी का दर्जा मिलते ही पिछड़े मुसलमानों को अपने आप विधानसभाओं और संसद में भी आरक्षण मिल जाएगा. इसलिए उनकी मुख्य मांग है कि 1950 का प्रेसिडेंसियल ऑर्डर वापस लिया जाए.

मुस्लिम आरक्षण का मसला केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुका है. रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों के मुताबिक़, 15 फ़ीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, क्योंकि 50 फ़ीसदी आरक्षण की सीमा पार करना पड़ेगा. दूसरी ओर ओबीसी कोटे में से आरक्षण देने की बात न तो कई राजनीतिक दल मानेंगे और न इस देश की सबसे बड़ी आबादी यानी ओबीसी. सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम पेंचों के बाद भी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विकास की चिंता किसे है? ऐसा नहीं है कि रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट में सिर्फ़ मुस्लिमों सहित अन्य अल्पसंख्यक समुदायों (बौद्ध एवं सिक्ख) के पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की वकालत की गई है, बल्कि आयोग ने अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए कई अन्य रास्ते भी बताए हैं. मसलन, उनके लिए ऋण, व्यापार एवं शिक्षा आदि की समुचित व्यवस्था कैसे की जा सकती है, इस संदर्भ में विशेष उपाय भी इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, लेकिन इस सबकी चिंता किसी को नहीं है, सिवाय मुस्लिम आरक्षण के नाम पर राजनीति करने के. सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे की गंभीरता और इसके क्रियान्वयन के रास्ते में आने वाली समस्याओं का अंदाजा है. फिर भी असल मुद्दे अल्पसंख्यकों के विकास से उनका कोई लेना-देना नहीं है.

चौथी दुनिया और रंगनाथ रिपोर्ट

वर्षों से सरकार के पास पड़ी रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को जब चौथी दुनिया ने प्रकाशित किया, तब 2009 के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हंगामे के बाद सरकार ने वह रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी, वह भी बिना एटीआर के. उसके बाद दो साल बीतने को हैं, लेकिन अभी तक न उस रिपोर्ट पर कोई चर्चा हुई और न केंद्र सरकार ने रिपोर्ट की सिफारिशें लागू कराने की कोशिश की. इस बीच चौथी दुनिया ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार बहाने बनाकर उन सवालों के जवाब देने से बच रही है, जो पिछले कई सालों में देश की सर्वोच्च अदालत ने पूछे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से अंतिम जवाब दाख़िल करने को कहा था. याचिका संख्या 180/2004 में याचिकाकर्ता ने यह दलील दी है कि पैरा 3 में वर्णित राष्ट्रपति के आदेश 1950 की वजह से मुसलमानों, ईसाइयों, जैनियों और पारसियों के साथ भेदभाव हो रहा है.

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

पुराने कामों को नया दिखाकर करोड़ों रुपये की हेराफेरी कर ली गई. कुएं बनवाने के लिए अग्रिम राशि की निकासी तो बैंक से हो गई, किंतु पूरा धन लाभार्थियों को न देकर उसकी बंदरबांट कर ली गई.

उत्तर प्रदेश

मायावती के मुक़ाबले उमा भारती

फोटो– प्रभात पाण्डेय

अजय कुमार

भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस और बसपा की तरह अपनी महिला नेत्री उमा भारती को आगे कर दिया है. तमाम दिग्गजों को पछाड़ते हुए उमा भाजपा की नई खेवनहार बन गईं, मगर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष एवं प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती से मुक़ाबला करना आसान नहीं है, क्योंकि उमा भारती जहां संप्रदाय विशेष की राजनीति करने में विश्वास करती हैं, वहीं मायावती सभी वर्गों को साथ लेकर चलती हैं. एक समय था, जब भाजपा ने राम जन्मभूमि मुद्दे के ज़रिये लोगों की भावनाओं को भड़का कर समर्थन हासिल किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. आज के मतदाता इस तरह के चुनावी हथकंडों को समझ चुके हैं और वे बुनियादी मुद्दों एवं विकास को प्राथमिकता देने लगे हैं. जिस तरह मायावती ने प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने की चाल चली है, उसके मुक़ाबले कोई लोक लुभावन मुद्दा उठाना भाजपा के लिए आसान नहीं है. हालांकि भाजपा आलाकमान ने उमा भारती को चुनाव की ज़िम्मेदारी सौंप कर अपना तुरुप का पत्ता चल दिया है. संभावना है कि उमा भारती किसी विधानसभा क्षेत्र से क़िस्मत आज़माती नज़र आ सकती हैं, ताकि विरोधियों के मुंह से यह न निकल पाए कि वह बाहरी हैं. भाजपा की फायर ब्रांड नेता अपनी स्थिति स्पष्ट होते ही शब्दों के बाण छोड़ने लगी हैं. मायावती ने जब कहा कि प्रदेश को दलित मुख्यमंत्री चाहिए तो उमा ने साफ़ किया कि दलित मुख्यमंत्री तो चाहिए, लेकिन लुटेरा मुख्यमंत्री नहीं. आगे भी मायावती के ख़िलाफ़ ऐसे आक्रमण भाजपा की तरफ़ से होते रहेंगे, लेकिन मायावती भी चुप बैठने वाली नहीं हैं. मायावती की यह विशेषता है कि वह किसी भी जांच के दायरे में आने पर अपने मंत्री या पार्टी पदाधिकारी को बख्शती नहीं हैं, जिससे विरोधी उन पर आरोप लगा सकें, जबकि भाजपा अपने लोगों का उस समय तक बचाव करती है, जब तक उनका सारा कच्चा चिट्ठा सामने न आ जाए. एक तरफ़ उमा भाजपा को मुख्य मुक़ाबले में लाने के लिए बसपा प्रमुख पर हमला बोलेंगी, वहीं दूसरी तरफ़ वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिलीभगत को उजागर करने में भी पीछे नहीं रहेंगी. इसके साथ उन्हें जनता को यह भी विश्वास दिलाना होगा कि किसी भी दशा में भाजपा बसपा या सपा से सत्ता के लिए हाथ नहीं मिलाएगी. उमा पर विश्वास जताने के साथ ही आलाकमान ने उन पर कई ज़िम्मेदारियां डाल दी हैं. उमा को भाजपा लाओ और प्रदेश बचाओ की ज़िम्मेदारी पिछले दिनों अयोध्या में हुए एक समारोह के दौरान सौंपी गई थी, जबकि जल यात्रा पर निकलने का दायित्व उन्हें कुशीनगर की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सौंपा गया. इसके अलावा मायावती सरकार के काले कारनामों का पर्दाफ़ाश करने की कमान भी उन्हें दी गई है. भाजपा उमा के सहारे जनता को ख़ुद से जोड़ना चाहती है.

उमा को पावरफुल लेडी बनाने के लिए आतुर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता है कि उनके मार्ग में कोई व्यवधान आए. इसलिए उसने उनकी राह में आने वाले रोड़े भी किनारे करने की योजना बना ली है. उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे कुछ भाजपा नेता अक्सर कहा करते थे, सूबे के बाहर का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं हो सकता. इस बात की काट के लिए भाजपा ने उमा के लिए तीन सीटों चरखारी (महोबा, बबीना (झांसी) और बिठूर (कानपुर) का चयन भी कर लिया है. इनमें से किसी एक पर वह अपनी क़िस्मत आज़मा सकती हैं. वैसे कुछ लोग उन्हें लखनऊ से भी चुनाव लड़ाने की वकालत कर रहे हैं. पहले उमा चुनाव न लड़ने की बात कहती थीं, लेकिन अब कहने लगी हैं कि आलाकमान जैसा चाहेगा, वैसा होगा. उमा के मैदान में उतरने से भाजपा के लिए अति पिछड़ा और अति दलित कार्ड खेलना आसान हो जाएगा, वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं का भी भाजपा की तरफ़ झुकाव बढ़ेगा. सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा, वह हिंदुत्व का एजेंडा होगा, जो उमा के चलते अपने आप आगे बढ़ जाएगा. उमा न तो अयोध्या पर ज़्यादा फोकस करेंगी, न हिंदुत्व पर मुखर होकर बोलेंगी, लेकिन उनका चेहरा और वेशभूषा देखते ही अयोध्या और हिंदुत्व का मुद्दा मतदाताओं के दिलोदिमाग़ पर छा जाएगा. भाजपा यही चाहती है. उमा बिना किसी रोक-टोक काम करें, इसके लिए ख़ुद को प्रदेश भाजपा का कर्णधार समझने वाले कुछ नेताओं को उनसे दूर कर दिया गया है. उमा के साथ काम करने वालों की जो टीम बनी है, उसमें कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है.

भाजपा आलाकमान ने उमा भारती को चुनाव की ज़िम्मेदारी सौंप कर अपना तुरुप का पत्ता चल दिया है. संभावना है कि उमा भारती किसी विधानसभा क्षेत्र से क़िस्मत आज़माती नज़र आ सकती हैं, ताकि विरोधियों के मुंह से यह न निकल पाए कि वह बाहरी हैं. भाजपा की फायर ब्रांड नेता अपनी स्थिति स्पष्ट होते ही शब्दों के बाण छोड़ने लगी हैं. मायावती ने जब कहा कि प्रदेश को दलित मुख्यमंत्री चाहिए तो उमा ने साफ़ किया कि दलित मुख्यमंत्री तो चाहिए, लेकिन लुटेरा मुख्यमंत्री नहीं.

बीते एक दिसंबर को सहारनपुर के बेहट क्षेत्र से प्रदेश बचाओ-भाजपा लाओ अभियान से इसकी शुरुआत हो चुकी है. बसपा का गढ़ बने सहारनपुर ज़िले से अभियान की शुरुआत करके उमा ने उड़ान भर ली है. राजनाथ सिंह एवं कलराज मिश्र की यात्राओं के बाद चुनावी रण को बसपा बनाम भाजपा में तब्दील करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपनी पूरी ताक़त लगा दी है. किसी से छिपा नहीं है कि उमा भारती को उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में उतारना संघ की रणनीति का ही हिस्सा है. क़रीब छह माह पूर्व भाजपा की सदस्यता दोबारा लेने और उत्तर प्रदेश में पूरा समय देने के बाद भी साध्वी उमा की भूमिका पर उत्तर प्रदेश को लेकर असमंजस की स्थिति बनी थी, लेकिन नवंबर के मध्य में अयोध्या के विजय संकल्प समागम में अध्यक्ष नितिन गडकरी ने अपनी मंशा ज़ाहिर कर दी थी. भाजपा नेतृत्व ने उमा भारती को पूरी छूट दे रखी है. इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उमा की मर्ज़ी देखकर अयोध्या में घोषित किए गए समन्वयक को बदल दिया गया. साध्वी के साथ जुड़ने वाली टीम में उनके क़रीबी कई ऐसे चेहरे हैं, जो लंबे अंतराल के बाद पार्टी की मुख्य धारा में दिखेंगे. इनमें मनोज सिन्हा, बृजभूषण कुशवाहा, वीरेंद्र सिंह, जितेंद्र कश्यप, विद्या सागर सोनकर, अनिल जैन, अमर सिंह, विपिन वर्मा डेविड एवं अनिता सिंह आदि प्रमुख हैं.

feedback@chauthiduniya.com

सरकारी धन की बंदरबांट

मनरेगा

नक्सलवाद, भौगोलिक स्थिति और पिछड़ापन आदि वे कारण हैं, जो विंध्याचल मंडल को प्रदेश के विकसित हिस्सों से अलग करते हैं. मंडल के तीन ज़िलों में से एक भदोही को विकसित कहा जा सकता है, किंतु कालीन उद्योग में आई मंदी ने जनपद की अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया. मिर्जापुर पिछड़ा होने के साथ-साथ भ्रष्टाचारियों के लिए चारागाह बन गया है. मनरेगा योजना से जनपद का चेहरा चमक सकता था, किंतु तंत्र की गिरोह संस्कृति ने आम लोगों को निराश कर दिया. मनरेगा के अंतर्गत हो रहे भ्रष्टाचार की एक उच्चस्तरीय जांच हलिया विकास खंड में राज्य गुणवत्ता नियंत्रक विनोद शंकर चौबे की देखरेख में कराई गई. जांच में सामने आए तथ्य चौंकाने वाले हैं. जांच में पाया गया कि ब्लॉक प्रमुख की चौकड़ी ने सरकारी धन की लूट की सारी सीमाएं लांघ दी. पुराने कामों को नया दिखाकर करोड़ों रुपये की हेराफेरी कर ली गई. कुएं बनवाने के लिए अग्रिम राशि की निकासी तो बैंक से हो गई, किंतु पूरा धन लाभार्थियों को न देकर उसकी बंदरबांट कर ली गई. नतीजा यह कि कुएं आज तक नहीं खोदे जा सके. जांच में यह भी पाया गया कि जहां प्राक्कलन से अधिक ख़र्च करने के बावजूद कई काम अधूरे हैं, वही सीमेंट सहित कई सामग्रियों की मनमानी दरें लगाई गईं. सरकारी रायल्टी और आयकर आदि की भी चोरी हुई. समिति के सदस्य अपर ज़िलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) भी रहे, किंतु अभी तक दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई. जांच के दौरान पता चला कि विकास खंड हलिया के प्रमुख, कर्मचारियों एवं दलालों ने साठगांठ करके मनरेगा के धन का दुरुपयोग किया. चहेतों को इतने अधिक कार्यों का प्रभारी बना दिया गया कि वे कार्यस्थलों पर जाने लायक़ नहीं रहे. उनका काम मात्र यही था कि वे बैंक से पैसा निकाल कर उसकी बंदरबांट करते रहे और काग़ज़ रंगते रहे. जो कर्मचारी इस गोलमाल में शामिल नहीं हुए, उन्हें उपेक्षा-अपमान का सामना करना पड़ा, मामला पुलिस तक जा पहुंचा और मंडलस्तरीय हड़ताल हो गई. हलिया विकास खंड के एक खंड विकास अधिकारी ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया कि बिना उसकी सहमति, बग़ैर कोई औपचारिकता पूरी किए कई लाख के चेक काट लिए गए और तत्कालीन प्रमुख द्वारा उन पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया गया. यह भी जांच का विषय है कि उन चेकों का क्या हुआ, जो मनरेगा के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके काटे गए थे. हालत का बदतरपन यह कि तत्कालीन खंड विकास अधिकारी आशा राम को स्थानांतरण की पीड़ा झेलनी पड़ी और दोषियों का बाल भी बांका नहीं हुआ. सबसे पिछड़ा विकास खंड होने के कारण हलिया को विकसित करने के नाम पर पैसा पाने के लिए पूरा तंत्र एड़ी-चोटी का जोर एक कर देता है, घड़ियाली आंसू बहाता है, चौपालें लगाता है, किंतु उन लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं होता, जो विकास के नाम पर सरकारी बजट हड़प रहे हैं. राज्य गुणवत्ता नियंत्रक ने दोषियों की पहचान करके उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई और शासन को विभागीय कार्यवाही के लिए भी लिखा. इस संदर्भ में आयुक्त ग्राम्य विकास ने मुख्य विकास अधिकारी मिर्जापुर को कार्यवाही के निर्देश दिए, लेकिन मामले की लीपापोती की नीयत से आज तक दोषियों के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की गई. इसी जांच आख्या को आधार बनाकर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी चल रही है. विकास खंड हलिया के घोटाले चर्चा में तब आए, जब इस उच्चस्तरीय समिति ने दौरा किया. अभी और भी कई घोटाले हैं, जो प्रकाश में नहीं आए हैं. यदि सघन जांच कराई जाए तो शायद ही कोई अधिकारी-कर्मचारी दंडित होने से बच पाएगा. जिन्होंने भी घोटालों में शामिल होने से मना किया, उनकी नौकरी ख़तरे में पड़ गई. पहाड़ी विकास खंड में बतौर तकनीकी सहायक तैनात अखिलेश मिश्र ने एक दबंग प्रधान पति के कहने पर फ़र्ज़ी भुगतान करने से मना कर दिया और उच्चाधिकारियों को इससे अवगत करा दिया. नतीजा यह हुआ कि अखिलेश को नौकरी से वंचित कर दिया गया और उक्त फ़र्ज़ी भुगतान भी हो गया.

मनरेगा में कामगारों की एक निश्चित संख्या के बाद एक अतिरिक्त कर्मचारी पूरे समूह को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए होता है, जिसे मजदूरी नहीं करनी पड़ती. कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए टेंट और उनके बच्चों के लिए खिलौने उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान है. इसी के तहत पटेहरा विकास खंड के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी ने खिलौनों की मद में एक मोटी धनराशि की कथित ख़रीदारी उस फर्म से कर ली, जो खिलौने बेचती ही नहीं. विकास खंड कोन में मनरेगा के अंतर्गत करोड़ों रुपये की मेड़बंदी की योजनाएं स्वीकृत की गईं. कुछ पर शिकायतें हुईं, जांच हुई, शिकायतें सही पाई गईं, लेकिन जांच अधिकारियों ने मामला रफा-दफा कर दिया. अधिकतर उन्हीं गांवों में काग़ज़ी मेड़बंदी कराई गई, जो गंगा नदी के निकट हैं.

सबसे गंभीर मामला छानबे विकास खंड का है, जहां करोड़ों रुपये के वारे-न्यारे हो गए और जांच तक नहीं हुई. अकोढ़ी-बबुरा संपर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन है. विभाग ने इस पर तारकोल स्तर का काम करा रखा है. इस सड़क पर निर्माण कार्य के लिए लगभग 35 लाख रुपये का ख़र्च विकास खंड द्वारा दिखाया गया. तत्कालीन आयुक्त सत्यजीत ठाकुर के निर्देश पर जब एक उच्चस्तरीय समिति ने जांच की तो उसने पाया कि बिना कोई व्यय किए ही विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों ने पूरा पैसा हजम कर लिया. जांच के बाद विभागीय कार्यवाही और गबन किए गए धन की वसूली के आदेश दिए गए, किंतु पूरी फाइल दबा दी गई. चूंकि मनरेगा में धन का आवंटन मांग आधारित है, इसलिए अधिक से अधिक काग़ज़ी व्यय दिखाकर धन हासिल करने के हथकंडे अपनाए जाते हैं. मनरेगा के अंतर्गत सभी जानकारी वेबसाइट पर रखी जाती है, इसलिए एक ही कार्य का मस्टर रोल कई गांवों में दिखा दिया जाता है, जिससे व्यय धनराशि बढ़ जाती है और अगला आवंटन आसानी से हो जाता है. ऐसे कई प्रकरण संज्ञान में लेकर मंडलायुक्त विंध्याचल ने एक वरिष्ठ अधिकारी को उनकी जांच सौंपी हैं, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है.

अमरेश मिश्र
feedback@chauthiduniya.com

सिद्धांतों का ढोल पीटने वाली भाजपा ने भी अवैध खनन को काफ़ी बढ़ावा दिया. भाजपा शासित प्रदेश उत्तराखंड में गंगा में अवैध खनन जारी है.

अवैध खनन

सरकार एजेंट की भूमिका निभा रही है

फ़िरदौस ख़ान

देश में अवैध खनन का कारोबार बदस्तूर जारी है. राजनेताओं के संरक्षण और अफ़सरों की मिलीभगत से खनन माफ़िया देश के खनिज बहुल राज्यों में प्राकृतिक खनिजों को लूटने में जुटे हैं. अफ़सोस की बात तो यह है कि लोकतांत्रिक देश की सरकार और जनप्रतिनिधि जनहित को ताक़ पर रखकर पूंजीपतियों के एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं. कर्नाटक के लोकायुक्त एन संतोष हेगड़े की अवैध खनन मामले में आई रिपोर्ट भी इस अवैध कारोबार में सरकार और जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता को साबित करती है. अवैध खनन के कारोबार में कांग्रेस और भाजपा नेताओं का गठजोड़ रहा है. संतोष हेगड़े की रिपोर्ट में भाजपाई मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और रेड्डी बंधुओं के साथ ही पिछले दस साल में कर्नाटक की कांग्रेस, जनतादल सेक्युलर और भाजपा की सभी सरकारों को दोषी क़रार दिया गया है. हालांकि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विदेश मंत्री एस एम कृष्णा का कहना है कि उनके कार्यकाल में खनन का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया. लोकायुक्त कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एन के सुधींद्र राव द्वारा अवैध खनन मामले में उनकी जांच के आदेश दिए जाने के बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने खान एवं भूगर्भ विभाग अपने पास कभी नहीं रखा.

बंगलुरु के व्यापारी टी जे अब्राहम ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि एस एम कृष्णा, धर्म सिंह और एच डी कुमारस्वामी के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रदेश में अवैध खनन हुआ, जिसे उन्होंने नहीं रोका. याचिका में 11 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है. एस एम कृष्णा 11 अक्टूबर, 1999 से 28 मई, 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे. इसके बाद कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर गठबंधन की सरकार में एन धर्म सिंह 28 मई, 2004 से 28 जनवरी, 2006 तक मुख्यमंत्री रहे. जबकि इसके बाद बनी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर गठजोड़ की सरकार में एच डी कुमारस्वामी 2 फरवरी, 2006 से 8 अक्टूबर, 2007 तक मुख्यमंत्री रहे. एन धर्म सिंह इस समय उत्तरी कर्नाटक के बिदर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सांसद हैं, जबकि कुमारस्वामी बंगलुरु के समीप रामनगरम से सांसद हैं. रिपोर्ट में मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और कई अन्य मंत्रियों को दोषी ठहराया गया, जिनमें पूर्व मंत्री कट्टा सुब्रमन्या नायडू, एस एन शेट्टी और मौजूदा गृह मंत्री आर अशोका, उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी एवं गृह निर्माण मंत्री वी सोमाना शामिल हैं. इससे जहां भाजपा की ख़ासी किरकिरी हुई, वहीं येदियुरप्पा को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी. कर्नाटक में लोकायुक्त की जांच के घेरे में आने वाले सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं की तादाद बढ़ती ही जा रही है. विधानसभा अध्यक्ष के जी बोपैया के ख़िलाफ़ भी धन का दुरुपयोग करने के मामले में जांच शुरू हो चुकी है. हाल में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने आंध्र प्रदेश की भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी वाई श्रीलक्ष्मी को जेल भेज दिया. उन पर आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी की सरकार के कार्यकाल में खनन विभाग की सचिव रहते हुए रेड्डी बंधुओं की ओबुलापुरम कंपनी को लाइसेंस देने में पक्षपात करने का आरोप है. खनन माफ़िया, अफ़सरों और नेताओं का गठजोड़ चांदी कूटने के साथ ही सरकारी ख़ज़ाने को अरबों का चूना भी लगा रहा है. कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त संतोष हेगड़े की रिपोर्ट के मुताबिक़, 2006–2010 के बीच राज्य से क़रीब तीन करोड़ टन अवैध लौह अयस्क का खनन किया गया. इससे देश को क़रीब 16,200 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ. वहीं गोवा में 12,000 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ है. पिछले पांच वर्षों में राज्य में 1.42 करोड़ टन अवैध खनन हुआ. राज्य का खनन विभाग मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के पास है. यहां से सालाना 5.4 करोड़ टन लौह अयस्क का निर्यात होता है.

पिछले दिनों भाजपा ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को एक ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री कामत, गोवा कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर और सरकार के मंत्रियों के इसमें शामिल होने का आरोप लगाया. भाजपा ने राज्य में 25 हज़ार करोड़ रुपये के अवैध खनन का आरोप लगाते हुए इसे बेल्लारी से भी बड़ा घोटाला क़रार दिया है. कांग्रेस सांसद शांताराम नाईक का कहना है कि केंद्रीय खान मंत्रालय ने गोवा में खनन उद्योगों की जांच का आदेश दे दिया है. उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर न्यायमूर्ति एम बी शाह आयोग की रिपोर्ट लीक करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. पिछले दिनों लीक हुई इस रिपोर्ट में राज्य में बड़े खनन घोटाले का ज़िक्र किया गया था. उड़ीसा में देश का लगभग एक तिहाई लौह अयस्क भंडार है. यहां की 243 खदानों में वर्ष 2009 से खनन बंद है. अकेले उड़ीसा में अवैध खनन से सरकारी ख़ज़ाने को तीन लाख करोड़ रुपये का नुक़सान हो चुका है. सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक़, अवैध खनन के कारण पिछले पांच वर्षों में मध्य प्रदेश में क़रीब 1500 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ है. वन विभाग के अधिकारियों ने अपनी एक रिपोर्ट में अवैध खनन के मामले में राज्य के खनन मंत्री राजेंद्र शुक्ल और लोक निर्माण मंत्री नागेंद्र सिंह को ज़िम्मेदार ठहराया है, जबकि दोनों ही मंत्रियों ने इन आरोपों को ग़लत बताया है. छत्तीसगढ़ में 700 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ है. एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक़, झारखंड में अवैध खनन से सरकार को सालाना 600 करोड़ रुपये का नुक़सान होता है. यहां के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर भी अवैध खनन में शामिल होने के आरोप लगे हैं. राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में सरकार को 150 करोड़ रुपये के राजस्व का नुक़सान हुआ है.

अवैध खनन रोकने की सरकारी क़वायद

अवैध खनन रोकने की क़वायद का दावा करते हुए इसी साल सितंबर माह में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनन एवं खनिज (विकास एवं नियमन) विधेयक 2011 को मंज़ूरी दी है. इसमें प्रावधान है कि कोयला खनन कंपनियों को हर साल अपने शुद्ध लाभ का 26 फ़ीसदी और अन्य खनिज कंपनियों को रॉयल्टी के बराबर धनराशि ज़िलास्तरीय खनिज न्यास को देनी होगी. इस रक़म का इस्तेमाल स्थानीय लोगों के विकास के लिए किया जाएगा. केंद्रीय खान मंत्री दिनशा पटेल का कहना है कि खनन से पहले प्रभावित होने वाले लोगों से बात करना अनिवार्य होगा. अवैध खनन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए राज्य स्तर पर विशेष अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है. देश के 60 ऐसे ज़िलों में राष्ट्रीय खनन नियामक प्राधिकरण और राष्ट्रीय खनिज ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, जहां खनिज संसाधन काफ़ी प्रचुर मात्रा में हैं. इस विधेयक के आने से सरकार को मिलने वाली रॉयल्टी 4500 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,500 करोड़ रुपये हो जाएगी. विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि खनन कंपनियों को राज्य सरकार को कुल रॉयल्टी पर 10 फ़ीसदी और केंद्र सरकार को 2.5 फ़ीसदी का उपकर जमा करना होगा. सरकार का दावा है कि इस विधेयक में अवैध खनन रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं. आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखकर ही इसे तैयार किया गया. इसके तहत कोयला कंपनियों के शुद्ध लाभ का 26 फ़ीसदी हिस्सा प्रभावित लोगों के विकास के लिए ख़र्च किया जाएगा. यह विधेयक खनन एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1957 की जगह लेगा.

खनन मंत्रालय की एक रिपोर्ट में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि देश में अवैध खनन का कारोबार फल–फूल रहा है. इस रिपोर्ट के मुताबिक़, 2006 से 2010 तक देश भर में अवैध खनन के एक लाख 61 हज़ार 140 मामले सामने आए. इनमें सर्वाधिक 39670 मामले अकेले आंध्र प्रदेश के थे. इसके बाद गुजरात में 24936 मामले दर्ज किए गए. महाराष्ट्र में 22885, मध्य प्रदेश में 17397, कर्नाटक में 12191, राजस्थान में 11513, केरल में 8204, छत्तीसगढ़ में 7402, तमिलनाडु में 5191, हरियाणा में 3897, हिमाचल प्रदेश में 2095, गोवा में 492, झारखंड में 953 और पश्चिम बंगाल में 901 मामले सामने आए. अफ़सोस की बात यह है कि कई राज्यों में तो अवैध खनन के मामलों में प्राथमिकी तक दर्ज नहीं हुई है. देश भर में सिर्फ़ 44 हज़ार 445 मामलों में ही कार्रवाई हुई. आंध्र प्रदेश में कोई भी मामला अदालत तक नहीं पहुंच पाया, जबकि छत्तीसगढ़ में 2383, गुजरात में आठ, हरियाणा में 138, हिमाचल प्रदेश में 711, झारखंड में 39, कर्नाटक में 771, मध्य प्रदेश में 16157, महाराष्ट्र में 13, उड़ीसा में 86, राजस्थान में 59, तमिलनाडु में 421 और बंगाल में 91 मामले अदालत में गए. गुजरात में 158 मामले पुलिस में दर्ज किए गए, जबकि हरियाणा में 103, झारखंड में 205, कर्नाटक में 959, मध्य प्रदेश में पांच, महाराष्ट्र में 20197, उड़ीसा में 57, राजस्थान में 607, तमिलनाडु में 579 और पश्चिम बंगाल में 974 मामले पुलिस तक पहुंचे.

देश के विभिन्न राज्यों में कोयला, एल्यूमिनियम, अभ्रक, तांबा और मैगनीज आदि क़ीमती खनिजों का भंडार है. सुप्रीमकोर्ट की सख़्त हिदायतों के बावजूद अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है. अवैध खनन के कारण पर्यावरण को ख़तरा पैदा हो गया है. पश्चिम बंगाल के रानीगंज, आसनसोल और झारखंड के झरिया का उदाहरण सबके सामने है. अवैध खनन के कारण यहां का एक बड़ा क्षेत्र कभी भी भयानक रूप ले सकता है, क्योंकि यहां ज़मीन के भीतर आग दहक रही है. यहां ज़मीन में पड़ी दरारों से आग की लपटें निकलती हैं. यहां का क़ीमती कोयला हर पल राख के ढेर में बदल रहा है. काग़ज़ों में तो यहां की कई खदानें बंद पड़ी हैं, लेकिन कोयला माफ़ियाओं के लिए यहां आज भी काम बदस्तूर जारी है. अवैध खनन के कारण जहां मज़दूरों की जान ख़तरे में रहती है, वहीं अत्यधिक खनन से खनिजों के भंडार भी ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं, मगर राजनीतिज्ञों के संरक्षण के कारण यह धंधा बिना रोक–टोक के चल रहा है. इस धंधे ने लोगों को सड़क से उठाकर मंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया है. जनार्दन रेड्डी को ही लीजिए. सामान्य हेड कांस्टेबल चेंगा रेड्डी के घर में पैदा हुए जनार्दन रेड्डी ने 1995 में बेल्लारी में चिटफंड कंपनी खोली, लेकिन तीन साल बाद ही ख़ुद को दिवालिया घोषित करके उसे बंद कर दिया. इसके बाद उन्होंने होटल और मीडिया बिजनेस शुरू किया, वहां भी उन्हें घाटा उठाना पड़ा, लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव के वक़्त उनके दिन बदल गए. सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज के बीच चुनावी मुक़ाबले में उन्होंने सुषमा स्वराज के लिए काम किया. सुषमा स्वराज को भले ही हार का मुंह देखना पड़ा हो, लेकिन रेड्डी बंधुओं का भला हो गया. सियासत में आते ही उन्होंने खनन उद्योग में क़दम रखा और अवैध खनन के चलते वे दौलतमंद होते चले गए. जनार्दन रेड्डी और उनके साले श्रीनिवास रेड्डी ने राजनीतिज्ञों से संबंधों के कारण कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पैर जमा लिए. हालत यह हो गई कि उन्होंने बेल्लारी की लोहे की खानों को ख़ाली कर डाला. कर्नाटक में अवैध खनन पर जारी लोकायुक्त की रिपोर्ट के मुताबिक़, 2009–10 में ही रेड्डी बंधुओं ने 4635 करोड़ रुपये का अवैध खनन किया. रेड्डी बंधु भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और जी जनार्दन रेड्डी के अलावा उनके भाई जी करुणाकर रेड्डी कर्नाटक की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे. आंध्र प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी का भी उन्हें संरक्षण हासिल था. यह रेड्डी बंधुओं का प्रभाव ही था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2009 में आंध्र प्रदेश की तत्कालीन के रोसैया सरकार द्वारा अनंतपुर ज़िले में अवैध खनन और धांधली के आरोप में रेड्डी बंधुओं की ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराने के बावजूद सीबीआई ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में देर की. इसमें कोई दो राय नहीं कि सर्वदलीय सहमति और केंद्रीय खनन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय खनन ब्यूरो और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत के बग़ैर इतना बड़ा अवैध खनन का कारोबार चल ही नहीं सकता. केंद्र सरकार की नीतियों ने भी अवैध खनन को बढ़ावा देने का काम किया. 1993 में केंद्र की नरसिम्हाराव सरकार ने खनन को निजी और विदेशी पूंजी के हवाला कर दिया. नतीजतन, पोस्को से लेकर वेदांता जैसी कंपनियां भी क़ीमती खनिजों की लूट में शामिल हो गईं.

सिद्धांतों का ढोल पीटने वाली भाजपा ने भी अवैध खनन को काफ़ी बढ़ावा दिया. भाजपा शासित प्रदेश उत्तराखंड में गंगा में अवैध खनन जारी है. इसके ख़िलाफ़ आमरण अनशन पर बैठे स्वामी निगमानंद की कथित हत्या के बाद भी सरकार खनन पर रोक नहीं लगा पाई. स्वामी निगमानंद के गुरु शिवानंद का आरोप है कि खनन माफ़िया पार्टी फंड के लिए चंदे के रूप में एक मोटी रक़म देता है, इसलिए भाजपा सरकार ने उसे खनन की खुली छूट दे रखी है. अवैध खनन से जहां सरकारी ख़ज़ाने को नुक़सान होता है, वहीं इससे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश पर भी विपरीत असर पड़ता है. आदिवासियों से उनकी पैतृक ज़मीन छीनी जा रही है. आदिवासियों को अपनी पुश्तैनी जगह छोड़कर दूरदराज के इलाक़ों में पलायन करना पड़ रहा है. इससे उनके सामने रोज़गार का संकट पैदा हो गया है, उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनके रीति–रिवाज भी ख़त्म होते जा रहे हैं. विकास के लिए खनन ज़रूरी है, लेकिन सुधार के नाम पर किए जा रहे अति खनन यानी अवैध खनन के दूरगामी नतीजे अच्छे नहीं होंगे. सरकार को चाहिए कि वह जनहित के मद्देनज़र अवैध खनन पर रोक लगाए, वरना वह दिन दूर नहीं, जब खानों से खनिजों के भंडार समय से पहले ख़त्म हो जाएंगे.

firdaus@chauthiduniya.com

प्रधानमंत्री ने अपनी इस यात्रा के दौरान आश्वासन तो ख़ूब दिए, लेकिन यहां के सबसे ज्वलंत मुद्दे अफसपा के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा और न पिछले 11 सालों से इस मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल कर रहीं शर्मिला के बारे में कोई बात कही.

दिल्ली, 19 दिसंबर–25 दिसंबर 2011 चौथी दुनिया

प्रधानमंत्री का मणिपुर दौरा

जनता के ज़ख्मों पर विकास का मरहम

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

एस. बिजेन सिंह

बीते एक अगस्त से मणिपुर के दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच–39 एवं 53) पर यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) ने आर्थिक नाकेबंदी कर रखी थी. इस 100 दिनों की बंदी ने यहां के जनजीवन को अस्त–व्यस्त कर किया. हर वस्तु के दाम आसमान छूने लगे. पेट्रोल 250 रुपये प्रति लीटर मिलने लगा और रसोई गैस का सिलेंडर 2100 रुपये में. आसमान छूती क़ीमतें एक तरफ़, रसोई गैस के लाले तक पड़ गए. पेट्रोल के लिए लोगों को तीन–चार किलोमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ी. रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों, जीवनरक्षक दवाओं और ऑक्सीजन आदि का अभाव हो गया. इन सबके बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते 3 दिसंबर को मणिपुर का एक दिवसीय दौरा किया. प्रधानमंत्री का यह तीसरा दौरा था. इस बार उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई अन्य योजनाओं की घोषणा की. आईएसबीटी, एमएफडीसी ऑडिटोरियम, सिटी कन्वेंशन सेंटर, एसेंबली कांप्लेक्स एवं हाईकोर्ट भवन के उद्घाटन के साथ कई घोषणाएं की गईं. मणिपुर में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं. प्रदेश में कांग्रेस की यह दूसरी सरकार है. ऐसे में प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा चुनाव प्रचार का एक हिस्सा मानी जा रही है.

जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आने वाले थे, तब सुप्रा स्टेट की ख़ूब चर्चा हुई. स्थानीय अख़बारों ने लिखा कि केंद्र सरकार आगामी 25 दिसंबर को नगाओं को क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर सुप्रा स्टेट देगी. सुप्रा स्टेट का मतलब पूर्वोत्तर के चारों राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड) में जितने नगा बसे हैं, उनकी एक अलग सरकार बनाना. नगाओं की यह मांग समझ में नहीं आती. इससे पहले वे नगालिम की मांग कर रहे थे और अब सुप्रा स्टेट की मांग कर रहे हैं. स्वाभाविक है कि अगर सुप्रा स्टेट को स्वीकृति मिलेगी तो नगालिम की स्थापना ख़ुद–बख़ुद हो जाएगी. नगाओं की इन मांगों ने स्थानीय लोगों में काफी तनाव पैदा किया. असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने सुप्रा स्टेट को लेकर खुला विरोध जताया कि चारों राज्यों की सहमति के बिना केंद्र नगाओं को कुछ नहीं दे सकता. मणिपुर के मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी ने भी लोगों को आश्वासन दिया कि ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. यह मांग ठुकराते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इंफाल में एक जनसभा में कहा कि सुप्रा स्टेट का कोई प्रस्ताव नहीं है. मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी से किसी को लाभ नहीं हुआ. पूर्वोत्तर में नगा समुदाय के लिए स्वायत्त राज्य बनाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि आर्थिक नाकेबंदी से राज्य की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा. मणिपुर की अखंडता अक्षुण्ण रखी जाएगी, यह देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है. जब उन्होंने कहा कि मणिपुर में क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा बहुत संवेदनशील है तो वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर के विकास के लिए अमन की ज़रूरत है. विभिन्न समुदाय यहां सदियों से रह रहे हैं और उनके बीच कोई ग़लतफ़हमी नहीं होनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र मणिपुर के विकास के लिए कुछ भी करने को तैयार है. केंद्र सरकार मणिपुर का विकास चाहती है, जिसके लिए वह प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि वह मणिपुर में परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन से ख़ुश हैं. पर्वतीय ज़िलों में क़रीब 20 सालों के बाद स्वायत्त ज़िला परिषदों के चुनाव होने पर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि स्थानीय निकायों को पर्याप्त अधिकार मिलेंगे. मनमोहन सिंह ने मणिपुर के खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने–अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है.

यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि आर्थिक नाकेबंदी से लोग प्रभावित हुए हैं. युवाओं को राज्य की स्थिति सामान्य करने की दिशा में काम करना चाहिए. केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि नई दिल्ली इंफाल से दूर हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार बहुत संवेदनशील है. बातचीत के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है. सोनिया ने कुकी उग्रवादियों समेत कुछ उग्रवादी संगठनों को बातचीत हेतु तैयार करने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया. प्रधानमंत्री ने अपनी इस यात्रा के दौरान आश्वासन तो ख़ूब दिए, लेकिन यहां के सबसे ज्वलंत मुद्दे अफसपा के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा और न पिछले 11 सालों से इस मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल कर रहीं शर्मिला के बारे में कोई बात कही. हो सकता है कि ऐसा उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए किया हो.

मणिपुर मूल रूप से दो भागों में विभाजित है, पहला घाटी और दूसरा पहाड़ी. मणिपुर की आबादी 27 लाख से ज़्यादा है. नौ ज़िलों में से चार घाटी में हैं और पांच पहाड़ में. आतंकवाद यहां की स्थायी समस्या है. यहां सक्रिय आतंकवादी अलगाव की मांग करते हैं, वे भारत से अलग होने की लड़ाई लड़ते हैं. वहीं राज्य के अंदर विभिन्न जातियों के बीच भी तनाव है. मणिपुर में लगभग 29 जातियां हैं. उनकी अलग–अलग बोली, संस्कृति और परंपराएं हैं. बड़े समुदायों में नगा, कुकी और मैतै हैं. नगा और कुकी की अनेक उपजातियां हैं, जो हमेशा एक–दूसरे से लड़ती रहती हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री की यात्रा विकास से कोसों दूर मणिपुर को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ सकेगी, इसमें संदेह है.

sbijensngh@gmail.com

एमपीपी यूथ फ्रंट का प्रदर्शन

सुप्रा स्टेट बॉडी के बारे में केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर कोई सफाई न देने और तीन महीने से अधिक आर्थिक नाकेबंदी के संबंध में कोई क़दम न उठाने के विरोध में एमपीपी (मणिपुर पीपुल्स पार्टी) यूथ फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों में ओ जोय, डॉ. एन जी विजय, डॉ. आई इबोहलबी एवं आर के आनंद आदि प्रमुख थे. एमपीपी ने कहा था कि मणिपुर की जनता सुप्रा स्टेट स्वीकार नहीं करेगी और अगर ऐसा कोई फ़ैसला हुआ तो प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर लिखा था, *वेलकम पीएम ऑफ इंडिया विथ ब्लैक कॉर्पेट.* उन्होंने *लांग लिव मणिपुर, वी कंडेम्न इंडियन पॉलिसी और गो बैक पीएम एंड सोनिया* आदि नारे भी लगाए. एमपीपी यूथ फ्रंट के अध्यक्ष मुतुम मनितोन ने कहा कि सुप्रा स्टेट के बारे में केंद्र सरकार को कई ज्ञापन भेजे गए, मगर उनका कोई जवाब नहीं मिला. मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के आने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है और न हम भारत विरोधी भावना रखते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर और पूर्वोत्तर की जनता की भावनाओं को समझ नहीं सकी. अगर वह नाकेबंदी नहीं हटा सकती तो कम से कम ज़रूरी सामान पहुंचाने के लिए संसाधन तो उपलब्ध करा सकती है. अगर लीबिया और इराक में राहत अभियान चलाए जा सकते हैं तो मणिपुर में क्यों नहीं?

केंद्र की नई घोषणाएं

- 12वीं पंचवर्षीय योजना में 6,000 करोड़ रुपये का मुख्य पैकेज
- सुप्रा स्टेट बॉडी बनाने की कोई योजना नहीं
- मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रखी जाएगी
- 13वें वित्त आयोग के तहत 13,600 करोड़ रुपये दिए जाएंगे
- 2011–12 के योजना बजट में पिछले बजट की तुलना में तीन गुना वृद्धि
- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तुलिहल एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड करेगी
- जिरी–इंफाल रेल मार्ग का निर्माण कार्य 2016 में पूरा हो जाएगा
- एनएच–53 का निर्माण कार्य 2013 में पूरा हो जाएगा
- ओल्ड काछार रोड बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति
- मराम–पेरेन रोड को डबल लेन करने का काम आगामी मार्च तक पूरा हो जाएगा
- मालोम में ऑयल डिपो की स्थापना
- सेकमाई बॉटलिंग प्लांट की क्षमता 600 से बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन की जाएगी
- टिपाइमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी
- हर जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना
- उखरूल और सेनापति जिले में नवोदय विद्यालय के निर्माण को स्वीकृति
- रिम्स (रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस) अस्पताल अपग्रेड किया जाएगा
- पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में हर साल 50 करोड़ रुपये मिलेंगे
- इंफाल–मंदले बस टर्मिनल के लिए म्यांमार सरकार से बातचीत की जाएगी

मेरी दुनिया.... सरकारी बाबू की चिंता

नेचर्स ट्रेल
वन्यजीवों को बचाने की मुहिम

उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि वन्यजीवों का संरक्षण बेहद ज़रूरी है. वह बीते नौ दिसंबर को दिल्ली के मंडी हाउस स्थित ललित कला अकादमी में जाने-माने वन्यजीव फोटोग्राफर, राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी कमल एम मोरारका की फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे. 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चली नेचर्स ट्रेल नामक इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के अध्यक्ष एवं सांसद डॉ. कर्ण सिंह और मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई क़ुरैशी ने संयुक्त रूप से किया. इस मौक़े पर सांसद डॉ. कर्ण सिंह ने कमल मोरारका के चित्रों की सराहना करते हुए कहा कि वन्यजीवों के प्रति जागरूकता के लिए निरंतर प्रयास की ज़रूरत है. मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई क़ुरैशी ने कहा कि पहले देश में बड़ी तादाद में जीवों का शिकार किया जाता था, लेकिन जागरूकता की वजह से अब इसमें कमी आ रही है. इस तरह की प्रदर्शनियों के ज़रिये लोग वन्यजीवों को बेहद क़रीब से जान पाएंगे. जनतादल (यूनाइटेड) के प्रमुख शरद यादव ने चित्रों को जीवंत बताते हुए कहा कि वन्यजीवों के प्रति कमल मोरारका के इस प्रयास की जितनी सराहना की जाए, कम है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद मणिशंकर अय्यर ने चित्रों की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों में वन्यजीवों के प्रति जागरूकता पैदा होगी. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह ने कहा कि वन्यजीवों की तस्वीरें खींचना काफ़ी मुश्किल कार्य है, लेकिन कमल मोरारका ने इसे बख़ूबी अंजाम दिया है. कमल मोरारका बताते हैं कि एक बार जब वह राजस्थान के भरतपुर में घूमने गए तो वहां परिंदों के झुंडों को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा. तभी उनके मन में वन्यजीवों की तस्वीरें खींचने का ख्याल आया और फिर वह अपने इस मिशन में जुट गए. उन्होंने दुर्गम परिस्थितियों में खींची तस्वीरों का ज़िक्र करते हुए उनकी विशेषताएं भी बताईं. चौथी दुनिया के संपादक संतोष भारतीय ने अतिथियों को चित्र प्रदर्शनी के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले मुंबई में भी मोरारका जी द्वारा खींचे गए चित्रों की प्रदर्शनी लग चुकी है, जिसे काफ़ी सराहा गया. प्रदर्शनी देखने आए लोगों ने भी सराहना करते हुए इस तरह के प्रयास जारी रहने की ज़रूरत पर बल दिया.

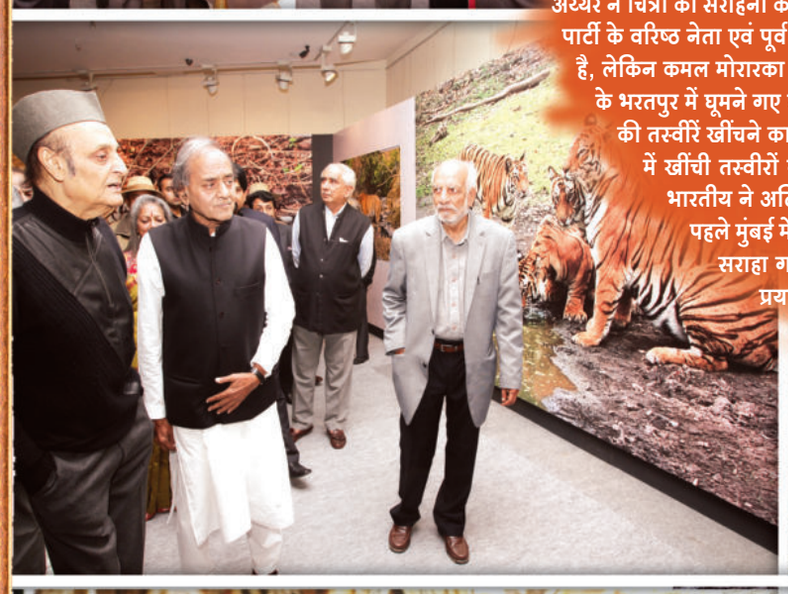

महावीर प्रसाद आर मोरारका

विदेशी आर्थिक सहायता शुद्ध स्वार्थ से प्रेरित

कोई भी पूंजीवादी उद्योगपति, किसी भी देश का वासी क्यों न हो, अपनी पूंजी तब ही लगाएगा, जब उसे उसकी सुरक्षा और उससे लाभ होने का पूरा विश्वास हो. अगर भारत सरकार की नीति उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की रही तो कोई भी बाहरी पूंजीवादी अपना एक रुपया भी भारत में नहीं लगाएगा. यह शंका सर्वथा निर्मूल तो नहीं है, पर ग़लत आधारशिला पर स्थित है. कोई भी पूंजीवादी तब तक अपने देश से बाहर जाकर रुपया नहीं लगाएगा, जब तक उसे अपने देश में मौक़ा मिलता रहे. विश्व में कोई भी देश परिपूर्ण हो नहीं पाया है और कभी हो भी नहीं सकता. प्रत्येक देश में पूंजी लगाने के और उससे लाभ कमा सकने के अनेक क्षेत्र खुले पड़े हैं, फिर भी ये विदेशी पूंजीपति भारत में या अन्य पिछड़े हुए देशों में क्यों अपनी पूंजी लगाते हैं, यह विषय परीक्षण करने योग्य है. सृष्टि के आदि से लेकर आज तक मानव-मानव का संघर्ष होता आया है. यह संघर्ष अवश्यंभावी है. चाहे वह संघर्ष साम्राज्य विस्तार की लिप्सा से हो, चाहे अपने धर्म या मत प्रचार के लिए हो, चाहे अर्थमूलक हो, संघर्ष चलता ही रहेगा और चलता ही रहता है.

गत महायुद्ध में जर्मनी के हिटलर और इटली के मुसोलिनी की तानाशाही से आतंकित होकर बाक़ी देशों ने उनके विरुद्ध युद्ध किया. परिणाम सामने है. आज शांति स्थापित हुए 14 वर्ष बीत गए, पर क्या सही माने में इसे शांति कह सकते हैं? आज दो प्रधान खेमों के बीच का भयानक विस्फोट विश्वयुद्ध में परिणत होने को है. एक ओर है, सोवियत रूस द्वारा संचालित साम्यवाद, जिसमें चीन, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी इत्यादि अनेक देश शामिल हैं. दूसरी तरफ़ अमेरिका के नेतृत्व में प्रजासत्तात्मक गणतंत्र राज्य है, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देश शामिल हैं और जिनको पूंजीवाद का पोषक माना जाता है. इन दोनों तथाकथित वादों में साम्यवाद और पूंजीवाद में ज़बरदस्त संघर्ष है. दोनों ही दल अपनी-अपनी शक्ति बढ़ाने में प्रयत्नशील हैं. मानव मस्तिष्क के जितने भी विनाशक अणु हैं, उनका पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है. परमाणु बम, हाइड्रोजन बम इत्यादि भयानक अस्त्र इसी तरह की मनोवृत्ति की देन हैं. दोनों दल बाज़ी लगाकर बैठे हैं कि इस पृथ्वी भर का नाश कौन कितनी जल्दी कर सकता है. इसी प्रतियोगिता में सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर आक्रमण करने की भी होड़ लगी हुई है. अगर सोवियत रूस ने चंद्र लोक पर पहले राकेट या स्पूतनिक भेज दिया तो अमेरिका मंगल ग्रह पर पहले पहुंचने की फ़िक्र में है. बात देखने-सुनने में आश्चर्यजनक और परियों की ख्याली कहानी दिखाई देती है, पर है यह सच. आज विश्व में अपनी-अपनी शक्ति की माप-तौल बढ़ाने में दोनों पक्ष जोर-शोर से लगे हुए हैं. इसी तरह अपने-अपने पक्ष को ज़्यादा पुष्ट या ताक़तवर बनाने के लिए दोनों ही दल ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं.

चीन की जनसंख्या भारत से कहीं ज़्यादा है. वहां की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भारत से कोई अच्छी नहीं थी. फिर भी जब सोवियत रूस वाले साम्यवाद के पक्ष में वह देश शामिल हो गया तो विकास और उद्योगीकरण अल्पकाल में ही संभव हो गया. क्या सोवियत रूस ने यह सारी सहायता दया या कृपा करके दी? कदापि नहीं, अपने स्वार्थ-साधन के लिए ही एक देश दूसरे देश को आर्थिक या सैनिक सहायता प्रदान करता है. भारत जबसे स्वतंत्र हुआ है, दोनों ही खेमे वाले इस प्रयत्न में हैं कि भारत उनके खेमे में शामिल हो. सौभाग्यवश इस देश का संविधान प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र है और इसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू हैं. वह किसी भी पक्ष में शामिल नहीं हुए हैं, न अपने देश को ही किसी गुट में शामिल होने दिया. यही कारण है कि आर्थिक सहयोग भारत को दोनों में से किसी पक्ष से भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है.

जर्मनी युद्ध में पराजित और ध्वस्त हो गया था और वह आज भी दो भागों में विभक्त है. एक भाग पश्चिमी पावर ब्लॉक अमेरिका के अधीन है. वह इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है, जितनी वह ताकत के चरम शिखर पर भी नहीं कर सका था. सोवियत रूस के अधीन जर्मनी का जो भाग है, वहां भी प्रगति भारी परिमाण में हुई है. ऐसा दावा किया जाता है, हालांकि उसका पूरा विवरण प्राप्त नहीं है. कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी विदेशी ताक़त भारत को आर्थिक सहायता देती है तो वह भारत पर कोई उपकार नहीं करती. वे अपने पक्ष का समर्थन बढ़ाने के उद्देश्य से ही ऐसा करते हैं और अगर भारत खुल्लमखुल्ला एक पक्ष का समर्थन करने लग जाए तो उसे पर्याप्त आर्थिक सहायता मिल सकती है. अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों का विकास पर्याप्त मात्रा में हो चुका है. उनके उसूल प्रजातांत्रिक गणतंत्र के हैं. अतएव भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नीति के वह ज़्यादा निकट हैं. पर किसी शक्ति-गुट में शामिल हों या न हों, यह तो राजनीतिक प्रश्न है, जिसके बारे में कुछ कहने से विषयांतर की संभावना है. कहना इतना ही है कि भारत को अपने विकास के लिए अगर विदेशी आर्थिक सहायता अपेक्षित है ही तो, वह मिले अथवा न मिले, सिद्धांतों का हनन तो कदापि नहीं करना चाहिए. अगर भारतीय जनता के हित में यह है कि तमाम मुख्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना ही चाहिए तो सिर्फ़ इसी आपत्ति से कि विदेशी सहायता नहीं मिलेगी, राष्ट्रीयकरण रुकना नहीं चाहिए.

एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इसी दौरान में उठता है. वह है, भारत के पूंजीवादी उद्योगपतियों का यहां से विदेशों में धन भेज देना. यहां के धनिकों को जब यह शंका हुई कि सरकार शायद जमीन, जायदाद और राष्ट्रीयकरण कर लेगी, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था को सरकार मान्यता दे चुकी है तो ये धनिक आशंकित और भयभीत हो उठे. अंग्रेजी सरकार का सहारा सिर पर से उठ ही चुका था. अब क्या करें? वे घबरा गए. बहुतों ने, खास करके राजा-महाराजाओं ने, असंख्य धन, सोना, हीरे, जवाहरात के रूप में या अन्य तरीक़ों से विदेशों में भेज दिया. वहां यह धन ब्याज कमा रहा होगा या यों ही बेकार पड़ा होगा, पर यह निश्चित है कि ऐसा धन जो विदेशों में भेजा गया है, वह भारत के साथ वैमनस्यपूर्ण परिणाम प्रस्तुत करता है. राष्ट्र का कर्तव्य है कि क़ानूनन इस तरह के कामों को अवैध ही करार न करे, बल्कि उन्हें बाध्य करे कि जो धन वे विदेशों में ले गए हैं, उसे वे लौटा लें और इस तरह की चेष्टाओं का अंत करने के लिए उच्चस्तरीय तात्कालिक सख्त क़दम उठाए जाएं.

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

कमल मोरारका का ब्लॉग

www.kamalmorarka.com

सरकार को स्थगन प्रस्ताव मानना चाहिए

खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश पर सरकार ने जो निर्णय लिया कि इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, यह फ़ैसला तो सही किया, लेकिन प्रणव मुखर्जी का जो बयान है, उसकी खास बात यह है कि वह नहीं चाहते थे कि लोकसभा भंग करने का दबाव बढ़े और जल्दी चुनाव कराना पड़े. यह अपने आप में एक तरह का खुलासा है. खुलासा इसलिए, क्योंकि सरकार खुद यह समझती है कि जनता में यह एक लोकप्रिय नीति नहीं है. किसी नीति पर फ़ैसला करने से पहले जनता की राय को महत्व देनी चाहिए, ताकि सरकार को फिर से कदम पीछे न खींचना पड़े. वर्ष 1970 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उसका भी विरोध हुआ था, लेकिन उसी बात पर उन्होंने चुनाव कराया और भारी बहुमत से जीत कर आईं. यह लोकतंत्र का नया आयाम है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार खुद यह मानती है कि जो नीतियां वह लागू कर रही है, वे लोकप्रिय नहीं हैं.

मैं समझता हूं कि चुनी हुई सरकार पर नीतियां निर्धारित करने पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए. किसी भी सरकार पर कानून बनाने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए. सरकार वही नीति बना सके, जिस घोषणापत्र पर वह चुनकर आई है. उसके बाहर कानून बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए. जनता ने सरकार को चुना है, उनका मेनिफेस्टो पढ़कर और अगर आप उससे आगे जाना चाहते हैं तो आपको फिर से जनता की राय लेनी चाहिए. प्रणब मुखर्जी की तारीफ कर रहा हूं, जो कम से कम साफ-साफ बोल रहे हैं कि इस मुद्दे को आगे ले जाने में खतरा था. हो सकता था कि जिस तरह उन्होंने न्यूक्लियर बिल पास कराया, सहयोगी पार्टियों को मनाकर या खरीद-फरोख्त करके इसे भी पास करा लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार अपने सहयोगी दलों को उस नीति पर समझा नहीं पाई, जिस पर उसे खुद संदेह है.

संसद में दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, महंगाई और काला धन. संसद में हंगामा हो रहा था. भाजपा सदन चलने नहीं दे रही थी. होना तो यह चाहिए था कि सरकार और विपक्ष, दोनों मिल-बैठकर पहले ही तय कर लेते कि किस मुद्दे पर, किस तरह से बात होगी और किसी भी हालत में काम बंद नहीं होना चाहिए. लोकसभा में गतिरोध बहुत है. जब एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन का प्रस्ताव आता है तो होना यह चाहिए कि स्पीकर को उसे मानना चाहिए. स्थगन प्रस्ताव का मतलब सदन का स्थगन नहीं है, बल्कि जो काम चल रहा है, उसका स्थगन होना चाहिए. जो ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर बहस होनी चाहिए. जब स्थगन प्रस्ताव के लिए पचास सांसद खड़े हों तो स्पीकर को प्रस्ताव मान लेना चाहिए. चाहें तो सदस्यों की संख्या 50 की जगह 60 कर सकते हैं. अगर सारा विपक्ष स्थगन चाहता है तो सरकार को उस पर क्या आपत्ति है. स्थगन प्रस्ताव को तो मानना ही चाहिए, तभी देश की जनता को संतोष होगा.

संसद में दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, महंगाई और काला धन. संसद में हंगामा हो रहा था. भाजपा सदन चलने नहीं दे रही थी. होना तो यह चाहिए था कि सरकार और विपक्ष, दोनों मिल-बैठकर पहले ही तय कर लेते कि किस मुद्दे पर, किस तरह से बात होगी और किसी भी हालत में काम बंद नहीं होना चाहिए. लोकसभा में गतिरोध बहुत है. जब एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन का प्रस्ताव आता है तो होना यह चाहिए कि स्पीकर को उसे मानना चाहिए. स्थगन प्रस्ताव का मतलब सदन का स्थगन नहीं है, बल्कि जो काम चल रहा है, उसका स्थगन होना चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

क़लम की ताक़त

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर हो रहे हमले बेहद चिंता का विषय हैं. मीडिया से टकराए तानाशाहों का अंजाम दुनिया देख चुकी है. प्रभावशाली लोग अपने स्वार्थ के लिए संवाददाताओं पर हमले कराने से भी नहीं चूकते. पिछले दिनों धनबाद में एक अख़बार के संवाददाता के साथ मारपीट की गई और सरेआम अख़बार की प्रतियां जलाई गईं. इस घटना ने ब्रिटिश शासन की याद ताज़ा कर दी. यह नहीं भूलना चाहिए कि क़लम की ताक़त के आगे तलवार भी कुछ नहीं कर पाती.

–अक्षय कुमार मिश्रा, *धनबाद, बिहार.*

सर्वश्रेष्ठ पत्र

जनता की मजबूरी

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-भारतीय राजनीति का ख़ालीपन पढ़कर कहा जा सकता है कि राजनीति कब किस ओर करवट लेगी, यह स्वयं राजनीतिज्ञ भी नहीं जानते. कभी मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और पी चिदंबरम कांग्रेस के त्रिदेव हुआ करते थे, लेकिन आज हालात बदल गए हैं. भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी यूपीए सरकार आंतरिक कलह में उलझ कर रह गई है. प्रधानमंत्री को बार-बार बताना पड़ रहा है कि वह पंगु प्रधानमंत्री नहीं हैं. युवा वर्ग राहुल गांधी को देश के भविष्य के रूप में देख रहा है, लेकिन उनके मौन पर सब स्तब्ध हैं. यही हाल विपक्षी पार्टी भाजपा का है. जनता नागनाथ या सांपनाथ में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर है.

–प्रभात कुमार, *रमेश नगर, नई दिल्ली.*

ब्लॉग पसंद आया

चौथी दुनिया के आलेख सबसे अलग होते हैं, जिन्हें पढ़कर अच्छा लगता है. कमल मोरारका का ब्लॉग भी पसंद आया. साईं बाबा के चमत्कारों के बारे में भी जानकारी मिलती है. लेख पढ़कर शिरडी जाने की इच्छा हो रही है. चौथी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष सामग्री नियमित रूप से दी जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा.

–ईश्वर चंद्र आत्रेय, *हिसार, हरियाणा.*

मायावती की रणनीति

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने बहुत सोच-समझ कर चुनावी रणनीति तैयार की है. उन्होंने प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने का जो दांव चला है, समाजवादी पार्टी उसका विरोध कर रही है. भाजपा भी बहुजन समाज पार्टी पर कीचड़ उछाल रही है. अगर मायावती अपनी चाल में कामयाब हो जाती हैं तो प्रदेश में एक बार फिर से नीला झंडा लहराएगा.

–सुधीर एच तायडे, *अमरावती कैंप, महाराष्ट्र.*

परमाणु संयंत्र का विरोध

केंद्र सरकार के परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के निर्णय से जनता में भय पैदा हो गया है. एक ओर महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले के जैतपुर में परमाणु संयंत्र की स्थापना का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चेन्नई के कुडानकुलम परमाणु संयंत्र की स्थापना का भी विरोध किया जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति लोगों की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था किए जाने का ढोल पीट रही है. जापान का उदाहरण सबके सामने है. ऐसे में भारत में परमाणु संयंत्र की स्थापना को उचित नहीं ठहराया जा सकता. सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए.

–प्रताप नारायण सिंह, *बेगूसराय, बिहार.*

देव आनंद का जाना

फिल्म अभिनेता देव आनंद अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने अभिनय के कारण वह सदा जीवित रहेंगे. उनकी विशेष जीवनशैली के कारण उन्हें सदाबहार अभिनेता कहा जाता रहा है. देव आनंद ने अपनी आत्मकथा-रोमांसिंग विद लाइफ में कुछ ऐसी बातें भी लिखीं, जिनका ज़िक्र उन्होंने कभी अपने साक्षात्कारों में नहीं किया था. किताब में गुरुदासपुर (पंजाब) में बिताए अपने बचपन से लेकर फिल्मी संघर्ष, प्रेम-प्रसंग, अभिनेताओं से अपनी प्रतिद्वंद्विता और राजनीति से लेकर फिल्म मेकिंग के प्रति अपने जुनून तक की बातों का ज़िक्र है.

–काशिफ़, *दरियागंज, दिल्ली.*

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें:

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट लागू होनी चाहिए

उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर पर है और कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण का शिगूफ़ा छोड़ दिया है. कांग्रेस इसलिए, क्योंकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कांग्रेस के सदस्य हैं. इसलिए यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि शिगूफ़ा कांग्रेस ने छोड़ा है. शिगूफ़ा इसलिए, क्योंकि इसमें कोई गंभीरता नज़र नहीं आती. अगर गंभीरता होती तो कई सालों तक रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में न पड़ी रहती और न सरकार दबाव में आकर इसे सदन में रखती. सरकार ख़ुद इसे सदन के पटल पर रख सकती थी, साथ ही वह संसद को यह जानकारी देती कि उसने क्या कार्रवाई की और किस तरह रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट लागू होगी. जस्टिस सच्चर की कमेटी बनी थी. जस्टिस सच्चर ने देश को ख़ासकर अल्पसंख्यकों के बीच व्याप्त भेदभाव के कारण बताए थे. लगभग हर मुस्लिम संगठन और नेता सच्चर कमेटी को लेकर काफ़ी चिंतित हुआ. रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट बीमारी का कारण नहीं, निदान बताती है, लेकिन अफ़सोस की बात यह कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, इसके लिए न मुस्लिम संगठनों ने कुछ किया और न राजनीतिक दलों ने.

यह संयोग की बात है कि जब हमने इस रिपोर्ट को छापा तो कुछ सांसद जागे और राज्यसभा एवं लोकसभा में इसे लेकर हंगामा हुआ. अंततः सरकार ने मजबूर होकर रिपोर्ट को सदन में रखा. हमने कहा था कि सरकार कहे कि यह रिपोर्ट झूठी है. सरकार ने रिपोर्ट को झूठी कहने की जगह उसे सदन में रखने का दबाव सांसदों का मान लिया. रिपोर्ट को सदन में रखे हुए भी लगभग दो साल हो गए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और न करने के लिए इच्छाशक्ति दिखाई. अब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर पर है तो सरकार कह रही है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा. बहुत सारे अंतर्विरोध हैं. क्या सभी मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा, मुसलमानों में जो पिछड़े हैं, उन्हें आरक्षण मिलेगा या पिछड़ों में भी जो अति पिछड़े हैं, उन्हें आरक्षण मिलेगा? आरक्षण अगर मुसलमानों को मिलता है तो वह सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले को ध्यान में रखते हुए मिलेगा कि 50 प्रतिशत से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता. सामान्य कोटे में से किसे निकालेंगे. यह आरक्षण सामान्य कोटे से दिया जाएगा या दलित-अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण है, उसमें से दिया जाएगा, यह अभी साफ़ नहीं है.

सरकार को इस तरह के खेलों से बचना चाहिए, अगर उसे वाक़ई कुछ करना है. इस तरह के खेलों से सरकार या सरकार चलाने वाली पार्टियों को कोई फ़ायदा मिलेगा, ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोग उतने भोले नहीं हैं, जितने आज से 15 या 20 साल पहले थे. अब नई पीढ़ी या जो लोग जवानी से बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, वे तरह-तरह के बयानों का मतलब समझने लगे हैं. अगर कांग्रेस यह सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी या उसकी विचारधारा वाली पार्टियां इस बयान का विरोध करेंगी और उसे मुसलमानों के वोटों का लाभ मिल जाएगा तो शायद वह ग़फ़लत में है. भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को भी मालूम है कि यह सिर्फ़ एक शिगूफ़ा है. उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि वे इसे चाहे जितना उछालें, उन्हें ग़ैर मुस्लिम वोटों का बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस देश में रहने वाले, चाहे वे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों या बहुसंख्यक हों, सभी लोग राजनीतिक दलों की चालों को थोड़ा-बहुत समझने लगे हैं. राजनीतिक भाषा का अर्थ उन्हें पता चल गया है. इससे सिर्फ़ इतना हो सकता है कि छोटे तबक़ों को भरमा कर आप अखबारों में बयान दिला सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता.

होना यह चाहिए कि देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग यानी मुसलमानों को महसूस हो कि हम उनकी परेशानियों से वाक़िफ़ हैं, यह मुल्क उनकी चिंताओं को समझता है और उन्हें अपने बराबर लाने के लिए कुछ नए उपाय भी सोच सकता है. इसके लिए 2006 से अभी तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी. लगभग चार साल से ज़्यादा का वक़्त गुज़र गया, सरकार, संसद और राजनीतिक दल अगर गंभीर होते तो अब तक कुछ न कुछ उपाय लागू करने की घोषणा हो चुकी होती. दरअसल यह पूरा तंत्र न केवल अमानवीय तंत्र में बदल रहा है, बल्कि उसने लोगों की परेशानियों, तकलीफ़ों से चिंतित होना भी छोड़ दिया है. इसका सबसे भयंकर नतीजा यह निकल रहा है कि देश के दबे-कुचले वर्ग में से कई सारे नौजवान देश, देशभक्ति और देश के प्रति अपने कर्तव्य की सीमाएं भूलने लगे हैं. उन्हें लगता है कि जब मुल्क में रहने वाले लोग, दूसरे शब्दों में मुल्क को चलाने वाले लोग उनकी तकलीफों के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए इस मुल्क को अपना कहना कितना जायज़ है. ऐसी भावना अगर मुल्क के थोड़े से लोगों में भी पैदा हुई है, तो यह हम सभी की असफलता है और ख़तरनाक भी. पर दुर्भाग्य की बात यह कि ऐसा हो रहा है.

भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को भी मालूम है कि यह सिर्फ़ एक शिगूफ़ा है. उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि वे इसे चाहे जितना उछालें, उन्हें ग़ैर मुस्लिम वोटों का बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस देश में रहने वाले, चाहे वे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों या बहुसंख्यक हों, सभी लोग राजनीतिक दलों की चालों को थोड़ा-बहुत समझने लगे हैं. राजनीतिक भाषा का अर्थ उन्हें पता चल गया है. इससे सिर्फ़ इतना हो सकता है कि छोटे तबक़ों को भरमा कर आप अख़बारों में बयान दिला सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता.

बहुत सारे हिस्सों में इस तरह के विचार चलाए जा रहे हैं कि यह मुल्क उनके लिए नहीं है, जो गांवों में रहते हैं. यह मुल्क किसानों, अल्पसंख्यकों या कमज़ोरों के लिए नहीं है. वे लोग इसलिए हैं, क्योंकि वे सरकारों को चुन रहे हैं. उनका कर्तव्य सिर्फ़ वोट डालना है, वोट डालने के बाद उनकी ज़िंदगी सुधरी या नहीं सुधरी, इससे जीतने वालों को कोई मतलब नहीं रहता. यह भावना देश प्रेम की अवधारणा के ख़िलाफ़ है, पर यह बात इसलिए फैल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुल्क चलाते हैं, गंभीरता से सोचते नही हैं. अफ़सोस की बात यह है कि इधर जितने फ़ैसले हुए, उनमें से ज़्यादातर ऐसे थे, जिन्हें देश के लोगों ने शंका की नज़र से देखा. एक अजीब संयोग है और दुर्भाग्य भी कि अगर आप अपना दर्द सरकार से बताने जाएं तो वह यह मानती है कि आप उसका विरोध कर रहे हैं. अपना दर्द बताने वाले चाहे मुसलमान हों, दलित हों, ग़रीब हों या अन्य वंचित लोग, सरकार उन्हें कब अपना दुश्मन मान ले, यह कहा नहीं जा सकता. यह अजीब सी चीज सरकार चलाने वालों के बीच पैदा हुई है. पहले जब लोग अपना दु:ख-दर्द कहते थे तो सरकार उस पर विचार करती थी, उसे दूर करने का उपाय बताती थी, लोगों से सुझाव आमंत्रित करती थी, पार्टी फोरम में उस पर बहस होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता. अब अगर आप देश या ग़रीबों की बात करें तो सरकार और राजनीतिक दलों को लगता है कि आप उनका विरोध कर रहे हैं. इसे कहने या प्रकट करने में सरकार के लोगों को कोई संकोच भी नहीं होता. इसीलिए अब लोगों ने मंत्रियों या सरकारी अधिकारियों से शिकायतें करना बंद कर दिया है. मन ही मन कहीं घुटन हो रही है, कहीं ऊब हो रही है, कहीं लोग ख़ुद को निराश महसूस कर रहे हैं. अब इन सब स्थितियों का हल या जिन्हें इनका सामना करना है, वे लोग सोए हुए हैं. वे ऐसी बातें करते हैं, जो ग़ैर ज़िम्मेदाराना होती हैं.

हमने यह विषय नए तरीक़े से इसलिए उठाया, क्योंकि यह विषय कुछ ऐसा है, जो ग़लतफ़हमियां पैदा कर सकता है. अगर यह विषय हिंदू-मुसलमान के संदर्भ में देखा जाएगा तो इससे ग़लतफ़हमियां पैदा होंगी, लेकिन यह विषय इस तरह देखा जाना चाहिए कि देश में रहने वाले, एक तरह के काम करने वाले, भले ही वे किसी भी धर्म के हों, उनकी समस्याएं एक हैं, आर्थिक स्थिति एक है, ग़रीबी-बीमारी-बेकारी एक है, तो अगर एक तबक़े को सुविधाएं मिलती हैं तो दूसरे तबक़े को क्यों नहीं मिल रही हैं? रंगनाथ मिश्र कमीशन यही कह रहा है कि अगर हिंदू दलितों को संरक्षण मिल रहा है तो मुस्लिम या ईसाई दलितों को संरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है.

जस्टिस रंगनाथ मिश्र स्वयं उच्च जाति से आते हैं, लेकिन जब आप देश के बारे में फ़ैसला कर रहे होते हैं तो न आपकी कोई जाति होती है, न आपका कोई धर्म होता है और न आप किसी के भाई या चाचा होते हैं. आप न्याय की कुर्सी पर होते हैं. शायद यही न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र ने किया. वह ऐसी कुर्सी पर थे, उन्हें एक ऐसी रिपोर्ट बनानी थी, जिसका आग्रह सुप्रीम कोर्ट ने किया था और जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर टर्म ऑफ रेफरेंस में डाला था. उन्हें मालूम था कि अगर वह ग़लत सिफ़ारिशें करेंगे तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा. इसलिए उन्होंने सिफ़ारिशें कीं, जिनका विरोध किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया. जब किसी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया तो फिर क्यों सरकार ने इसे लोगों से छुपाए रखा और क्यों नहीं अब भी इन समस्याओं के समाधान के लिए सुझाए गए रास्तों पर वह अमल कर रही है. अगर सरकार अभी भी रंगनाथ मिश्र कमीशन द्वारा सुझाई गई सलाहों पर अमल करने का फ़ैसला करे और लागू होने वाले क़दमों का ऐलान करे तो यह मानना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा निराशा के दौर में नहीं हैं. सरकार से यह आग्रह करना चाहिए, ख़ासकर मुस्लिम संगठनों को आग्रह करना चाहिए कि सरकार रंगनाथ मिश्र कमीशन द्वारा की गई सिफ़ारिशों को लागू करने में देर न लगाए. पर यहां सवाल मुसलमानों के अपने बीच का भी है कि उनके अपने नेता, उनके संगठन इस कमीशन की सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं. वे जितनी बहसें जस्टिस सच्चर द्वारा सुझाई गई सिफ़ारिशों पर करते हैं, उतनी गंभीरता के साथ रंगनाथ मिश्र कमीशन में सुझाई गई तस्वीर को क्यों नहीं देखते या उनके द्वारा सुझाए गए क़दमों पर बहस क्यों नहीं करते. इस सवाल का जवाब अगर किसी को देना है तो मुस्लिम संगठनों को ही देना है. मुस्लिम संगठनों से एक ही बात कह सकते हैं या सामान्य मुसलमानों से कि अगर आप ख़ुद मांग नहीं करेंगे तो लोग आपके दरवाज़े पर आकर आपको खाना नहीं देंगे, आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई नहीं करेंगे. इसलिए यह ज़रूरी है कि आप ख़ुद रंगनाथ मिश्र कमीशन की सिफ़ारिशों को समयबद्ध तरीक़े से लागू करने के लिए सरकार पर दबाव डालें.

संपादक

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

एफडीआई और राजनीति

जब मैं युवा था तो सारी रात बैठकर कथकली का नृत्य देखा करता था. इसमें भाग लेने वाले कलाकार अलग तरह के मास्क और वस्त्र पहने हुए होते थे. इनका प्रदर्शन बहुत शानदार हुआ करता था. भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध होता था, जिसमें कलाकार बहुत समय तक एक-दूसरे के इर्द-गिर्द चक्कर लगाते थे. हम सभी लोग इसके परिणाम से वाकिफ होते थे, लेकिन फिर भी इसे मजे से देखते थे. कुछ इसी तरह का ड्रामा इस समय खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश को लेकर हमारे देश में चल रहा है. इसके बारे में वही सारी बातें कही जा रही हैं, जो पहले भी कही जा चुकी थीं. भाजपा अचानक उदारवाद के विरुद्ध हो गई है, सरकार के सहयोगी दल पहले की तरह नखरे दिखाने लगे हैं, वामदल अपनी बुद्धिमता दिखाने लगे हैं. ये वही करने की कोशिश करने लगे हैं, जैसा इन्होंने पश्चिम बंगाल में किया था यानी देश को समाजवादी राज्य बनाने की कोशिश तेज हो गई है. सभी लोग विकास के लिए आशाविहीन लड़ाई लड़ने लगे हैं. विदेशी निवेश पर पिछले बीस वर्षों से वाद-विवाद हो रहा है. जब मनमोहन सिंह ने 1991 का बजट पेश किया था तो सीपीएम की तरफ़ से बोलते हुए सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि यह विश्व बैंक और अमेरिका की गुलामी है. आलोचकों का कहना था कि भारत विदेशी क़र्ज़ के जाल में फंस जाएगा और उसका वही हाल होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद हुआ था.

खुदरा क्षेत्र के मल्टीपल ब्रांड में विदेशी निवेश पूरे भारत में तभी लागू किया जाएगा, जबकि संसद इसे स्वीकार करेगी. अगर संसद इसे स्वीकार नहीं करती है तो इसे लागू करना मुश्किल हो जाएगा. विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है. अगर इसे मान भी लिया जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी.

यही बात उस समय भी कही गई थी, जबकि 1980 में सत्ता में वापसी के बाद इंदिरा गांधी ने आईएमएफ से क़र्ज़ लिया था. उन्हीं लोगों ने आज फिर से साम्राज्यवाद विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए हैं. वामदलों की बात करें तो उन्होंने भी आर्थिक सुधार की इस प्रक्रिया को नहीं रोका था, जब वे देवगौड़ा सरकार का समर्थन कर रहे थे. भाजपा की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं थी. उसने भी अपनी एनडीए सरकार (1998-2004) के समय कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई उदारवादी योजना को नहीं रोका था, बल्कि उसे और गति ही प्रदान की थी. देखा जाए तो भारत इस मायने में सौभाग्यशाली रहा है कि पिछले बीस सालों में इसे केवल पांच वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और प्रणव मुखर्जी मिले हैं. इन सभी ने उदारवादी सुधार के लिए लगभग समान मत रखे हैं. यहां तक कि वामदलों ने भी ऐसा ही किया, जबकि वे यूडीएफ और यूपीए-1 सरकार में सहयोगी थे.

खुदरा क्षेत्र के मल्टीपल ब्रांड में विदेशी निवेश पूरे भारत में तभी लागू किया जाएगा, जबकि संसद इसे स्वीकार करेगी. अगर संसद इसे स्वीकार नहीं करती है तो इसे लागू करना मुश्किल हो जाएगा. विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है. अगर इसे मान भी लिया जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी. कुछ राज्य सरकारें इसे लागू नहीं करेंगी, उन्हें इसे चुनने के लिए छोड़ दें. बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु अगर इसे नहीं लागू करना चाहते हैं तो उन्हें इसे अस्वीकार करने दें. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, गुजरात, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश इसे लागू करते हैं, तो वहां इसे लागू होने दें. इसके बाद यह देखना काफी रोमांचक होगा कि उक्त राज्य कितने दिनों तक इसे लागू नहीं करते हैं. हमारे सांसद संभवत: देश के बड़े बाज़ारों की दुकानों पर नहीं जाते हैं. अगर किसी बाज़ार की दुकानों पर जाएं तो हक़ीक़त का पता चले. अगर मांस-मछली की किसी दुकान पर चले जाएं तो वहां आपको चारों तरफ़ चूहे दौड़ते दिखाई देंगे. साफ-सफाई का तो कोई ध्यान ही वहां नहीं होता है. इन बाज़ारों में मिलने वाले सामानों से अक्सर बीमारी हो जाती है. दूसरी तरफ़ देखें तो भारत के फल-सब्जी उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है. वह बाज़ार तक पहुंच ही नहीं पाता है. भारत में खाद्य पदार्थों का लगभग बीस फ़ीसदी हिस्सा बाज़ार तक नहीं पहुंच पाता और रास्ते में ही नष्ट हो जाता है. इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है, हमारे किसानों को ही न. इस नुक़सान के चलते किसानों की आय कम हो जाती है. यह किसी एक राज्य की स्थिति नहीं है, बल्कि ऐसा हर जगह होता है.

अगर हम किसानों की भलाई चाहते हैं, तो फिर हमें उनके उत्पादों को सही क़ीमत देनी होगी और इसके लिए उन्हें आधुनिक विपणन व्यवस्था से जोड़ना होगा. अगर उपभोक्ताओं को सही सामान देना है, तो स्वच्छ दुकानें उन्हें उपलब्ध करानी होंगी. ऐसा लगता है कि खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश को लेकर जो हंगामा हो रहा है, वह केवल देश की वर्तमान समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने का एक तरीक़ा है. देश के समक्ष कई गंभीर समस्याएं हैं, जिन पर सही तरीक़े से ध्यान नहीं दिया जा रहा है. हमारे देश की जीडीपी लगातार घटती जा रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के समक्ष कई चुनौतियां हैं. पाकिस्तान का अमेरिका के साथ विवाद चल रहा है, जिसके कारण चीन को मौक़ा मिल गया है कि वह पाकिस्तान के साथ अपने संबंध मज़बूत करे. म्यांमार के साथ भी यही स्थिति है. हालांकि अमेरिका उसके साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन पहले से वहां मौजूद है. वह भारत को घेरने की नीति अपनाए हुए है. अगर यही स्थिति रही तो हम चारों तरफ़ से चीन से घिर जाएंगे, जिसका वह किसी भी समय भारत के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है. अत: यह समय इस तरह के ड्रामे करने का नहीं है, बल्कि देश की गंभीर समस्याओं की तरफ़ विशेष ध्यान देने का है.

feedback@chauthiduniya.com

लोग इसे झाड़-फूंक से ठीक हो जाने वाला रोग मानते हैं और जब सब जगह से निराश हो जाते हैं. जब रोग बढ़ जाता है तो वह डॉक्टर के पास पहुंचते हैं.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 19 दिसंबर-25 दिसंबर 2011

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

जब सरकारी अस्पताल में दवा न मिले

ग़रीबों के लिए महंगा इलाज करा पाना या महंगी दवाइयां ख़रीद पाना आसान नहीं होता. इसके लिए सरकार ने सरकारी अस्पताल और सरकारी डिस्पेंसरी (दवाखाना) की व्यवस्था की है, लेकिन देश के कुछ राज्यों में सरकारी अस्पताल का नाम लेते ही एक बदहाल सी इमारत की तस्वीर जेहन में आ आती है. डॉक्टरों की लापरवाही, बिस्तरों एवं दवाइयों की कमी, चारों तरफ़ फैली गंदगी के बारे में सोचकर आम आदमी अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराने के बजाय किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में कराने का फ़ैसला ले लेता है. लेकिन बेचारा ग़रीब क्या करे, जो दो जून की रोटी के लिए ही दिन-रात मेहनत में जुटा रहता है, फिर भी बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए खाने का जुगाड़ कर पाता है. ऐसी स्थिति में उसके पास इस अव्यवस्था के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के अलावा क्या विकल्प बचता है. लेकिन एक रास्ता और है, जिसके सहारे न केवल सरकारी अस्पतालों या दवाखानों में फैले भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है, बल्कि अपना हक़ भी पाया जा सकता है. ग़रीब से ग़रीब आदमी सरकार को टैक्स देता है. इसलिए सरकार से अपने द्वारा दिए गए टैक्स का हिसाब मांगना हमारी ज़िम्मेदारी है. अच्छी स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना सरकार की ज़िम्मेदारी है. अगर सरकार अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतती है तो क्या इसके लिए पांच साल तक इंतज़ार किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि अब सूचना का अधिकार क़ानून है. इस क़ानून के ज़रिए आप सरकार की ज़िम्मेदारी तय कर सकते हैं. सरकार को उसकी लापरवाही के बारे में बताया जा सकता है.

सरकारी अस्पताल के मामले में सबसे ज़्यादा शिकायतें दवाइयों की कमी से ही जुड़े होते हैं और ये शिकायतें जायज़ होती हैं. दरअसल, प्रत्येक सरकारी अस्पताल में दवाइयों की ख़रीद के लिए सरकार पैसा मुहैया कराती है. समस्या यहीं से शुरू होती है. इस बात के लिए कोई कारगर मशीनरी नहीं होती, जो दवाइयों की ख़रीद और जारी किए गए पैसों की जांच करे. नीचे से ऊपर तक के अधिकारी मिल-बांटकर पैसा हजम कर जाते हैं. भुगतना पड़ता है बेचारे ग़रीब आदमी को. सूचना अधिकार क़ानून के ज़रिए अस्पताल और संबंधित सरकारी विभाग से यह पूछा जा सकता है कि अस्पताल के स्टॉक में अभी कितनी दवाएं हैं, कितनी दवाएं इस अस्पताल के लिए ख़रीदी गईं, कब-कब ख़रीदी गईं, कितने पैसों की ख़रीदी गईं. ग़रीबों के बीच निःशुल्क बांटी जाने वाली दवाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है. उदाहरण के लिए सरकारी नीति के तहत टीवी जैसी गंभीर बीमारी के लिए डॉट्स नामक दवा मरीजों के बीच मुफ्त बांटने का प्रावधान है. आप अस्पताल प्रशासन से यह जान सकते हैं कि किसी खास समय सीमा के भीतर कितने मरीजों के बीच उक्त दवा का वितरण किया गया. आप दवा ख़रीदने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के नाम एवं पदनाम के बारे में भी पूछ सकते हैं. ज़ाहिर है, जब आप इतने सारे सवाल पूछेंगे तो अधिकारियों पर दबाव बनेगा. जब दबाव बनेगा तो स्थितियां भी सुधरेंगी. इस अंक में हम इसी मसले से संबंधित आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर आप अपने गांव और शहर के सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार ला सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप
(अस्पताल में दवाइयों की कमी)

सेवा में
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

दिनांक.....

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

-स्थित-अस्पताल के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं:-

1. दिनांक-से-के बीच अस्पताल के लिए कुल कितनी दवाएं ख़रीदी गईं. दवाइयों के ख़रीदने और उन्हें अस्पताल/ चिकित्सा केंद्र के स्टॉक में रखे जाने से संबंधित रजिस्टर की पिछले-महीने की प्रति उपलब्ध कराएं.
2. उपरोक्त समय के बीच कुल कितनी रकम की दवाइयां यहां आने वाले मरीजों को नि:शुल्क बांटी गईं? नि:शुल्क दवाइयां प्राप्त करने वाले मरीजों की संख्या बताएं और उनके नाम-पते आदि जिस रजिस्टर में लिखे जाते हैं, उस रजिस्टर की पिछले महीने की प्रति उपलब्ध कराएं.
3. अस्पताल के लिए दवाइयां खरीदने और वितरण के लिए नियुक्त अधिकारियों के नाम, पदनाम और संपर्क के पते उपलब्ध कराएं.
4. इस दौरान जिन एजेंसियों से दवाएं खरीदी गईं, उनका पूरा विवरण उनके नाम-पते के साथ उपलब्ध कराएं.
5. इस अस्पताल में मुख्य रूप से किन-किन बीमारियों से संबंधित दवाइयां नि:शुल्क वितरित की जाती हैं?
6. अस्पताल द्वारा दवाइयों का नि:शुल्क वितरण किस आधार पर किया जाता है?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में दस रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
टेलीफोन नंबर.....

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

दूध पीजिए नहीं, पहनिए

जर्मनी में दूध से बने हुए कपड़े जल्द ही बाज़ार में आने वाले हैं. ये त्वचा और पर्यावरण दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं. जर्मन डिज़ाइनर की इस नई रचना को अवॉर्ड भी दिया गया है. 28 साल की आंके डोमास्के ने दूध से कपड़े तैयार किए हैं. खास तौर से संवेदनशील त्वचा वाले लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. आंके ने इस खास कपड़े को नाम दिया है क्यू मिल्क्श. अंग्रेजी के अक्षर क्यू को क्वॉलिटी यानी गुणवत्ता के लिए इस्तेमाल किया गया है और जर्मन शब्द मिल्क्श यानी दूध. यह कपड़ा रेशम जैसा मुलायम है और धोने में सूती जितना आसान है. आंके ने अब तक केवल अपने फैशन हाउस के लिए ही इस कपड़े से ड्रेस बनाई हैं, लेकिन अगले साल से वह इन्हें बाज़ार में उतारना चाहती हैं. कई कंपनियों ने आंके की इस नई रचना में रुचि दिखाई है. आंके बताती हैं कि यह कपड़ा बनाने का विचार उन्हें तब आया, जब उन्होंने अपने पिता को कैंसर से लड़ते हुए त्वचा की बीमारियों के साथ देखा. कई लोगों को साधारण कपड़े पहनने के कारण एलर्जी हो जाती है, मैं केवल उनकी मदद करना चाहती थी. हालांकि दूध के प्रोटीन से 1930 से ही कपड़े बनते आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर कपड़ों में एक्रेलिक का इस्तेमाल होता है. आंके का कहना है कि वह पूरी तरह ऑर्गेनिक फाइबर तैयार करना चाहती थीं. यह कपड़ा बनाने के लिए दूध को उबाल कर प्रोटीन पाउडर बनाया जाता है. उसके बाद इस प्रोटीन से धागे बनाए जाते हैं. आंके बताती हैं कि इन धागों को इस तरह बुना जाता है कि यह रेशम जैसा दिखने लगे. कपड़ा बनाने के लिए केवल ऑर्गेनिक दूध का इस्तेमाल किया जाता है. यह ताजा होता है, जिसमें किसी भी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता. जर्मनी में ताजे दूध को पीने लायक़ नहीं माना जाता. इस तरह का एक किलो कपड़ा बनाने के लिए केवल दो लीटर दूध की ज़रूरत पड़ती है. इतना ही सूती कपड़ा तैयार करने के लिए कम से कम दस हज़ार लीटर पानी का इस्तेमाल होता है.

मिर्गी के साइड इफेक्ट

अज्ञानता, अंधविश्वास और जागरूकता न होना मिर्गी रोग के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, जिसके चलते आज विश्व में लगभग सात करोड़ और भारत में एक करोड़ 20 लाख लोग इस रोग से पीड़ित हैं. डॉ. नवनीत कुमार ने बताया कि अभी भी देश के ग्रामीण इलाक़ों और क़स्बों में लोग मिर्गी का दौरा पड़ने पर डॉक्टर के पास जाने के बजाय ओझा, मंदिरों और मजारों के चक्कर लगाते हैं. लोग इसे झाड़-फूंक से ठीक हो जाने वाला रोग मानते हैं और जब सब जगह से निराश हो जाते हैं. जब रोग बढ़ जाता है तो वह डॉक्टर के पास पहुंचते हैं. मिर्गी के अधिकतर रोगी इलाज से ठीक हो जाते हैं, लेकिन यह इलाज थोड़ा लंबा चलता है. इस रोग के लक्षणों के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें रोगी का अचानक बेहोश हो जाना, हाथ-पैर ऐंठ जाना, मुंह से झाग निकलना और रोगी का गिर जाना शामिल है. इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और वहां लोगों को पर्चे बांटकर और शिविर लगाकर जागरूक किया जा रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
जोखिम से दूर रहना बुद्धिमानी होगी या व्यर्थ के मनस्ताप बढ़ सकते हैं. किसी से कुछ उल्टा-सीधा कहने से आपकी पर्सनैलिटी पर विपरीत असर पड़ सकता है, इसलिए जुबान को काबू में रखना फ़ायदेमंद होगा. मन की चंचलता पर अंकुश रखकर ही नई समस्याओं का समाधान अच्छी तरह कर पाएंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
धर्म-कर्म के प्रति रुचि पैदा होगी और मनोविनोद बढ़ेगा. यह हफ्ता भाग्यवर्द्धक है, इसलिए इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और कोई भी पल व्यर्थ न गंवाएं. ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और आपकी योजनानुसार कार्य संपन्न होगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
लाभकारी गतिविधियों से सक्रियता रहेगी. निकट-दूर की यात्रा संभव है. संघर्ष और विवाद के नतीजे भी फ़ायदेमंद होते हैं. शरीर अस्वस्थ हो सकता है, खानपान पर ध्यान दें. बिना प्रशिक्षण भी आप बहुत जानकारी रखते हैं, परंतु किसी बिगड़े काम का विकल्प आपके पास नहीं है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
अधिक व्यग्रता और कार्यभार बढ़ने से मानसिक-शारीरिक शिथिलता पैदा हो सकती है. हफ्ते के मध्य तक कुछ टेंशन कम होगी. बिजनेस में लाभ होगा, साहित्य में रुचि बढ़ेगी और पढ़ाई-लिखाई में ख़ूब मन लगेगा. ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण सफलता धन लाभ कराएगी.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
एकाग्रता की प्रवृत्ति बनेगी. मानसिक दबाव घटने से शरीर भी चुस्त-दुरुस्त रहेगा. चतुराई और चालाकी हमेशा काम नहीं आती है. अधिक उतावली से कार्यक्षेत्र की परिस्थितियां ख़राब हो सकती हैं, इसलिए काम धीरे-धीरे ही निपटाएं.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
व्यवसाय में बढ़ोत्तरी होगी और प्रसन्नता बढ़ेगी. किसी विवाद को आगे बढ़ाने के बजाय ख़त्म करने से ही शांति मिलेगी. हफ्ते के मध्य तक ख़र्च के मौक़े सामने आएंगे. किसी अभद्र व्यक्ति के कारण मूड ख़राब हो सकता है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
शुभ कार्यों की प्रवृत्ति बनेगी और अच्छे समाचार मिलेंगे. हफ्ते का मध्य महत्वपूर्ण है. दोस्तों सहयोग बढ़ेगा. काम में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी. अपनी राय देने से बचे रहें. सप्ताहांत तक विसंगतियां समाप्त होती जाएंगी.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
श्रेष्ठजनों की सहानुभूति मिलेगी. शुभचिंतकों का सहयोग कार्य साधक होगा. यह हफ्ता अच्छा गुजरेगा, लेकिन मध्य में कुछ शरारती लोग आपके काम में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे. वरिष्ठ और अनुभवी लोगों की मदद से समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
हफ्ते के आरंभ में पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे. किसी प्रतिस्पर्धा से विजय का लाभ मिलेगा. हफ्ते के मध्य तक किसी कारण परेशानी होगी, लेकिन उसका हल निकलने से ख़ुशी भी उतनी ही मिलेगी.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
कामकाज की व्यस्तता से सुख-आराम प्रभावित होगा. जो जितना आपको लाभ दे सकता है, दे रहा है. सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील रहेंगे. किसी प्रकार की बहसबाज़ी से बचें और दूसरों की भावनाओं को चोट न पहुंचाएं.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. अगर आपके अंदर हुनर और गुणवत्ता है तो योजनाएं फ़ायदा पहुंचाने लगेंगी. अपने पुराने एवं क़रीबी दोस्तों से मुलाकात होगी. पारिवारिक असुविधाएं और घर से जुड़े कष्टों का हल खोजना आवश्यक होगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
किसी से कहासुनी न हो, यह ध्यान रहे. हफ्ता अच्छा व्यतीत होगा. हफ्ते का मध्य कुछ हटकर काम करने का है. कल की मौजमस्ती आपके आज पर टिकी है, तैयार रहें. आने-जाने में बाधा नहीं आएगी. पर्सनैलिटी का प्रभाव बनाए रखें. परिवार की उम्मीदें बढ़ेंगी. रिजल्ट अच्छा आएगा.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

मिस्र की जनता ने अगर धर्मनिरपेक्ष दलों को मौक़ा दिया होता तो आगे के लिए रास्ता निकल सकता था, लेकिन उसने ग़लत परंपरा का निर्वहन किया.

शीत युद्ध का बढ़ता ख़तरा

अमेरिका यह प्रस्ताव चीन का प्रभाव कम करने के लिए लाया था. इसके अलावा भी कई आर्थिक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच तनातनी है, जिससे साफ होता है कि दोनों देश आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए एक-दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं.

राजीव कुमार

सोवियत संघ के विघटन के बाद माना जाने लगा कि शीत युद्ध ख़त्म हो गया है. ऐसा इसलिए, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी खेमा कमज़ोर हो गया था. रूस सामरिक तौर पर तो मज़बूत था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह वैश्विक स्तर पर साम्यवाद के प्रसार के लिए मुहिम छेड़ सके. विश्व एकध्रुवीय हो गया था, जिसके केंद्र में अमेरिका ही था. लेकिन महज़ बीस साल बाद ही एक बार फिर शीत युद्ध का ख़तरा मंडराने लगा है. वैश्विक स्तर पर ऐसा परिदृश्य बन रहा है, लेकिन इस बार साम्यवाद का प्रतिनिधित्व रूस नहीं, बल्कि चीन कर रहा है. एक दूसरा अंतर यह भी है कि इस बार साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच टक्कर नहीं है, बल्कि अमेरिका यूरोप एवं कुछ अन्य देशों के सहयोग से अपना वर्चस्व बचाए रखने की कोशिश कर रहा है. दूसरी ओर चीन अपना वर्चस्व क़ायम करने के लिए गुटबंदी कर रहा है, जिसके लिए वह अमेरिका द्वारा उठाए गए क़दमों का विरोध करके अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा रहा है.

इस वक़्त अमेरिका और चीन कई मुद्दों पर आमने-सामने खड़े हैं. न केवल आर्थिक मुद्दों पर, बल्कि सामरिक तौर पर भी दोनों देश एक-दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. अमेरिका ने चीन की आर्थिक नीति की जमकर आलोचना की है. उसका कहना है कि चीन जानबूझ कर अपनी मुद्रा युआन की क़ीमत कम कर रहा है, ताकि उसका निर्यात बढ़ सके. चीन अपने लाभ के लिए जैसी आर्थिक नीति बना रहा है, उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं कहा जा सकता. हालांकि चीन ने अमेरिका की नाराज़गी पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं जताई है, लेकिन उसका तर्क है कि मुद्रा की क़ीमत धीरे-धीरे बढ़नी चाहिए, ताकि आर्थिक संतुलन न बिगड़े और बेरोज़गारी भी न बढ़े, क्योंकि ऐसा करने से वैश्विक विकास प्रभावित होगा. यही नहीं, यूरोप की मंदी से चीन के व्यापारियों को परेशानी तो है, लेकिन चीन की सरकार इस बात से ख़ुश है कि यूरोप और अमेरिका इससे आर्थिक तौर पर कमज़ोर होंगे.

एपेक की बैठक में भी दोनों देशों के बीच विवाद हुआ. एपेक देशों के बीच मुक्त व्यापार संबंधी अमेरिकी प्रस्ताव से चीन असंतुष्ट है. उसका कहना है कि अमेरिका उसे अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा है. अमेरिका यह प्रस्ताव चीन का प्रभाव कम करने के लिए लाया था. इसके अलावा भी कई आर्थिक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच तनातनी है, जिससे साफ होता है कि दोनों देश आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए एक-दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं. न केवल आर्थिक, बल्कि सामरिक तौर पर भी दोनों देश एक-दूसरे को मात देने की कोशिश में लगे हैं. अमेरिका ने आस्ट्रेलिया के साथ नौसैनिक समझौता किया है, जिसके तहत 2500 अमेरिकी पोत ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर तैनात किए जाएंगे. चीन ने प्रशांत महासागर में प्रभाव बढ़ाने के इस अमेरिकी प्रयास का विरोध किया है. चीन यह कभी नहीं चाहेगा कि उसके पास के क्षेत्रों में अमेरिकी नौसेना मौजूद रहे.

ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत को यूरेनियम देने की बात मान ली है. हालांकि उसके देश में ही इसका विरोध हुआ है, जबकि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के इस क़दम का स्वागत किया है. एक तरह से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस समझौते से भारत को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चीन से भारत को भी परेशानी है. अमेरिका ताइवान का समर्थन करता रहा है. उसने हाल-फ़िलहाल 4 बिलियन पाउंड के हथियार ताइवान को बेचे हैं, जिसका चीन ने जमकर विरोध किया. चीन भी गुटबंदी का कोई मौक़ा नहीं छोड़ रहा है. जब अमेरिका ने पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क से संबंध रखने के कारण धमकी दी तो चीन के उप प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया और किसी भी स्थिति में उसका साथ देने की बात कही.

हाल में नाटो सेना ने पाकिस्तानी क्षेत्र पर हमला किया, जिसमें 25 सैनिक मारे गए तो चीन ने उसे पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला बताया और पाक के साथ अपने संबंध मज़बूत करने की कोशिश की. ईरान के मुद्दे पर भी चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध किया है. उसने तर्क दिया कि ऐसे प्रतिबंधों से ईरान अलग-थलग पड़ जाएगा, लेकिन बात कुछ और है. यही नहीं, उसने लीबिया और सीरिया को भी गुपचुप तरीक़े से समर्थन दिया. यह भी उसकी कूटनीति का हिस्सा है. देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या आसियान, दक्षेस हो या कोई अन्य क्षेत्रीय संगठन, हर जगह पर चीन और अमेरिका आमने-सामने होते हैं. बात अगर चीन और अमेरिका के बीच की होती तो यह कोई गंभीर मुद्दा नहीं था, क्योंकि कोई भी देश हो, वह आगे बढ़ने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाना चाहेगा. अभी चीन और अमेरिका सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं. सामरिक तौर पर भी चीन किसी रूप में अमेरिका से कम नहीं है, लेकिन बात है गुटबंदी की. दोनों देश विश्व को दो गुटों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं. अमेरिका अपने समर्थकों की सूची बढ़ा रहा है और चीन अपने समर्थकों की. यही स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुई थी और पूरी दुनिया चालीस सालों तक युद्ध के ख़ौफ़ के साए में रही. चूंकि दोनों गुट परमाणु शक्ति संपन्न थे, इसलिए युद्ध नहीं हुआ, लेकिन डर तो बना ही रहा. इस गुटबंदी का असर अल्प विकसित और अविकसित देशों पर पड़ा, क्योंकि उन्हें किसी एक का सहयोग ही मिल पाया. हथियार हासिल करने की होड़ मच गई, जिससे विकास का पैसा हथियारों पर ख़र्च होने लगा. अगर वही स्थिति फिर आती है तो उसका खामियाजा विकासशील और अल्प विकसित देशों को ही भुगतना पड़ेगा. ऐसे में एक बार फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन को मज़बूत करने की ज़रूरत है, ताकि शीत युद्ध के ख़तरे से दुनिया को बचाया जा सके.

feedback@chauthiduniya.com

यह संकुचित लोकतंत्र है

मिस्र में संसदीय चुनाव शुरू हो गए हैं. तीन चरणों में होने वाले ये चुनाव जनवरी तक चलेंगे. प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उनके नतीजे भी आ चुके हैं. जो नतीजे सामने आए हैं, उन पर कई प्रश्न उठाए जा सकते हैं. हालांकि ये कोई अप्रत्याशित नतीजे नहीं हैं. पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी पार्टियों को चुनाव में ज़्यादा लाभ मिल सकता है, लेकिन फिर भी इस बात की उम्मीद ज़रूर थी कि लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाली मिस्र की जनता लोकतंत्र की मूल भावना को समझेगी, लेकिन वह इस उम्मीद पर खरी नहीं उतरी. इस चुनाव में धार्मिक दलों को धर्मनिरपेक्ष दलों की अपेक्षा काफी अधिक मत मिले. पहले दौर के इस चुनाव में 62 फ़ीसदी मतदान हुआ, जिसमें 65 फ़ीसदी वोट इस्लामी पार्टियों को मिले. मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी पार्टियों का बोलबाला देखने को मिला. फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी (एफजेपी) को 36.6 फ़ीसदी मत मिले. दूसरे नंबर पर भी इस्लामी पार्टी ही रही. अल नूर पार्टी को इस चुनाव में 24.4 फ़ीसदी मत मिले. वहीं दूसरी ओर जिस पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता की बात की, वह हाशिए पर चली गई. धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाली पार्टी इजिप्टियन ब्लॉक को मात्र 13.4 फ़ीसदी मत मिले. अन्य पार्टियों को भी छिटपुट मत मिले हैं.

अगर नतीजे पर ग़ौर किया जाए तो इस्लामी क़ानून की पैरोकारी करने वाले दलों को ही इस चुनाव में बहुमत मिलने की बात कही जा सकती है. हालांकि अभी दो चरणों के चुनाव बाक़ी हैं और जब तक उनके नतीजे नहीं आ जाते, तब तक पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि जनता धार्मिक पार्टियों के पक्ष में है या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक पार्टियों के. जो नतीजे सामने हैं, उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी भी मिस्र के लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं. लोकतंत्र एक आधुनिक शासन प्रणाली है, जिसके कुछ अपने मानदंड हैं. अगर इन मानदंडों पर किसी देश की जनता खरी नहीं उतरती तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि लोग वहां सही मायनों में लोकतंत्र चाहते हैं. लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर देश और जनता की भलाई के लिए तत्पर दल के पक्ष में मतदान करना. लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जिसमें हर वर्ग, समुदाय, धर्म के लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके. इस चुनाव के नतीजों पर नज़र डालने के बाद क्या ऐसा लगता है कि मिस्र की जनता सही मायनों में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने के लिए मानसिक तौर पर तैयार है. यह नहीं कहा जा सकता कि इस्लामी पार्टियों ने होस्नी मुबारक को पद से हटने को बाध्य करने के लिए कोई काम नहीं किया. तहरीर चौक पर उन्होंने भी प्रदर्शन किया था, लेकिन वहां के युवा, जो किसी दल के समर्थन के बिना इस तानाशाही के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे थे, वे क्या यही चाह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन तो हो, लेकिन उस परिवर्तन का आधार इतना संकुचित हो कि धर्म से ऊपर उठा न जा सके. अगर ऐसा है तो फिर इसे लोकतांत्रिक मानसिकता कैसे कहा जा सकता है. ऐसे लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कैसे हो सकती है.

ग़ौरतलब है कि मिस्र के संविधान निर्माण के लिए गठित की जाने वाली समिति का फ़ैसला भी इसी संसद द्वारा किया जाएगा. ऐसी स्थिति में उस संविधान पर धर्म का अच्छा-खासा असर होगा. उसमें किस वर्ग को कितना अधिकार दिया जाएगा, औरतों को किन-किन अधिकारों से वंचित रखा जाएगा, इसका तो केवल अनुमान लगाया जा सकता है. मिस्र की जनता ने अगर धर्मनिरपेक्ष दलों को मौक़ा दिया होता तो आगे के लिए रास्ता निकल सकता था, लेकिन उसने ग़लत परंपरा का निर्वहन किया. अब तो केवल यही संदेश जाएगा कि वोट लेने के लिए धर्म का सहारा लिया जाए, न कि विकास का. जिन दलों ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की थी, वे भी अपनी आगामी रणनीति पर विचार करेंगे कि अगर उन्हें सत्ता में आना है तो कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए. अगर जनता ने मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी इस्लामी पार्टियों पर केवल इतना दबाव डाला होता कि वे अपने धार्मिक एजेंडों को अलग कर दें तो भी वह लोकतंत्र के क़रीब मानी जा सकती थी. अगर ये दल जनता की बात न मानते तो उनके विरुद्ध मतदान करके यह साबित हो सकता था कि देश की जनता वास्तविक लोकतंत्र चाहती है, न कि लोकतंत्र के मुखौटे में लिपटा ऐसा तंत्र, जो धर्म के चंगुल से निकलने को तैयार न हो. इस चुनाव के परिणाम से यह साबित होता है कि आज भी लोग लोकतंत्र के मूल्यों को पहचान नहीं पाते हैं. एक तरह से देखा जाए तो मिस्र में जिस प्रकार की शासन प्रणाली आने वाली है, वह एक संकुचित लोकतंत्र है.

राजीव कुमार
feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
स्पेशल रिपोर्ट
नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया कि बीजिंग स्थित भारतीय राजनयिक इस मामले में घोर लापरवाही बरत रहे हैं. उन्होंने इस मामले में भारत सरकार की कोशिशों पर भी सवाल खड़े किए.

दिल्ली, 19 दिसंबर-25 दिसंबर 2011
चौथी दुनिया

श्री साई नाथ स्तवन मंजरी

साधु-असाधु सभी पा करुणा, दृष्टि समान सभी पर रखना.
पापी से कम प्यार न करते, पाप-ताप हर करुणा करते.

जो मलयुक्त है बहकर आता, सुरसरि जल में आन समाता.
निर्मल मंजूषा में रहता, सुरसरि जल नहीं वह गहता.

वही वसन इक बार था आया, मंजूषा में रहा समाया.
अवगाहन सुरसरि में करता, धुल कर निर्मल ख़ुद को करता.

सुदृढ़ मंजूषा है बैकुंठ. अलौकिक निष्ठा गंग तरंग.
जीवात्मा ही वसन समझिए, षड् विकार ही मैल समझिए.

जग में तव पद-दर्शन पाना, यही गंगा में डूब नहाना.
पावन इससे होते तन-मन, मल विमुक्त होता वह तत्क्षण.

दुःखद विवश हैं हम संसारी, दोष-कालिमा हम में भारी,
संत दरश केहम अधिकारी, मुक्ति हेतु निज बाट निहारी.

गोदावरी पूरित निर्मल जल, मैली गठरी भीगी तत्जल.
बन न सकी यदि फिर भी निर्मल, क्या न दोषयुक्त गोदावरी जल.

आप सघन हैं शीतल तरुवर, श्रांत पथिक हम डगमग पथ हम,
तपे ताप त्रय महाप्रखर तम, जेठ दुपहरी जलते भूकण.

ताप हमारे दूर निवारों, महा विपद से आप उबारों.
करों नाथ तुम करुणा छाया, सर्वज्ञात तेरी प्रभु दाया.

परम व्यर्थ वह छाया तरु है, दूर करे न ताप प्रखर है.
जो शरणागत को न बचाए, शीतल तरु कैसे कहलाए.

कृपा आपकी यदि नहीं पावें, कैसे निर्मल हम रह जावें,
पारथ-साथ रहे थे गिरधर, धर्म हेतु प्रभु पांचजन्य धर.

सुग्रीव कृपा से दनुज विभीषण, पाया प्राण तपाल रघुपति पद.
भगवत पाते अमित बड़ाई, संत मात्र के कारण भाई.

नेति-नेति हैं वेद उचरते, रूप रहित हैं ब्रह्म विचरते.
महामंत्र संतों ने पाएं, सगुण बनाकर भू पर लाएं.

दामा ए दिया रूप महार, रुक्मणि वर त्रैलोक्य आधार.
चोखी जी ने किया कमाल, विष्णु को दिया कर्म पशुपाल.

महिमा संत ईश ही जानें, दासनु दास स्वयं बन जावें,
सच्चा संत बड़प्पन पाता, प्रभु का सुजन अतिथि हो जाता.

ऐसे संत तुम्हीं सुखदाता, तुम्हीं पिता हो तुम ही माता.
सद्गुरु साई नाथ हमारे, कलियुग में शिरडी अवतारे.

लीला तिहारी नाथ महान, जन-जन नहीं पाएं पहचान.
जिव्हा कर न सके गुणगान, तना हुआ है रहस्य वितान.

तुमने जल के दीप जलाएं, चमत्कार जग में थे पाएं.
भक्त उद्धार हित जग में आए, तीरथ शिरडी धाम बनाए.

जो जिस रूप आपको ध्याए, देव स्वरूप वही तव पाए.
सूक्ष्म तत्व निज सेज बनाएं, विचित्र योग सामर्थ्य दिखाएं.

पुत्रहीन संतति पा जावें, रोग असाध्य नहीं रह जावें.
रक्षा वह विभूति से पाता, शरण तिहारी जो भी आता.

भक्तजनों के संकट हरते, कार्य असंभव संभव करते.
जग की चींटी भार शून्य ज्यों, समक्ष तिहारे कठिन कार्य त्यों.

साई सद्गुरु नाथ हमारे, रहम करो मुझ पर हे प्यारे.
शरणागत हूं प्रभु अपनाएं, इस अनाथ को न ठुकराएं.

प्रभु तुम हो राज्य राजेश्वर, कुबेर के भी परम अधीश्वर.
देव धनवंतरी तव अवतार, प्राणदायक है सर्वाधार.

बहु देवों का पूजन करते, बाह्य वस्तु हम संग्रह करते.
पूजा प्रभु की सीधी-साधी, बाह्य वस्तु की नहीं उपाधी.

जैसे दीपावली त्योहार, आए प्रखर सूरज के द्वार.
दीपक ज्योति कहां वह लाएं, सूर्य समक्ष जो जगमग होए.

जल क्या ऐसा भू के पास, बुझा सके जो सागर प्यास.
अग्नि जिससे उष्मा पाएं, ऐसी वस्तु कहां हम पाएं.

जो पदार्थ हैं प्रभु पूजन के, आत्मवश वे सभी आपके.
हे समर्थ गुरुदेव हमारे, निर्गुण अलख निरंजन प्यारे.

तत्व दृष्टि का दर्शन कुछ है, भक्ति भावना हृदय सत्य है.
केवल वाणी परम निरर्थक, अनुभव करना निज में सार्थक.

अर्पित करूं तुम्हें क्या साई, वह संपत्ति जग में नहीं पाई.
जग वैभव तुमने उपजाया, कैसे कहूं कमी कुछ दाता.

पत्र-पुष्पं विनत चढ़ाऊं, प्रभु चरणों में चित्त लगाऊं.
जो कुछ मिला मुझे हे स्वामी, करूं समर्पित तन-मन वाणी.

प्रेम अश्रु जलधार बहाऊं, प्रभु चरणों को मैं नहलाऊं.
चंदन बना हृदय निज गारूं, भक्ति भाव का तिलक लगाऊं.

शब्दाभूषण-कफनी लाऊं, प्रेम निशानी वह पहनाऊं.
प्रणय सुमन उपहार बनाऊं, नाथ कंठ में पुलक चढ़ाऊं.

आहुति दोषों की कर डालूं, वेदी में वह होम उछालूं.
दुर्विचार धूम्र यों भागे, वह दुर्गंध नहीं फिर लागे.

अग्नि सरिस हैं सद्गुरु समर्थ, दुर्गुण-धूप करें हम अर्पित.
स्वाहा जलकर जब होता है, तद्रूप तत्क्षण बन जाता है.

धूप-द्रव्य जब उस पर चढ़ता, अग्नि ज्वाला में है जलता.
सुरभि अस्तित्व कहां रहेगा, दूर गगन में शून्य बनेगा.

प्रभु की होती अन्यथा रीति, बनती कुवस्तु जलकर विभूति.
सद्गुण कुंदन सा बन दमके, शाश्वत जग बढ़ निरखे-परखे.

निर्मल मन जब हो जाता है, दुर्विकार तब जल जाता है.
गंगा ज्यों पावन है होती, अविकल दूषण मल वह धोती.

साई के हित दीप बनाऊं, सत्वर माया मोह जलाऊं.
विराग प्रकाश जगमग होवे, राग अंध वह उर का खोवे.

पावन निष्ठा का सिंहासन, निर्मित करता प्रभु के कारण.
कृपा करें प्रभु आप पधारें, अब नैवेद्य-भक्ति स्वीकारें.

भक्ति-नैवेद्य प्रभु तुम पाओ, सरस-रास-रस हमें पिलाओ.
माता, मैं हूं वत्स तिहारा, पाऊं तव दुग्धामृत धारा.

मन रूपी दक्षिणा चुकाऊं, मन में नहीं कुछ और बसाऊं.
अहम भाव सब करूं समर्पण, अंत: रहे नाथ का दर्पण.

विनती नाथ पुन: दुहराऊं, श्री चरणों में शीश नवाऊं.
साई कलियुग ब्रह्म अवतार, करो प्रणाम मेरे स्वीकार.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

चीन की जेल में भारतीय कारोबारी

डी आर आहूजा

दक्षिणी चीन के सेंजेन स्थित पोर्ट टाउन में 22 भारतीय व्यवसायी पिछले डेढ़ वर्षों से नारकीय ज़िंदगी गुजार रहे हैं. उन पर हीरों की तस्करी का आरोप है. इन कारोबारियों के परिवारीजनों ने भारत सरकार से अपील की है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और उनकी रिहाई सुनिश्चित कराए. परिवारीजनों ने सरकार से इस मामले में ट्रायल शुरू कराने का भी आग्रह किया. जानकारी के मुताबिक़ , 8 जनवरी, 2010 को 7.3 यूएस डॉलर की कस्टम ड्यूटी चोरी करने के आरोप में इन कारोबारियों को जेल भेज दिया गया था. ये सभी डेढ़ वर्ष से अधिक समय जेल में गुजार चुके हैं, जबकि इन्हें सज़ा भी नहीं सुनाई गई और न इस मामले में कोई सुनवाई हुई. पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया कि बीजिंग स्थित भारतीय राजनयिक इस मामले में घोर लापरवाही बरत रहे हैं. उन्होंने इस मामले में भारत सरकार की कोशिशों पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने बताया कि वे भारतीय उच्चायोग के संपर्क में हैं, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा है कि कोई गंभीर पहल नहीं की जा रही है. हालांकि चीन के सख्त क़ानूनों की वजह से स्थानीय व्यापारी इस बारे में कुछ भी खुलकर कहने से कतरा रहे हैं.

पीड़ित परिवारों ने बताया कि उन्होंने बीजिंग और संघाई में पैरवी के लिए वकीलों से बात की, लेकिन केस काफी उलझा हुआ है. सुनवाई की तारीख़ तय न होने से उन्हें न्याय मिलने में बेवजह देरी हो रही है. हालांकि चीन के विदेश मंत्री ने बीजिंग में दिए गए अपने बयान में कहा था कि इस मामले की स्थिति और गंभीरता पर सरकार विचार कर रही है.

पीड़ित परिवारों ने बताया कि उन्होंने बीजिंग और संघाई में पैरवी के लिए वकीलों से बात की, लेकिन केस काफी उलझा हुआ है. सुनवाई की तारीख़ तय न होने से उन्हें न्याय मिलने में बेवजह देरी हो रही है. हालांकि चीन के विदेश मंत्री ने बीजिंग में दिए गए अपने बयान में कहा था कि इस मामले की स्थिति और गंभीरता पर सरकार विचार कर रही है. उनके मुताबिक़, सेंजेन की अदालत में क़ानून के मुताबिक़ कार्रवाई की जा रही है और मामले की प्रगति रिपोर्ट से भारतीय अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है. एक अन्य बयान में यह भी कहा गया कि मामले में हुए ट्रायल के परिणाम समय-समय पर गुआंगझो स्थित भारतीय राजनयिक को भेजे गए हैं. चीनी अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में निष्पक्ष क़ानूनी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि हम उन लोगों की धार्मिक, सांस्कृतिक और मानवीय भावनाओं का सम्मान करते हैं. जबकि पीड़ित परिवारों का कहना है कि हमने चीनी अधिकारियों से कहा कि हम उचित जुर्माना देने को तैयार हैं, बावजूद इसके वे इस मामले में अनावश्यक देरी कर रहे हैं. चीन के सख्त कानूनों के चलते पीड़ित परिवारों को तरह-तरह की आशंकाएं सता रही हैं. उनका कहना है कि वे जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं और शाकाहारी हैं. जेल में बंद कई लोगों की तबीयत काफी ख़राब है. अगर जल्द उनकी रिहाई नहीं हुई तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता है. भारतीय अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पीड़ित परिवारों की यात्रा के लिए पांच बार व्यवस्था की, लेकिन चीन ने बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी. कई भारतीय कारोबारियों ने आरोप लगाया कि वे चीनी कंपनियों की ठगी के शिकार हुए. इसी बीच चीन सरकार ने 48 कंपनियों के ख़िलाफ़ फरेब करने संबंधी एक सूची जारी की है. कहा गया है कि कई फरेबी कंपनियों ने 1.8 मिलियन यूएस डॉलर की रकम विस्तारित की है. इस तरह के सबसे अधिक 29 मामले हेबई प्रांत में सामने आए. जबकि त्यानजेंन म्यूनिसिपल इलाके में 26 मामले सामने आए.

सूत्रों के मुताबिक़, विदेश एवं वाणिज्य मंत्रालय ने इस मामले की विवेचना करते हुए पाया कि ऐसे छह कारण हैं, जो इस तरह की धोखाधड़ी की जड़ में हैं:-

1-चीनी कंपनियों के आमंत्रण पर भारतीय कंपनियों के अधिकारी चीन यात्रा पर गए. यह प्रयास आपसी विश्वास बहाली के लिए किया गया. भारतीयों के वापस जाने से पहले चीनियों ने उनसे पैसों की मांग की, ताकि उनके लिए सांस्कृतिक महत्व की चीजें ख़रीदी जा सकें. इस पर भारतीय सहमत हो गए, लेकिन वापस लौटने पर उन्होंने सभी तरह की बातचीत बंद कर दी. जिस वजह से भारतीय कंपनियों को यात्रा और रहने-खाने के खर्च का नुक़सान उठाना पड़ा.

2-भारतीय कंपनियां बी-2 पोर्टल के जरिए चीनी निर्यातकों से मदद पाती हैं. निर्यातकों का कहना है कि भारतीय कंपनियों को कुल राशि एक बार में अग्रिम रूप से जमा करनी चाहिए.

3-भारतीय कंपनियों ने डील को अंतिम रूप देते हुए चीनी कारोबारियों से प्रोडक्ट के नमूने देने की बात कही थी. सभी ऑर्डरों के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया गया और कंसाइमेंट भारतीय तटों पर पहुंच गया. भुगतान सामान पहुंचने और लोडिंग के बाद किया गया. कस्टम द्वारा सभी प्रोडक्ट्स देखने के बाद ही उन्हें रिलीज किया गया.

4-इस बात पर सहमति हुई कि ख़रीददार (भारतीय) कंसाइनमेंट के समय एडवांस जमा कर दें. चीनी साझेदार को इस मामले में अग्रिम भुगतान में देरी हुई. उन्होंने बकाया रकम के भुगतान में हो रही देरी, लागत ख़र्च और आपूर्ति में परेशानी के लिए धमकी भी दी.

5-चीनी कंपनियां सौदे को अंतिम रूप देने से पहले भारतीय कंपनियों को नियमानुसार हिस्सा देती हैं. इस समझौते के तहत कुल लागत के लिए एक नोटराइजेशन भी तैयार किया गया. वापस लौटने पर भारतीयों ने इसके लिए अतिरिक्त भुगतान देने की बात कही.

6-समझौते से पहले भारतीयों को निर्देश दिया गया कि वे अग्रिम भुगतान या पूर्ण भुगतान बैंक खातों के ज़रिए अलग-अलग चीनी कंपनियों को दें, लेकिन उन्होंने धनराशि पाने के बाद कोई जवाब नहीं दिया. जब धनराशि मिलने के बावजूद जवाब न देने के बारे में पूछा गया तो चीन का कहना था कि कंपनियों के खाते में कोई धनराशि जमा नहीं हुई. बाद में वहां काम करने वाले लोगों ने नौकरी छोड़ दी.

उल्लेखनीय है कि हर साल कई देशों में जाने-अनजाने सैकड़ों भारतीयों को सजा भोगनी पड़ती है. गिरफ्तार किए गए लोगों की सुनवाई कई महीनों तक नहीं होती. रिहाई के इंतज़ार में कई कैदी जेल में दम तोड़ देते हैं. निश्चित तौर पर यह मामला मानवाधिकारों के हनन से जुड़ा है. चीन की जेल में बंद भारतीय कारोबारियों पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. भारत सरकार इस मामले में राजनयिक स्तर पर प्रयास करे और सुनवाई के लिए चीन सरकार पर दबाव बनाए.

feedback@chauthiduniya.com

कपिल सिब्बल चाहे जो भी सफ़ाई दें और जिस भी वजह की आड़ में सोशल साइट्स पर पाबंदी लगाने की कोशिश करें, लेकिन इतना साफ़ है कि यह सबकुछ अन्ना हजारे की मुहिम को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है.

अनंत विजय

फेसबुक नहीं, अन्ना का ख़ौफ़

अन्ना हजारे के ख़िलाफ़ सरकारी मुहिम के स्वयंभू अगुवा रहे कपिल सिब्बल लंबे समय से राजनीतिक परिदृश्य से ग़ायब थे. विवाद प्रिय नेता होने के बावजूद सिब्बल की मीडिया और विवाद से दूरी आश्चर्य चकित ही नहीं करती थी, बल्कि चौंका भी रही थी. अन्ना हजारे की जनलोकपाल की मुहिम और उनके अनशन के दौरान कपिल सिब्बल के अड़ियल रुख़ और ग़ैर राजनीतिक तरीक़ों ने सरकार की अच्छी ख़ासी किरकिरी करवाई थी. क़यास यह लगाए जा रहे थे कि उसके बाद सिब्बल को आलाकमान की तरफ़ से चुप रहने की सलाह दी गई थी. लेकिन एक बार जिसको विवादों का चस्का लग जाता है, वह ज़्यादा दिनों तक उससे दूर नहीं रह सकता है. कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से उसको साबित भी कर दिया. इस बार सिब्बल बहुत दूर की कौड़ी लेकर आए हैं. उन्होंने इस बार सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की क़वायद शुरू की है. सिब्बल ने फेसबुक, गूगल और अन्य सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के प्रतिनिधियों को अपने दफ्तर में बुलाकर उनको कंटेंट पर लगाम लगाने की हिदायत दी. अमेरिका के एक अख़बार के मुताबिक़, सिब्बल ने फेसबुक और अन्य कंपनी के प्रतिनिधियों को बुलाकर साफ़ तौर पर कहा कि साइट्स पर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह से जुड़ी आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों पर पाबंदी लगाने या फिर उसे रोकने का का इंतज़ाम करें. सिब्बल ने इसके साथ ही धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले चित्रों पर भी ऐतराज़ जताया और कहा कि इस तरह के आपत्तिजनक कंटेट वहां न हों. फेसबुक और अन्य कंपनियों ने सरकार की इस सलाह को मानने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि इन वेबसाइट्स पर यूजर्स अपनी सामग्री डालते हैं और अगर उस पर कोई पाबंदी लगाई गई तो इन वेबसाइट्स का मूल चरित्र ही ख़त्म हो जाएगा. इसके अलावा सिर्फ़ फेसबुक के पूरे विश्व में अस्सी करोड़ यूजर्स हैं और किसी भी कंपनी के लिए इतने बड़े उपभोक्ता वर्ग द्वारा डाले जाने वाले कंटेंट पर निगाह रखना मुमकिन नहीं है. ऐसा लगता है कि सिब्बल अपने इस क़दम से सरकार और पार्टी के आला नेताओं को साधने में लगे हैं. मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सैकड़ों आपत्तिजनक तस्वीरें नेट पर मौजूद हैं. क्या सिर्फ़ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाम लगाकर सिब्बल सोनिया और मनमोहन की आपत्तिजनक और अपमानजनक तस्वीरें हटवाने में कामयाब हो जाएंगे. लेकिन अचानक से कांग्रेसी मंत्री कपिल सिब्बल को लोगों की धार्मिक भावनाओं की फ़िक्र कहां से होने लगी. सिब्बल को अब धर्म और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरों की याद आ रही है, लेकिन उस वक़्त सिब्बल कहां थे, जब एम एफ हुसैन कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली पेंटिग्स बना रहे थे. उस वक़्त अगर हुसैन की पेंटिग्स उत्कृष्ट कला का एक नमूना और एक कलाकार की अभिव्यक्ति थी तो अब भी जो कुछ नेट पर किया जा रहा है या हो रहा है उसे भी उसी स्पिरिट में देखा जाना चाहिए. हुसैन का विरोध करने वाले अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला कर रहे थे, तो सिब्बल उस वक़्त क्या कर रहे हैं, इस पर भी कांग्रेस और लेफ्ट दोनों को सिर्फ़ विचार ही नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्मावलोकन भी करना चाहिए.

कपिल सिब्बल चाहे जो भी सफ़ाई दें और जिस भी वजह की आड़ में सोशल साइट्स पर पाबंदी लगाने की कोशिश करें, लेकिन इतना साफ़ है कि यह सबकुछ अन्ना हजारे की मुहिम को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है. जब अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अपने चरम पर था तो सरकार ने माना था कि वह सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नज़र नहीं रख पाई. लिहाज़ा इस बार सरकार ने अपनी इस भूल को सुधारने की कोशिश की और लगता है कि उसका ज़िम्मा दूरसंचार मंत्री होने के नाते सिब्बल को दिया गया है. फेसबुक और ट्विटर की ताक़त से सरकार अनजान नहीं है. चाहे वह मिस्र में तहरीर चौक पर लाखों लोगों के जुटने का मामला हो, चाहे वह ट्यूनीशिया में सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन हो, चाहे वह अमेरिका में चल रहा ऑक्योपॉय वॉल स्ट्रीट हो या फिर अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो, सब में फेसबुक और ट्विटर की बेहद अहम भूमिका रही है. उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो फेसबुक पर पिछले साल नवंबर में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पेज बनाया गया और सालभर में तक़रीबन साढ़े पांच लाख से ज़्यादा लोग उसके सदस्य बन गए और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. उसी तरह अगर हम ट्विटर को देखें तो जनलोकपाल के नाम से पिछले ही साल ट्विटर अकाउंट खोला गया. ट्विटर को रेटिंग देने वाली एजेंसी ने जनलोकपाल को एक मज़बूत ब्रांड के तौर पर रेटिंग दी और शुरुआत में ही उसे दसवें नंबर पर रखा. लेकिन महीने भर में ही जनलोकपाल टॉप फाइव में पहुंच गया. और तब से वह लगातार दूसरे–तीसरे नंबर पर बना रहता है. इसके बावजूद जनलोकपाल को फॉलो करने वाले महज़ दो लाख के क़रीब लोग हैं. सरकार के पास ये सब आंकड़ें तो जाते ही हैं. इन आंकड़ों और पिछले दो अनशन के दौरान अन्ना हजारे को मिले जनसमर्थन से यूपीए सरकार के कान खड़े हो गए. अन्ना हजारे एक बार फिर से अनशन करने के लिए हुंकार रहे हैं और दूसरे वह यह भी ऐलान कर चुके हैं कि अगर लोकपाल बिल पास नहीं होता है, तो वह आठ दिनों के अनशन के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ख़िलाफ़ चुनाव प्रचार करेंगे. उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की सक्रियता को लेकर कांग्रेस ख़ासी सतर्क है. इस वजह से अन्ना के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ख़िलाफ़ प्रचार के ऐलान और राजनेताओं के ख़िलाफ़ साइबर दुनिया में बन रहे माहौल को देखकर ही सिब्बल उस पर लगाम लगाने की मंशा पाले बैठे हैं. लेकिन सिब्बल जैसे क़ानून के जानकार यह भूल जाते हैं कि इस देश का संविधान प्री सेंसरशिप की इजाज़त नहीं देता. हमारे संविधान के मुताबिक़, कोई भी प्रचार प्रसार–दृश्य या श्रव्य अगर आपत्तिजनक दिखाई देता है, तो उसके ख़िलाफ़ शिकायत होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर बनाने वाले और उसे प्रचारित–प्रसारित करने वालों पर क़ानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी प्री सेंसरशिप की बात नहीं कही गई है.

प्री सेंसरशिप की बात दो बार कांग्रेस के शासनकाल में ही कही गई है. एक बार इमरजेंसी के दौरान, जब प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया था और इंद्रकुमार गुजराल को हटाकर विद्याचरण शुक्ला को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ज़िम्मेदारी दी गई थी. पद संभालने के बाद शुक्ला अपने दफ्तर में अख़बार के संपादकों को बुलाकर यह बताते थे कि अख़बार में क्या छापना है. इमरजेंसी लगने और पद संभालने के फ़ौरन बाद ही विद्याचरण शुक्ला ने 26 जून, 1975 को दिल्ली में अख़बार के संपादकों के साथ एक बैठक करके उन्हें सेंसरशिप समझाया था. कुछ अख़बारों ने उस दिन के अपने अंक में लिख दिया था कि आज के अख़बार की ख़बरें सरकार द्वारा सेंसर की गई हैं, जिस पर विद्याचरण शुक्ला ने संपादकों को ख़ूब खरी–खोटी सुनाई थी. सेंसरशिप का नतीजा कांग्रेस ने भुगता. इसलिए एक बार जब राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में फिर से सेंसरशिप की बात चली तो उसे लागू करने का साहस सरकार नहीं कर पाई. सिब्बल की सोशल मीडिया पर सेंसरशिप पर ही एक व्यक्ति ने ट्वीट किया– 1975 में भी एक वकील सिद्धार्थ शंकर रे ने श्रीमती गांधी को सलाह दी थी, जिसका नतीजा कांग्रेस ने भुगता और अब फिर से एक वकील सरकार की तरफ़ से मोर्चा संभाले है, तो दूसरी श्रीमती गांधी को इस बात पर ग़ौर करना चाहिए.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

हिंद स्वराज का सफ़रनामा

हिंदुत्व की विचारधारा से ओत–प्रोत किताब हिंद स्वराज की अनंत यात्रा में लेखक अजय कुमार उपाध्याय ने हिंद स्वराज की रोशनी में महात्मा गांधी के जीवन की विराट यात्रा का संक्षिप्त विवरण दिया है, जो साधारण व्यक्ति को भी महान कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और वह अपने आराध्य के प्रति उसी प्रकार लीन हो सकता है, जिस प्रकार महात्मा गांधी ने अंतिम क्षणों में अपने आराध्य का नाम लिया. बक़ौल लेखक, वास्तव में गांधी जी ने तो अपने जीवन भर की तैयारी को ही बोला था, जिसके संबंध में तुलसीदास जी ने भी लिखा है–जनम–जनम मुनि जतन कराहीं, अंत राम कहि आवत नाहीं. इस तरह महात्मा गांधी ने सत्य की खोज में ही अपने मोक्ष का मार्ग ढूंढ लिया था. सत्य रूप में हिंद स्वराज के आलोक में इनके जीवन की यात्रा से निकले वचन, संदेश बनकर सारी मानवता के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए हैं. वास्तव में इनकी यात्रा की सार्थकता जब तक पूरी नहीं होती, जब तक मुनष्यत्व की खोज पूर्ण नहीं होती. इस तरह मानवता की अनंत यात्रा में हिंद स्वराज एक प्रकाश की तरह सभी को मार्ग दिखाता रहेगा. यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना सौ वर्ष पूर्व था और आने वाली सदियों के लिए भी उतना ही प्रेरणादायी रहेगा.

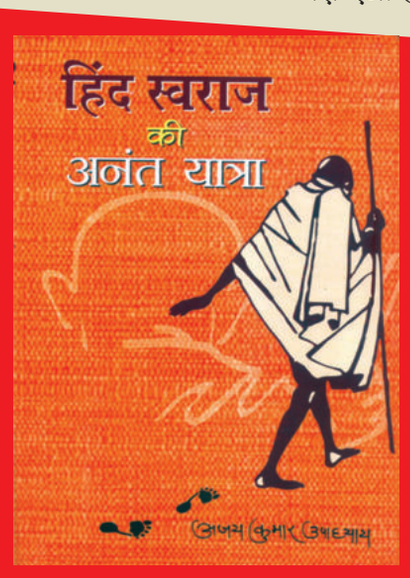

समीक्ष्य कृति : हिंद स्वराज की अनंत यात्रा
लेखक : अजय कुमार उपाध्याय
प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य : 250 रुपये

किताब के अध्याय राष्ट्रीय पुनर्जागरण एवं नवचेतना, हिंद स्वराज की पृष्ठभूमि, कांग्रेस की प्रारंभिक यात्रा, बंग–भंग और राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्र की अवधारणा और हम, सभ्यता का सार्थक पक्ष, शिक्षा, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, हिंदू–मुस्लिम एकता के प्रयास, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऐतिहासिक वार्ता, भारत में सामाजिक क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध और नेहरू, स्वराज्य क्यों और कैसे, पार्लियामेंटरी स्वराज्य और विभाजन, सामाजिक सरोकार गांधी और संघ आदि में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है. मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को उनकी दयनीय दशा से उबारने के लिए संघर्षरत थे. उन्होंने 9 अक्टूबर, 1909 को लार्ड एमपीथील के नाम पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने हिंद स्वराज की आधारशिला रखी. उन्होंने लिखा कि शासकों का कर्तव्य है कि वे जन आकांक्षाओं के अनुरूप शासन करें. अगर वे अपने प्राथमिक कर्तव्यों को पूरा करने में असफल होते हैं, तो जनता को इस बात का अधिकार है कि वे उसे पहचाने व सहयोग करने से इंकार कर दे. महात्मा गांधी का अंत:करण पिछले पचास वर्षों से गूंज रहे स्वराज्य के उन उद्घोषों के प्रति जागृत था, जिसमें 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसी न किसी रूप में अपनी आवाज़ लिए गूंज रह था, जो महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के और पंजाब में रामसिंह कूका के नेतृत्व में देशभक्ति का भाव भर रहा था. इसी बीच 1885 में मुंबई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसके दादाभाई नौरोजी उपसभापति चुने गए. एओ ह्यूम ने 27 दिसंबर, 1885 को कांग्रेस की स्थापना की. कांग्रेस के संबंध में गांधी जी लिखते हैं–देखिए, कांग्रेस ने अलग–अलग जगहों पर हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके उनमें हम एक राष्ट्र हैं, ऐसा जोश पैदा किया. कांग्रेस पर सरकार की कड़ी नज़र रहती थी. महसूल का हक़ प्रजा को होना चाहिए, ऐसी मांग कांग्रेस ने हमेशा की है. जैसा कनाडा में है, वैसा स्वराज्य हमें चाहिए, उससे बढ़कर इसका कोई स्वराज्य है या नहीं, यह सवाल अलग है. मुझे दिखाना तो इतना ही है कि कांग्रेस ने हिंद को स्वराज्य का रस चखाया है. इसका यश कोई और लेना चाहे तो वह ठीक न होगा, और हम भी ऐसा मानें तो बेक़दर ठहरेंगे. इतना ही नहीं, बल्कि जो मक़सद हम हासिल करना चाहते हैं, उसमें मुसीबतें पैदा होंगी.

किस तरह हिंदुत्व को ख़त्म करने और ईसाइयत को बढ़ावा देने के लिए लार्ड मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किए, उसे भी लेखक ने पेश किया है. मैकाले ने अंग्रेजी भाषा द्वारा अपने ईसाईयत के लक्ष्य को घोषित किया था–थोड़ी सी पाश्चात्य शिक्षा से ही बंगाल में मूर्ति पूजने वाला कोई नहीं रह जाएगा. तभी तो अलैक्जेंडर डफ भारत में धर्म प्रचार के लिए आया, लेकिन सबसे अधिक प्रचार उसने अंग्रेजी का किया था. चर्चों की एक सभा में 1835 में डफ ने घोषणा की थी, जिस–जिस दिशा में पाश्चात्य शिक्षा प्रगति करेगी, उस–उस दिशा में हिंदुत्व के अंग टूटते जाएंगे और अंत में जाकर ऐसा होगा कि हिंदुत्व का कोई भी अंग साबुत नहीं रहेगा. उन्हीं लार्ड शाफ्ट ने कहा था–जो भी हिंदू ईसाई परमात्मा का ध्यान करेगा, वह ब्रह्मा और विष्णु को स्वयंमेव भूल जाएगा. लार्ड विलियम बैंटिक ने 1835 में लार्ड मैकाले की योजना की घोषणा करते हुए ऐलान किया कि भारतवर्ष में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगी.

चूंकि लेखक दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक हैं, इसलिए संघ की विचारधारा इस पुस्तक के हर अध्याय में प्रकट होती है. पुस्तक की प्रस्तावना संघ के सरकार्यवाह भय्याजी जोशी ने लिखी है. वह लिखते हैं–हिंद स्वराज ने पाश्चात्य सभ्यता की बुनियाद में उस समय जिन ख़ामियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया था, वे ख़ामियां ही पूरे पश्चिमी जगत को आज सामाजिक–आर्थिक स्तर पर संकटग्रस्त किए हुए हैं. इसलिए पश्चिम के विद्वान हिंद स्वराज की प्रासंगिकता को स्वीकारते हैं, क्योंकि हिंद स्वराज ने मानवीय पक्ष को सभ्यता का केंद्र मानते हैं. लेखक ने किताब की भूमिका में उन लोगों का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने इस किताब में अपना योगदान दिया है.

फ़िरदौस ख़ान
firdaus@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
सत्य के मेरे प्रयोग

लेखक
मोहनदास करमचंद गांधी

प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन

मूल्य
450 रुपये

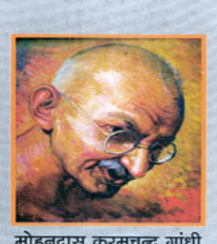

यह किताब महात्मा गांधी की आत्मकथा है. इसमें उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया हैं.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

ब्राईट® की सभी के लिए उपयोगी पुस्तकें

FROM THE HOUSE OF : BRIGHT® Career's® BOOKS | COMPETITION REFRESHER | SCIENCE REFRESHER | G.K. GENERAL KNOWLEDGE REFRESHER

BRIGHT PUBLICATIONS®
Publishers of INDIA'S LARGEST SELLING Competition & School Books
2767, Kucha Chellan, Darya Ganj, New Delhi-110 002 (India) —— (ESTD. 1968)
Ph.: 011-64632226 & 3226, 23282226 & 3226 Fax: 011-23269227 Telefax: 64633226
E-mail: sales@brightpublications.com | Web Site: http://www.brightpublications.com

FOR VPP ORDERS, SEND ₹ 25/- AS ADVANCE & FOR FREE CATALOGUE WRITE TO US

होटल के कमरों से लेकर आपके घरों, थिएटरों और कारों तक इनकी आसान पहुंच रहती है. ये ऊपर से साफ दिखाई देने वाली चादरों एवं गद्दों तक छिपे होते हैं.

स्टाइलिश न्यू सुजुकी जीएस 150-आर

भारतीय बाज़ार में 150 सीसी की रेंज में यह पहली बाइक है, जिसे 6 गियरों के साथ पेश किया गया है.

इसका स्टाइलिश लुक और पावर इंजन इसे स्पोर्ट्स बाइक की श्रेणी में खड़ा करता है.

सुजुकी ने जीएस 150-आर को कुछ वक़्त पहले ही भारतीय बाज़ार में उतारा है. अब कंपनी ने इसका नया वर्जन पेश किया है. नई सुजुकी की हेडलाइट पुराने मॉडल के मुक़ाबले ज़्यादा आकर्षक बना दी गई है.

भारतीय बाज़ार में वर्ष के अंत में ग्राहकों को रिझाने के लिए वाहन निर्माता इस समय अपने वाहनों का फेश लिफ्टेड वर्जन पेश कर रहे हैं यानी मॉडलों में थोड़ा–बहुत बदलाव करके बाज़ार में उतार रहे हैं. सुजुकी ने जीएस 150–आर को कुछ वक़्त पहले ही भारतीय बाज़ार में उतारा है. अब कंपनी ने इसका नया वर्जन पेश किया है.

नई सुजुकी की हेडलाइट पुराने मॉडल के मुक़ाबले ज़्यादा आकर्षक बना दी गई है. ग्राहकों के लिए बाइक के रंगों के चयन के विकल्प भी बढ़ा दिए गए हैं. भारतीय बाज़ार में 150 सीसी की रेंज में यह पहली बाइक है, जिसे 6 गियरों के साथ पेश किया गया है. यह चलाने में आसान है. इसका स्टाइलिश लुक और पावर इंजन इसे स्पोर्ट्स बाइक की श्रेणी में खड़ा करता है. सुजुकी जीएस–150 के नए मॉडल की खास बात यह है कि कंपनी ने इसके फीचर्स में इज़ाफ़ा किया है, लेकिन इसकी क़ीमत पुराने मॉडल जितनी है. यह बाइक 66,695 रुपये में मिलेगी. कंपनी को उम्मीद है कि नया मॉडल दोपहिया वाहनों की बिक्री में इज़ाफ़ा करेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बिस्तर रखें साफ

एलजी ने एक नया प्रोडक्ट बाज़ार में उतारा है. उसका नया बैडिंग क्लीनर बिस्तर को पूरी तरह स्वच्छ बनाए रखने का भरोसा देता है. यह हैंडहैल्ड डिवाइस गद्दे के कोनों एवं घुमाव आदि में छिपे ख़तरनाक कीटों और एलर्जेंस को सोखने में कारगर हैं.

अपने बच्चों को कीटों और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों के बीच सोने से आपको बचाना होगा. क्या आप जानते हैं कि आपके घरों में आम तौर पर स्वच्छ दिखाई देने वाले बिस्तरों में ऐसे सूक्ष्म कीट और एलर्जेंस हो सकते हैं, जो बच्चे को बीमार कर सकते हैं. एलर्जी पैदा करने वाले तत्व कहीं भी हो सकते हैं. होटल के कमरों से लेकर आपके घरों, थिएटरों और कारों तक इनकी आसान पहुंच रहती है. ये ऊपर से साफ दिखाई देने वाली चादरों एवं गद्दों तक छिपे होते हैं. इनकी वजह से आपके परिवारीजनों को एलर्जी, दमा, खांसी–जुकाम और श्वांस संबंधी शिकायतें हो सकती हैं. इससे बचने के लिए एलजी ने एक नया प्रोडक्ट बाज़ार में उतारा है. उसका नया बैडिंग क्लीनर बिस्तर को पूरी तरह स्वच्छ बनाए रखने का भरोसा देता है. यह हैंडहैल्ड डिवाइस गद्दे के कोनों एवं घुमाव आदि में छिपे ख़तरनाक कीटों और एलर्जेंस को सोखने में कारगर हैं.

इस तरह बिस्तर को पूरी तरह एलर्जेंस और कीटों से मुक्त किया जा सकता है. इसमें लगा ऑटोमेटिक टच हैंडल संपूर्ण साफ–सफाई सुनिश्चित करता है. इसमें थ्री लैवल डीप क्लीनिंग की व्यवस्था है. इसका शक्तिशाली फिल्टर धूल के बारीक कणों को भी सोखने में सक्षम है, जिससे आपको मिलता है साफ और सेहतमंद घर.

इसके पहले लेवल में है शक्तिशाली वाइब्रेशन, जो हर मिनट 4000 शक्तिशाली वाइब्रेशन के चलते धूल के कण और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं का सफाया करता है. दूसरा लेवल है स्मूद पिकअप, जिसके पिकअप ब्रश के चलते बिस्तरों पर पड़े महीन बाल आदि भी आसानी से निकाले जा सकते हैं और गद्दे को भी नुक़सान नहीं पहुंचता. इस वैक्यूम क्लीनर में हाइजिन यूवी स्टर्लाइज़ेशन स्टेशन भी है, जो बैडिंग की सफाई के बाद इसके भीतर लगे यूवी लैंप क्लीनर के निचले भाग में जमा बैक्टीरिया आदि को स्टर्लाइज़ कर देता है, ताकि इनसे संक्रमण न फैले. एलजी बैडिंग क्लीनर घरों के लिए एक बढ़िया विकल्प है और यह आपके बच्चों के लिए सुरक्षित एवं सेहतमंद नींद सुनिश्चित करने का भरोसा लेकर आया है. यह कॉम्पैक्ट होने के साथ–साथ दिखने में भी आकर्षक है. इस खास बैडिंग क्लीनर की क़ीमत 12,990 रुपये है.

जेब्रोनिक्स साउंड मॉन्सटर

जेब–एसडब्लयू–4100 आरयूसी इस्तेमाल में बेहद सुविधाजनक है. रिमोट कंट्रोल से सभी सुविधाएं संचालित करने की सुविधा है. बास/वॉल्यूम कंट्रोल गाने की आवाज़ को मधुर, स्पष्ट एवं आनंददायक बनाता है.

संगीत प्रेमियों के लिए टॉप नॉच इंफोट्रॉनिक्स ने 2.1 मल्टी मीडिया स्पीकर सेट जेब–एसडब्ल्यू–4100 आरयूसी यानी साउंड मॉन्सटर पेश किए हैं. ये नए मॉडल 5 इंच पोर्टेड सब–वूफर और 4 इंच चुंबकीय कवच वाले सैटेलाइट से लैस हैं. जेब–एसडब्ल्यू–4100 आरयूसी स्पीकर सेट में फ्रंट माउंटेड वॉल्यूम और सब–वूफर पर बास लेवल कंट्रोल की सुविधा है. इसमें किसी भी एमपी 3 प्लेयर और सेल फोन के लिए 3.5 एमएम इनपुट है. हाई ग्लॉस, ब्लैक साटन फिनिश इस स्पीकर को जमाने के मुताबिक स्टाइलिश बनाता है. जेब–एसडब्लयू–4100 आरयूसी इस्तेमाल में बेहद सुविधाजनक है. इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए रिमोट कंट्रोल से सभी सुविधाएं संचालित करने की सुविधा है. बास/वॉल्यूम कंट्रोल गाने की आवाज़ को मधुर, स्पष्ट एवं आनंददायक बनाता है. इसकी सबसे बड़ी ख़ूबी संभवत: एसडी/यूएसबी इनपुट सुविधा है, जिसकी बदौलत यूजर मेमोरी कार्ड या डेटा स्टोरेज उपकरण से सीधे म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं यानी पेनड्राइव या एसडी कार्ड को प्लग–इन करके सीधे गाने का आनंद उठा सकते हैं. जेब–एसडब्ल्यू–4100 आरयूसी खास तौर पर डिज़ाइन किया गया पीसी मल्टी मीडिया स्पीकर सिस्टम है, जिसमें कनेक्टर,अतिरिक्त इनपुट, आउटपुट पोर्ट और रिमोट कंट्रोल की सुविधा है. अगर आप इन ख़ूबियों से लैस 2.1 स्पीकर सिस्टम की तलाश में हैं तो आपको निश्चित रूप से इसे लेने पर विचार करना चाहिए. ट्रेंडी डिज़ाइन वाला जेब–एसडब्ल्यू–4100 आरयूसी आधुनिक आलमारी या मेज की शोभा बढ़ाने वाला स्पीकर है. यह एक साल की वारंटी के साथ 1950 रुपये में उपलब्ध है.

होंडा सीविक का डीजल मॉडल

पेट्रोल की क़ीमतों में आई उछाल के कारण भारतीय बाज़ार में पेट्रोल कारों की मांग कम हो गई और ग्राहकों का रुख तेजी से डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक कारों की तरफ़ बढ़ा है. भारतीय बाज़ार में खासकर डीजल कारों की मांग में लगातार इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है. कार निर्माता भी अब दूसरे ईंधन के विकल्पों में सफलता तलाशने लगे हैं. जानी-मानी जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा भी भारतीय बाज़ार में अपनी पहली डीजल कार उतारेगी. उसने अपना पहला 1.6 लीटर आई-डीटेक डीजल इंजन पेश किया है. यह डीजल इंजन वह अपनी सिडान कार सीविक में इस्तेमाल करेगी. होंडा की यह शानदार कार सीविक भारतीय बाज़ार में मौजूद प्रीमियम सिडान कार रेंज में एक बेहतर कार है. इसका डीजल संस्करण उतारने के बाद इसकी बिक्री बढ़ जाएगी. इस नए डीजल इंजन की खास बात यह है कि इसका वजन कुल 170 किलोग्राम है. कम वजन का यह इंजन कार को बेहतर माइलेज देगा. कंपनी फिलहाल इस इंजन का प्रयोग पहले सीविक में करेगी, उसके बाद उसकी योजना इसका प्रयोग शानदार सिडान सिटी में भी करने की है.

लिनोवो के प्रोफेशनल डेस्कटॉप

लैपटॉप और डेस्कटॉप के अपने अलग फ़ायदे और नुक़सान हैं. जहां लैपटॉप को कैरी करना आसान होता है, वहीं डेस्कटॉप में लैपटॉप के मुक़ाबले बेहतर स्पीड और परफार्मेंस मिलती है. यही वजह है कि केवल भारत ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में डेस्कटॉप की मांग लगातार बनी हुई है. लिनोवो ने पावरफुल डेस्कटॉप की रेंज में अपने दो नए खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं. लिनोवो थिंक सेंटर ऐज 71 जेड और लिनोवो थिंक सेंटर ऐज 91 जेड नामक दोनों लिनोवो पीसी काफी यूजर फ्रेंडली होने के साथ तकनीकी रूप से उन्नत हैं. लिनोवो का पहला पीसी थिंक सेंटर ऐज 71 जेड में इंटल कोर आई 3–2100 प्रोसेसर के साथ जेन्यून 64 बिट का विडों 7 प्रोफेशनल ओएस पर रन करता है. डेस्कटॉप का स्क्रीन साइज भी 20.0 इंच का है, जिससे यूजर को मूवी और पिक्चर देखते समय अच्छा व्यू मिलता है. डिवाइस में इंटल का हाईडेफिनेशन ग्राफिक कार्ड सपोर्ट दिया गया है, जिससे पीसी में हाईडेफिनेशन गेम और वीडियो देखे जा सकते हैं. लिनोवो डेस्कटॉप 71 जेड में 500 जीबी की 7200 हार्डड्राइव दी गई है, जो फास्ट ब्राउजिंग स्पीड प्रोवाइड करती है. 71 जेड में इनबिल्ड रैम की बात करें तो पीसी में 1333 मेगाहट्र्ज की 2 जीबी हार्डडिस्क–10600 डीडीआर–3 एचडी रैम दी गई है.

लिनोवो के दूसरे पीसी 91 जेड में इंटल का सेकेंड जेनरेशन कोर आई 7 प्रोसेसर दिया गया है. 91 जेड पीसी में 32 बिट की जगह 64 बिट का विडो 7 प्रोफेशनल ओएस पड़ा हुआ है. इसकी स्क्रीन भी पिछले पीसी से थोड़ी बड़ी है. इसमें 21.5 इंच का डिस्प्ले है, जो फुल एचडी क्वालिटी की पिक्चर प्रोवाइड करता है. कंपनी अपने दोनों डेस्कटॉप कंप्यूटर पर 3 साल की वारंटी भी दे रही है. 91 जेड के अन्य कनेक्टिविटी फीचरों में 6 इन 1 कार्ड रीडर, 2 मेगा पिक्सल कैमरा, 1 जीबी का वॉयरलेस एएमडी रेडियॉन ग्राफ्रिक कार्ड आदि शामिल हैं, जो यूजर के मल्टीमीडिया अनुभव को बढ़ाएंगे. ये दोनों डेस्कटॉप कंप्यूटर सभी लिनोवो स्टोर में उपलब्ध हैं. लिनोवो थिंक सेंटर ऐज 71 जेड की क़ीमत 28,000 और लिनोवो थिंक सेंटर ऐज 91 जेड की क़ीमत 45,000 रुपये है.

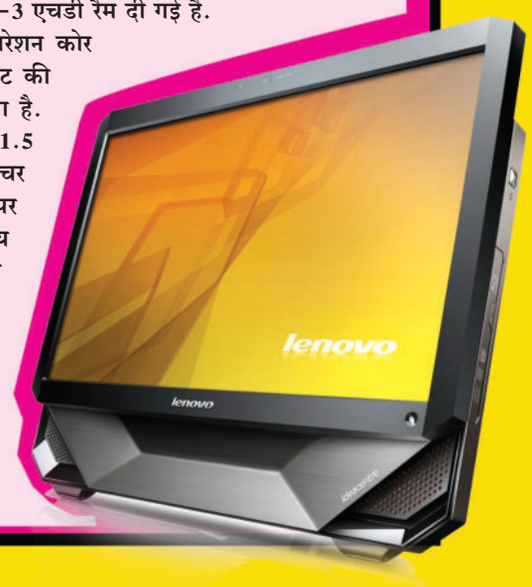

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

रोनाल्डो भारत में

पेले, माराडोना, लियोनल मेस्सी और अब रोनाल्डो. तीन महान फुटबॉल खिलाड़ियों के बाद अब रोनाल्डो भी भारत आ रहे हैं. वह आगामी 15 जनवरी को कोलकाता में प्रदर्शनी मैच खेलेंगे. यह मैच सिक्किम भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए खेला जा रहा है. इस मैच की योजना बाईचुंग भूटिया ने बनाई है. इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी भाग ले सकते हैं. इसमें बॉलीवुड के कई अभिनेता भी शामिल होंगे. यह मैच भारतीय फुटबाल खिलाड़ी संघ के अंतर्गत खेला जाएगा.

पेस अलग हुए थे: भूपति

टेनिस स्टार महेश भूपति का कहना है कि उनकी और लिएंडर पेस की जोड़ी टूटने के पीछे की वजह ख़ुद पेस हैं. अलग होने का फ़ैसला पेस का था. पेस मानते थे कि वह साथ खेलने के लिए बहुत उम्रदराज हैं और एकजुट नहीं हो पा रहे हैं. नौ साल बाद भूपति और पेस एकजुट हुए थे और उनका इरादा अगले साल ओलंपिक में साथ खेलने का था, लेकिन वे इस सत्र के अंत में अलग हो गए. भूपति अब रोहन बोपन्ना के साथ खेलेंगे और पेस चेक गणराज्य के रॉडेक स्टीपानेक को अपना जोड़ीदार बनाएंगे. भूपति ने कहा कि इस अलगाव को समझा पाना उनके लिए मुश्किल है.

फुटबॉलर सॉकरेट्स नहीं रहे

ब्राज़ील फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान सॉकरेट्स का निधन हो गया. वह 57 साल के थे. डॉक्टरों के मुताबिक़ , सॉकरेट्स आंत संबंधी संक्रमण से पीड़ित थे. उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. सॉकरेट्स दुनिया के बेहतरीन मिड फील्डरों में से एक थे. फुटबॉल के दो विश्वकपों में वह ब्राज़ील की ओर से खेले. कुल मिलाकर उन्होंने 1979 और 1986 के बीच 60 मैच खेले और 22 गोल किए. सॉकरेट्स ने माना था कि उन्हें अपने खेलने के दिनों में शराब को लेकर समस्या थी. वह धूम्रपान की अपनी लत के लिए भी जाने जाते थे. उन्हें अगस्त और सितंबर में पाचन संबंधी परेशानी के चलते दो बार अस्पताल ले जाया गया.

बोपन्ना-कुरैशी अलग हुए

पेस-भूपति के बाद अब भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और पाकिस्तान के टेनिस खिलाड़ी एसाम उल-हक कुरैशी की जोड़ी भी टूट गई है. भारत-पाक सद्भावना के तौर पर देखी जा रही यह जोड़ी अब साथ-साथ नहीं खेलेगी. बोपन्ना अब महेश भूपति के साथ मैदान में उतरेंगे. बोपन्ना-कुरैशी की जोड़ी हाल में खेल गए वर्ल्ड टूर फ़ाइनल्स के तीनों मैच हार गई थी. दोनों खिलाड़ी 16 साल की उम्र में मिले थे और अब दोनों 30 साल के हो रहे हैं.

मैकग्रा बनना चाहते हैं उमेश

तेज गेंदबाज़ उमेश यादव भारत के ग्लेन मैकग्रा बनना चाहते हैं. वेस्टइंडीज के ख़िलाफ़ अपनी ही धरती पर शानदार गेंदबाज़ी कर रहे उमेश पूर्व आस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ मैकग्रा की तरह अपनी गेंदबाज़ी में लाइन और लेंथ लाना चाहते हैं. यादव का कहना है कि मैकग्रा उनके हीरो हैं, वह उनसे प्रेरित हैं और उनकी तरह गेंदबाज़ी करना चाहते हैं. आस्ट्रेलियाई दौरे के लिए चुने गए यादव मानते हैं कि उन्हें वहां के विकेटों से तालमेल बैठाने में मदद मिलेगी, हालांकि भारतीय विकेट वहां की तुलना में भिन्न हैं.

टीम के साथ जासूस

ब्रिटेन के एक पूर्व रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों का इस्तेमाल ब्रिटेन में जासूस भेजने के लिए कर सकता है. इस पूर्व मंत्री ने अपनी चेतावनी में कहा कि रूसी खिलाड़ियों के सुरक्षाकर्मियों के रूप में कुछ जासूस भी ब्रिटेन में दाखिल हो सकते हैं. उधर रूसी प्रधानमंत्री ब्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने इस दावे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रूस ऐसी किसी भी राय की परवाह नहीं करता.

हॉकी कोच दु:खी

भारतीय हॉकी टीम के कोच माइकल नोब्स दु:खी हैं. वजह, दक्षिण अफ्रीका में संपन्न एफआईएच चैंपियंस चैलेंज वन हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में बेल्जियम से मिली हार. इस हार से वह निराश थे, उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने अंतिम क्षणों में हाथ आई बाजी गंवा दी. खेल के पहले हाफ में भारत 1-0 और दूसरे हाफ में एक समय 3-1 से आगे था, लेकिन बेल्जियम ने आख़िरकार 4-3 से जीत दर्ज करते हुए खिताब जीत लिया. इसके साथ ही भारत ने वर्ष 2005 के बाद पहली बार चैंपियंस ट्राफी के लिए क्वालीफाई करने का मौक़ा गंवा दिया. नोब्स ने कहा कि मैच पूरी तरह हमारे नियंत्रण में था, लेकिन हम जीती बाज़ी हार गए. नोब्स ने कहा कि टीम को इस टूर्नामेंट से कई अच्छी बातें सीखने को मिली हैं, ओलंपिक क्वालीफायर से पहले उसे अपने प्रदर्शन में सुधार की ज़रूरत है.

मुआवज़ा लो, फिर खेलो

पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ ने अपने क्रिकेट बोर्ड से कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज तभी खेली जाए, जब वह 2009 में पाकिस्तान दौरा रद्द होने का मुआवज़ा अदा कर दे. लतीफ ने कहा, मैं बोर्ड अधिकारियों के भारत के साथ द्विपक्षीय मैच शुरू होने के काफी बयान पढ़ रहा हूं. मुझे नहीं लगता कि हमें तब तक भारत का दौरा करना चाहिए, जब तक वह 2009 में रद्द हुए दौरे का मुआवज़ा नहीं दे देता. भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत हमें ही क्यों करनी चाहिए, जबकि उसने हमारे खिलाड़ियों को पिछले तीन चरणों से आईपीएल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी. इससे हमारे क्रिकेट को क्या फ़र्क़ पड़ेगा, बल्कि हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और हमारे खिलाड़ियों की दुनिया भर में मांग है.

पाकिस्तान की जीत

स्पिनरों के जलवे से पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश को 58 रनों से शिकस्त देकर सीरीज पर 3-0 से क़ब्ज़ा कर लिया. पाकिस्तानी टीम चटगांव स्थित जाहुल अहमद चौधरी स्टेडियम में 177 रनों के स्कोर पर सिमट गई थी, लेकिन उसके स्पिनरों ने स्पिन की मुफीद उछाल भरी और शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 119 रनों में समेट दिया. शोएब मलिक ने अपना 200वां वन डे खेलते हुए चार ओवरों में छह रन देकर तीन विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद हफीज ने 27 रन देकर तीन विकेट हासिल किए, जिससे बांग्लादेश की पूरी टीम 38 ओवरों में पवेलियन लौट गई. यह पाकिस्तान की बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 29 वन डे मैचों में 28वीं जीत थी. दूसरे सत्र में 20 मिनट के लिए मैच रोकना पड़ा, क्योंकि फ्लड लाइट बंद हो जाने से पूरा स्टेडियम अंधकारमय हो गया था.

सैम लोक्सटन का निधन

आस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सैम लोक्सटन का निधन हो गया. नब्बे वर्षीय सैम 1948 में सर डान ब्रैडमैन की उस टीम में शामिल थे, जिसने इंग्लैंड को सभी मैचों में पराजित किया था. उस सीरीज में हिस्सा लेने वालों में अब केवल नील हार्वे और आर्थर मोरिस जीवित हैं. सैम ने आस्ट्रेलिया के लिए कुल 12 टेस्ट मैच खेले. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वह राजनीति से जुड़े और विक्टोरियन संसद के सदस्य भी रहे.

रामपाल का विश्व रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के रवि रामपाल ने भारत के ख़िलाफ़ दूसरे वन डे मुक़ाबले के दौरान दसवें नंबर के बल्लेबाज़ के तौर पर वन डे क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर के नाम था, जिन्होंने 2009 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आबूधाबी में नाबाद 73 रन बनाए थे. रामपाल ने वरुण आरोन की गेंद पर चौका जड़कर आमिर का रिकॉर्ड तोड़ा. रामपाल 86 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने पारी की अंतिम गेंद पर छक्का लगाया. रामपाल और केमोर रोच ने 99 रनों की अटूट साझेदारी की, जो भारत और वेस्टइंडीज के बीच दसवें विकेट के लिए एक नया रिकॉर्ड है. इससे पहले यह रिकॉर्ड एंडी रॉबट्र्स और जोएल गार्नर के नाम था, जिन्होंने 1983 के विश्व कप में मैनचेस्टर में 71 रनों की साझेदारी की थी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

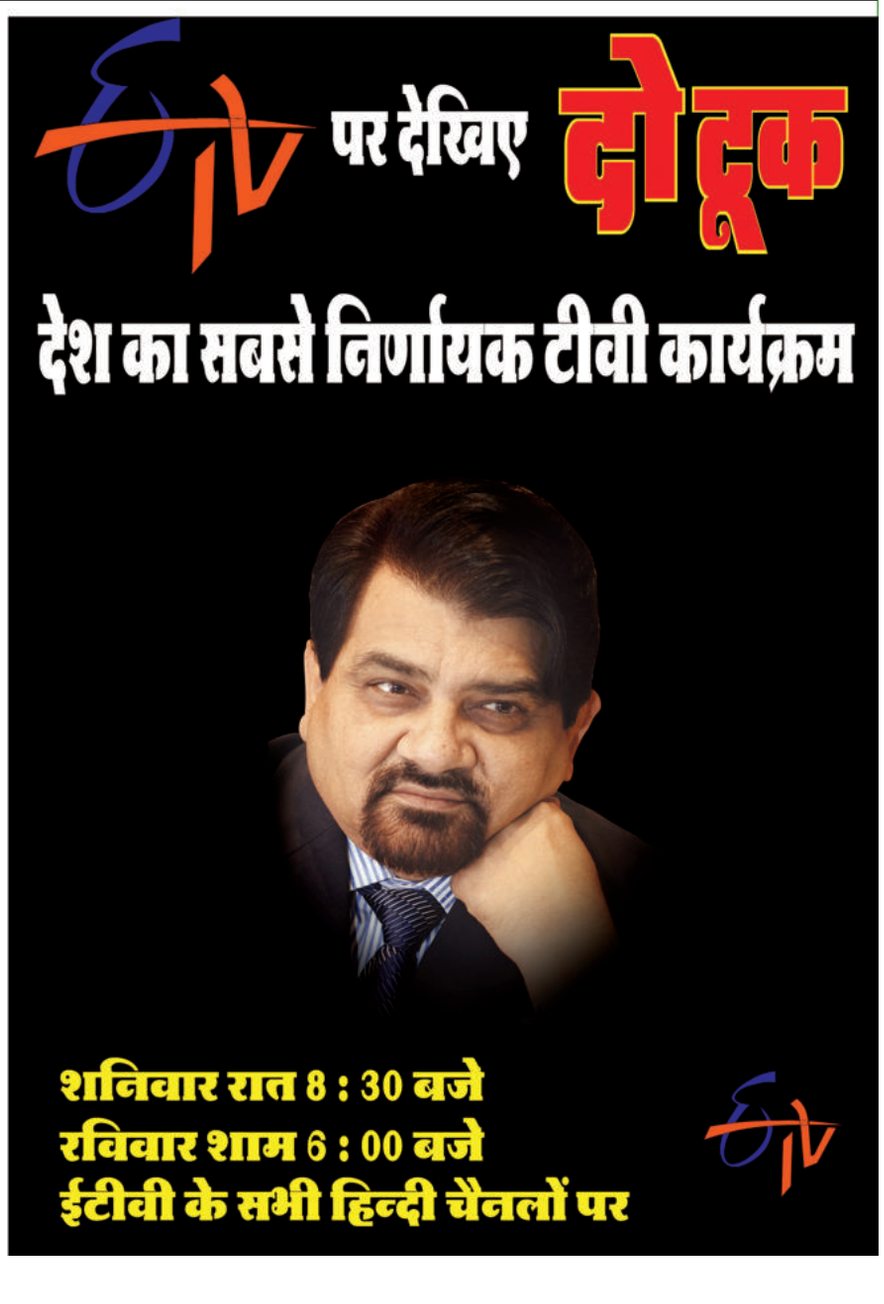

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

दीप्ति नवल के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में उन्होंने एक वृद्ध सेक्स वर्कर का किरदार निभाया है, जो 12 वर्षीय बच्चे की मां है.

twitter facebook

सोशल नेटवर्किंग साइट्स और फिल्मी सितारे

रीतिका सोनाली

एक छोटे एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान पसलियों में चोट लग गई...अंदर कुछ नुक़सान हुआ है. सांस लेने में परेशानी हो रही है. रात के तीन बज रहे हैं...कौन बनेगा करोड़पति का एपिसोड शूट करके घर लौट रहा हूं...सुबह जल्दी उठकर फिल्म की शूटिंग पर जाना है...

ऐसे कई संदेश हैं, जो फिल्मी सितारे ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपडेट करते रहते हैं. कई लोगों का मानना है कि ये संदेश बेमतलब होते हैं और इन्हें पढ़ना समय की बर्बादी है. फिल्मी सितारों की दिनचर्या से किसे क्या मतलब? वह क्या खा रहा है, यह जानकर हमें क्या करना है? वह कब सोने जा रहा है, यह जानकर ज्ञान में तो कोई वृद्धि नहीं हो रही है. लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ये संदेश केवल सितारों के बारे में जानकारी ही नहीं देते, बल्कि प्रेरणाप्रद भी हो सकते हैं. जगज़ाहिर है, जितनी लोकप्रियता फिल्मी सितारों की है, उतनी किसी और की नहीं. इसका अंदाज़ा इनके फॉलोअर्स की संख्या देखकर लगाया जा सकता है. इनमें से ज़्यादातर युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके हाथ में मोबाइल या लैपटॉप होता है. इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या बहुत है. जल्द ही भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल वाले देशों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर आ जाएगा. युवा वर्ग फिल्मों का शौक़ीन है, इसलिए सेलिब्रिटीज ब्लॉग और ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं.

युवा अपने प्रिय सितारे के इस कदर दीवाने रहते हैं कि उन्हें उनके बारे में हर पल की ख़बर रखना पसंद है. अपनी बातचीत में वे इसका उल्लेख करते हैं. आम नज़रिया यह है कि फिल्मी सितारों द्वारा ट्विट करने से उनका ही लाभ होता है, बैठे-ठाले प्रचार हो जाता है. इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब वे ट्वीट करते हैं कि वे रात के तीन बजे या देर रात काम करके घर लौट रहे हैं तो उनके हज़ारों प्रशंसकों तक यह बात पहुंच जाती है. पल भर के लिए सोचकर देखा जाए तो ख़ूबसूरत और लैविश दिखने वाले ये सितारे कितनी मशक्कत के बाद कोई मुक़ाम हासिल करते हैं और अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं. इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के संदेशों का युवाओं पर काफी असर होता है. सिर्फ़ यही नहीं, इन ट्विट के ज़रिए सेलिब्रिटीज को समझने, उनकी सोच जानने में मदद मिलती है.

देश की प्रमुख घटनाओं के बारे में भी कुछ कलाकार ट्विट कर अपनी राय देते हैं. चाहे वह अन्ना हजारे का आंदोलन हो या भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन. किसी भी तरह की घटना पर किसी सेलिब्रिटी की प्रतिक्रिया ट्विट के माध्यम से उसके प्रशंसकों तक पहुंचती है तो वे खासकर युवा वर्ग उसमें दिलचस्पी लेकर सार्थक भूमिका निभाने का प्रयास करता है. अपनी राय जताकर युवा वर्ग सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है. उसे अपनी नैतिक ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है, गुमराह और गुमनाम होते युवा वर्ग की चेतना का विकास होता है. कई बार ट्विटर के ज़रिए कलाकार बड़ी अच्छी बातें बताते हैं. जैसे कि साथी गायकों या संगीतकारों के जन्मदिन या पुण्यतिथि पर लता जी उन्हें याद करती हैं. कुछ ऐसी बातें बताती हैं, जो किसी को नहीं मालूम होतीं. अमिताभ अक्सर ऐसी बातें बताते हैं, जो उनसे किसी ने पूछी न हों. उन्होंने अपने दादा बनने की बात ट्विट करके ही सभी को बताई थी.

हालांकि यह भी ग़लत नहीं है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए करते हैं. अब इंडस्ट्री की हॉट गर्ल मानी जाने वाली पूनम पांडेय को ही लीजिए. उन्होंने जबसे ट्विटर पर अपना एकाउंट खोला है, तबसे वह सेमी न्यूड तस्वीरें पोस्ट करने की वजह से चर्चा में रहती हैं. लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वह अपनी एक हॉट पिक्चर ज़रूर पोस्ट करती है. पूनम ने ट्विटर को पब्लिसिटी पाने का प्लेटफॉर्म बना लिया है, लेकिन ऐसी हस्तियां अपवाद स्वरूप हैं. इन सब चीजों से लोगों को लुभाने की एक सीमा है, लोग बहुत ज़्यादा वक़्त तक यह सब पसंद नहीं करते. इसका पता चलता है, फॉलोअर्स की संख्या देखकर. हर चीज के साथ उसकी अच्छाई और बुराई दोनों ही जुड़ी होती हैं. यह तो हमें सोचना-समझना है कि किसे स्वीकार करना है और किसे अस्वीकार.

ritika@chauthiduniya.com

हिंदी फिल्में मुंबई तक सीमित नहीं

कई फिल्मों में अभिनय कर चुके अरविंद टाइटलर का नाम ताजनगरी आगरा में काफी जाना-पहचाना है. कृष्णा तेरे देश में, एक रात का मेहमान, साया, द शैडो, तीसरी चाल एवं ताजमहल जैसी फिल्मों के अलावा टीवी धारावाहिक तफ्तीश और भोजपुरी एलबम नाचे मयूरी में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके अरविंद से पिछले दिनों एक लंबी बातचीत हुई. पेश हैं मुख्य अंश:-

आजकल आप लगातार फिल्में कर रहे हैं....

मुझे कला के क्षेत्र में काफी समय हो गया है. पहले मैं शौकिया तौर पर फिल्मों से जुड़ा हुआ था, मगर अब इसे अपना करियर बना लिया है. इस वक़्त मेरे पास चार-पांच फिल्में हैं, जिनमें एक भोजपुरी फिल्म भी शामिल है.

आप सिर्फ़ खलनायक का रोल करना क्यों पसंद करते हैं?

यह सच नहीं है. दरअसल, कलाकार की एक छवि बन जाती है. मेरी शुरुआत खलनायक के सपोर्टिंग रोल के साथ हुई थी. अब मैं मुख्य खलनायक का रोल कर रहा हूं. ऐसी भूमिकाएं मुझे सूट करती हैं. वैसे मैं हर तरह की भूमिकाएं कर सकता हूं. कलाकार सिर्फ़ कलाकार होता है.

अभिनय का शौक कैसे हुआ?

मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था. पिता जी चाहते थे कि बड़ा होकर मैं आईपीएस अफसर बनूं, मगर मेरी मां ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. मां के आशीर्वाद और मेरे शौक ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया.

हिंदी फिल्मों के लिए आप मुंबई क्यों नहीं गए?

हिंदी फिल्मों का दायरा अब मुंबई तक सीमित नहीं है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष अनेक फिल्मों की शूटिंग होती है. इस दिशा में नोएडा और आगरा अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं.

अभिनय के क्षेत्र में सफलता का सूत्र क्या है?

सफलता का कोई तयशुदा फॉर्मूला नहीं होता. काफी लोग अभिनय करने मुंबई जाते हैं, लेकिन उन्हें मौक़ा नहीं मिल पाता. मैंने भी संघर्ष किया, लेकिन फिल्मों में अभिनय के लिए मुंबई का रुख नहीं किया. मैंने सोच लिया था कि पहले पहचान बनाऊंगा, उसके बाद करियर को आगे बढ़ाना है. मेरे पास ऑफर मुंबई से भी आ चुका है, बात बनी तो आप मुझे वहां भी काम करते हुए देखेंगे.

भविष्य की क्या योजनाएं हैं?

योजनाएं तो बहुत सारी हैं, पर उन्हें अमलीजामा पहनाना आसान नहीं है. फिल्म बनाने की योजना है, लेकिन पता नहीं, वह दिन कब आएगा.

अमिताभ आकाश
feedback@chauthiduniya.com

मनीषा की दूसरी पारी

एक छोटी सी लव स्टोरी से सुर्ख़ियों में आई मनीषा कोइराला अब बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं. उनकी फिल्म दो पैसे की धूप चार आने की बारिश अगले साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आठ मार्च को रिलीज हो रही है. ख़बर है कि वह अपनी इस फिल्म के प्रचार के सिलसिले में दो महीने के लिए मुंबई आ रही हैं. यहां वह सेक्स वर्करों के साथ कुछ समय बिताएंगी.

दीप्ति नवल के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में उन्होंने एक वृद्ध सेक्स वर्कर का किरदार निभाया है, जो 12 वर्षीय बच्चे की मां है. कुछ समय पहले तक उनके वैवाहिक जीवन में दरार की ख़बरें आ रही थीं, बात तलाक तक पहुंच चुकी थी. शायद फिल्मों में फिर से सक्रिय होने को लेकर उनके पति सम्राट दहल नाख़ुश हैं. मुंबई आने को लेकर भी उनके पति ने कई सवाल किए थे. हम तो यही कहेंगे मनीषा पहले आप अपने परिवार पर ध्यान दें, उसके बाद अपने करियर पर.

अनीता राज की वापसी

बहुत से लोग सोचते होंगे कि आख़िर अनीता राज कहां गईं. चक्कू मार दूंगी...डायलॉग हिट कराने वाली यह तारिका अब कहां है और क्या करती है, ऐसे सवाल दिल में आना लाज़िमी है, क्योंकि 1982 में उन्होंने फिल्म प्रेम गीत से डेब्यू किया था और रातोंरात स्टार बन गई थीं. 1992 में उन्होंने सुनील हिंगोरानी से शादी की थी. इस समय वह मुंबई में ऑप्टिकल स्टोर में पति का सहयोग करती हैं. उनका बेटा 20 वर्ष का है और अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है. फिल्मों में वापसी के संबंध में पूछने पर वह अक्सर कहती थीं कि यदि अच्छा रोल मिले तो काम ज़रूर करना चाहूंगी. प्रशंसकों के लिए एक अच्छी ख़बर है कि अस्सी के दशक की ख़ूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक अनीता राज भी अन्य वरिष्ठ अभिनेत्रियों की तरह बॉलीवुड में वापसी करने जा रही हैं. ख़बर है कि वह समीर कार्णिक की फिल्म चार दिन की चांदनी से वापसी कर रही हैं. फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक हीरोइन बेस्ड फिल्म है. अर्जुन हिंगोरानी के पुत्र सुनील हिंगोरानी से शादी करने के बाद अनीता फिल्मों से दूर हो गई थीं. अनीता राज के पास इस समय वक़्त है, इसलिए वह फिल्मों में वापसी कर रही हैं. उन्हें देखने वाले कहते हैं कि वह आज भी पहले की तरह जवान और सुंदर दिखाई देती हैं. उन्हें 2007 में थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन फिल्म में सितारों की भीड़ थी. इसलिए अनीता ने उसमें काम करने से इंकार कर दिया था. बक़ौल अनीता, फिल्म चार दिन की चांदनी में उनके लिए करने को बहुत कुछ है. अनीता राज नौकर बीवी का और गुलामी जैसी हिट फिल्मों में अपने सशक्त अभिनय के लिए आज भी याद की जाती हैं.

फिल्म प्रीव्यू

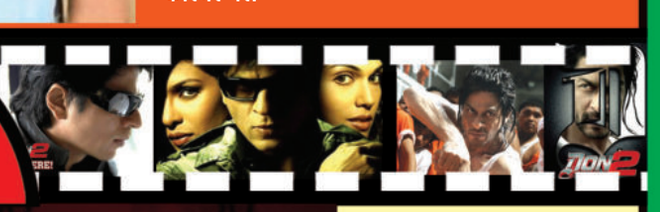

डॉन-2

एक्सेल एंटरटेनमेंट और रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्देशक फरहान अख्तर लेकर आ रहे हैं डॉन-2. निर्माताओं में फरहान के अलावा रितेश सिधवानी और शाहरुख ख़ान भी हैं. संगीत दिया है शंकर-एहसान-लॉय ने. कलाकार हैं शाहरुख ख़ान, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, बोमन ईरानी, ओम पुरी एवं कुणाल कपूर. पांच साल पहले पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल में डॉन (शाहरुख ख़ान) ने ख़ुद पुलिस को उलझा दिया और उनकी नाक के नीचे से चलता बना. पुलिस जिसे पान चबाने वाला सीधा-सादा विजय समझ रही थी, दरअसल वह डॉन था. एक बार फिर चोर-पुलिस के खेल में डॉन ने पुलिस को मात दी. रोमा (प्रियंका चोपड़ा), जिसे डॉन जंगली बिल्ली कहकर पुकारता है, अभी भी अपने भाई रमेश की हत्या का बदला डॉन से लेना चाहती है. वह डॉन जैसे दिखने वाले विजय के प्यार के चक्कर में पड़ गई और यह जानकर चकित रह गई कि वह विजय नहीं, डॉन है. अब वह इंटरपोल में शामिल हो चुकी है और डॉन को पकड़ने की योजना का अहम हिस्सा है. एशिया पर डॉन अपना दबदबा बना चुका है, उसकी नज़र अब यूरोप पर है. कुआलालंपुर से उसका एक्शन अब बर्लिन शिफ्ट हो गया है. यूरोप में वह किसी भी क़ीमत पर अपना दबदबा बनाना चाहता है. इसके लिए वह अपने रास्ते में आने वाले हर शख़्स को हटाने के पहले सोचेगा भी नहीं. पुलिस और डॉन की इस लुका-छिपी का मज़ा फिर देखने को मिलेगा डॉन 2 में. फरहान को ऑल राउंडर कहा जा सकता है. अभिनय, लेखन, गायन एवं निर्देशन यानी वह सब कुछ सफलतापूर्वक कर लेते हैं. बतौर निर्देशक उनकी फिल्म पांच वर्ष बाद आ रही है. उन्होंने डॉन-द चेज़ बिगिंस अगेन का सीक्वल डॉन-2 बनाई. पिछली फिल्म रीमेक थी और इस बार डॉन-2 में मौलिक कहानी देखने को मिलेगी. दिल चाहता है (2001), लक्ष्य (2004) और डॉन (2006) जैसी फिल्में बना चुके फरहान को अच्छी समझ है. डॉन-2 के ट्रेलर्स सराहे जा रहे हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें ज़बरदस्त एक्शन और रोमांच देखने को मिलेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 19 दिसंबर-25 दिसंबर 2011

www.chauthiduniya.com

गन्ना अपना, सौतेला धान

प्रफुल्ल भी भूले किसानों को

प्रवीण महाजन

बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और सच्चाई यह है कि देश की सभी पार्टियां किसानों को भूल चुकी हैं. खास कर गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरोली के धान उत्पादकों की सुननेवाला आज कोई नहीं है, जबकि इस क्षेत्र से केंद्र में अपना दबदबा रखने वाले राकांपा नेता व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल जैसे दमदार नेता चुनकर आते हैं. राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार केंद्र में कृषि मंत्री है. पटेल को पवार का दायां हाथ माना जाता है. ऐसे में वे चाहे तो चुटकी में धान उत्पादकों की समस्या हल कर सकते हैं, लेकिन केंद्र में इतना बड़ा नेता होने के बाद भी धान उत्पादकों को अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है. जिस पटेल घराने को बीड़ी मज़दूरों का नेता कहा जाता है, आज उसी घराने के प्रफुल्ल पटेल के राज में किसान खुद को लावारिस महसूस कर रहे हैं. एक के बाद एक बंद हो रही राइस मिल्स किसी को नज़र नहीं आ रही. हैरानी की बात यह है कि प्रफुल्ल पटेल एक ओर जहां किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या, जो अरबपति है उनकी एयर लाइंस को घाटे से उबारने के लिए आकाश-पाताल एक कर देते हैं. नागपुर में ही फुटबॉल के विकास के मुद्दे पर लंबा-चौड़ा भाषण देते हैं, वहीं दूसरी ओर वे धान उत्पादकों और डूबती राइस मिलों की समस्याओं की ओर से आंखें मूंदे नज़र आते हैं.

सरकार किसानों की दुश्मन

राज्य हो या केंद्र सरकार दोनों किसानों की दुश्मन है. धान, कपास, सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए उनके न मन में जगह है और न ही ऑफिस की फाइलों में. शक्कर की पिराई शुरू हुई नहीं कि दो दिन में निर्यात से पाबंदी हट जाती है, लेकिन कपास, धान पर निर्यात पाबंदी हटाने के लिए किसानों को अपनी जान देनी पड़ती है. ये सौतेलापन है, जिसे किसान बरसों से महसूस कर रहे हैं. पूर्व मुख्य आयकर अधिकारी और धान उत्पादकों की मांगों को निरंतर सरकार के सामने रख रहे डी.वी. धार्मिक जब धान पर चर्चा करते हैं, तो उनके शब्द कठोर हो जाते हैं. नेताओं व अधिकारियों के दोहरे चरित्र के कई सबूत वे आपके सामने रख देते हैं.

डी.वी धार्मिक के अनुसार धान उत्पादकों के लिए सरकार ने क्या किया इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है. क्योंकि ज़मीनी स्तर पर कुछ दिखाई ही नहीं देता. अधिकतर धान पट्टा आसमानी पानी पर निर्भर है. जहां सिंचाई की सुविधा है, वहां बिजली नहीं है. उन्होंने बताया कि देश में लगभग 380 से 395 लाख टन धान का उत्पादन होता है, जो मांग से कहीं अधिक है. सरकार अपने स्टॉक में दो वर्षों का अनाज रखती है. वर्ष 2008 के पूर्व क़रीब 60 लाख टन ग़ैर-बासमती धान का निर्यात किया जाता था, लेकिन वर्ष 2008 में बग़ैर किसी कारण के ग़ैर-बासमती धान पर निर्यात पाबंदी लाद दी गई. नवंबर 2010 में उन्होंने पूर्व विदर्भ के क़रीब 12 हज़ार किसानों के पत्र प्रधानमंत्री को भेजे, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आया. केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक की मदद से किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्रीय मंत्री प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की थी. धार्मिक ने बताया कि मुखर्जी मान गए थे. उन्होंने धान के निर्यात से पाबंदी हटाने की भी बात मान ली थी, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने केवल 5 लाख टन निर्यात को ही मंजूरी दी और वह भी तमिलनाडु की 3 वेरायटी (मट्टू, पुन्नू और सांबा) को. इसके पीछे का कारण उस दौरान तमिलनाडु में होने वाला चुनाव था. इससे सरकार की स्वार्थसिद्धि करने वाली नीति का पता चलता है. इसके बाद भी धार्मिक ने कई बार नेताओं से संपर्क किए. बाद में सभी वेरायटी के 10 लाख टन धान के निर्यात को मंज़ूरी दी गई. उल्लेखनीय है कि सरकार की निर्यात विरोधी इन्हीं नीतियों से तंग आकर आंध्रप्रदेश के किसानों ने इस वर्ष 1.50 लाख एकड़ में धान की रोपाई ही नहीं की. इससे परेशान आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर महीने में दिल्ली के आला नेताओं से चर्चा की इसके बाद 20 लाख टन निर्यात को मंज़ूरी दी गई. सबसे हैरत की बात यह है कि अब जो नया धान बाज़ार में आने वाला है, उसे लेकर सरकार ने अब तक कोई नीति घोषित नहीं की.

छीन लेते हैं तीन लाख करोड़

धान की फ़सल के पीछे प्रति एकड़ क़रीब 15 हज़ार रुपये का ख़र्च आता है. एक एकड़ में औसतन 12 क्विंटल धान का उत्पादन होता है. सरकार ने इसका भाव 1130 रुपये घोषित किया है, लेकिन पूर्व विदर्भ की सबसे बड़ी धान मंडी तुमसर में आज भी किसानों से धान एक हज़ार रुपये के नीचे का भाव देकर ही खरीदा जा रहा है. ऐसे में किसानों को प्रति एकड़ क़रीब 2 से 3 हज़ार रुपये का नुक़सान झेलना पड़ रहा है. केंद्र सरकार की पांच वर्ष पूर्व दी गई रिपोर्ट के अनुसार कृषि उपज को उचित भाव नहीं देकर सरकार किसानों से 3 लाख करोड़ रुपये हर वर्ष छीन लेती है. सरकार दावा करती है कि वह हर वर्ष किसानों को 70 हज़ार करोड़ की सब्सिडी देती है, लेकिन यदि हिसाब लगाया जाए, तो सब्सिडी काटकर उल्टा किसान ही सरकार को हर वर्ष 2 लाख 30 हज़ार करोड़ रुपये की सब्सिडी देते हैं. उन्होंने बताया कि जिस सब्सिडी की बात सरकार करती है, उसका कोई फ़ायदा किसानों को नहीं मिलता, बल्कि इससे कंपनियां फल-फूल रही हैं. अब तक सरकार ने इन 70 हज़ार करोड़ रुपये का ऑडिट भी नहीं किया है. ग़ौरतलब है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केवल पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में ही धान की ख़रीदी करता है, जबकि बाकी राज्यों में किसानों को मजबूरन अपना धान व्यापारियों को कम दाम पर बेचना पड़ता है.

रोगायो ने बढ़ाए दाम

एक अध्ययन के अनुसार रोज़गार गारंटी योजना के कारण मज़दूरों के दाम बढ़ गए हैं. खेती के लिए मज़दूर नहीं मिल पा रहे हैं. कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि रोगायो के कामों पर बुआई और कटाई के दौरान रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन इसे नहीं माना गया. धार्मिक ने कहा कि सरकार ने उन किसानों की सूची बनानी चाहिए, जिन्हें मज़दूर लगते हैं. बाद में रोगायो के मज़दूरों को उनके खेतों में काम देना चाहिए. इससे दोनों समस्याएं हल हो जाएगी, लेकिन उन्हें दुख: है कि सरकार इस तरह के सुझावों को अनदेखा कर देती है. उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियां काफी ग़लत हैं. इन नीतियों ने किसानों को केवल मौत के अलावा और कुछ नहीं दिया है. इन्हें बदलने की ज़रूरत हैं.

पूर्व विदर्भ की 300 राइस मिलें बंद

विकास में पिछड़ते जा रहे विदर्भ की बदहाली में एक और अध्याय जुड़ गया है. एक चौंकाने वाली जानकारी के तहत विदर्भ में 300 से भी अधिक राइस मिल्स बंद पड़ गई हैं जिनमें से अधिकांश भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरोली की हैं. ग़ौरतलब है कि इन चार ज़िलों में तीन वर्ष पूर्व लगभग 1300 राइस मिल्स थीं, लेकिन अब इनकी संख्या एक हज़ार के भी नीचे पहुंच गई हैं. जो शुरू है उनमें से भी क़रीब 30 फ़ीसदी मिल्स छह महीने या फिर दिन में केवल 8 घंटे शुरू रहती हैं. ऐसे में हज़ारों परिवारों पर बेरोज़गारी का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन इस गंभीर स्थिति का हल निकालने के प्रति राज्य सरकार व जन प्रतिनिधि गंभीर नज़र नहीं आ रहे है.

ग़ौरतलब है कि महाराष्ट्र में विदर्भ को धान का कटोरा कहा जाता है. भंडारा और गोंदिया ज़िले इसमें अग्रसर है. भंडारा ज़िले में एक लाख 80 हज़ार, गोंदिया ज़िले में 1 लाख 85 हज़ार, चंद्रपुर ज़िले में 70 हज़ार हेक्टेयर कृषि ज़मीन पर धान की फ़सल ली जाती है. गढ़चिरोली ज़िले में भी बड़े पैमाने में धान की फ़सल होती है. इनमें से गोंदिया ज़िले में सबसे अधिक राइस मिल्स हैं. इनकी संख्या 400 से अधिक हैं, जबकि भंडारा ज़िले में 395, चंद्रपुर ज़िले में 366 और गढ़चिरोली ज़िले में 126 राइस मिल्स हैं. जानकारी के अनुसार इनमें से भंडारा ज़िले की 75, चंद्रपुर 51 और गढ़चिरोली ज़िले की 63 राइस मिल्स बंद हो चुकी हैं. वहीं गोंदिया की स्थिति तो सबसे ख़राब है. यहां क़रीब 30 फ़ीसदी राइस मिल्स बंद हो गई है. जानकारों के अनुसार चारों ज़िलों में पहले राइस मिल्स 24 घंटे शुरू रहती थी, लेकिन जो शुरू है, उनमें से कई मिल्स अब केवल 4 से 6 महीने या फिर दिन में 8 घंटे ही शुरू रहती हैं. राइस मिलों की इस दयनीय स्थिति के कारण क्षेत्र में बड़े पैमाने में रोज़गार का संकट निर्माण हो गया है. भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरोली में लगभग 1300 राइस मिल्स में हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिल रहा था. चारों ज़िलों में राइस मिल्स को एक बड़े रोज़गार के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन सैकड़ों मिलों के बंद होने से हज़ारों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं. जो राइस मिल शुरू है, वे भी ग्रामीणों को वर्ष भर रोज़गार नहीं दे पा रही है. ऐसे में क्षेत्र में कई परिवार संकट में फंस गए हैं. राइस मिलों को पहले सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है. अधिकतर राइस मिलों में पुरानी मशीनें हैं. ऐसे में धान की पिसाई करने पर चावल की टूट अधिक होने से इसकी पॉलिशिंग नहीं होती. इसे देखते हुए अब किसान अपना धान राइस मिलों में नहीं लाकर सीधे व्यापारियों को बेच रहे हैं. खाद्यान्न महामंडल की ओर से जो धान राइस मिलों को पिसाई के लिए दिया जाता है, उसकी यातायात दर काफी कम है. गत तीन वर्षों से राइस मिल संचालक इसे 40 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने केवल 10 रुपये की बढ़ोतरी की है. वहीं मिल मालिकों का 15 करोड़ रुपये अब तक सरकार ने नहीं दिया है. मिलों में पिसा गया सरकार का ही चावल रखने के लिए खाद्यान्न महामंडल के गोदाम खाली नहीं है. व्यापार में घाटा होने के कारण राइस मिल मालिकों ने किसानों से धान की ख़रीदी बंद कर दी है. ऐसे में बाज़ार में किसानों का धान खरीदने के लिए व्यापारियों की कमी हो गई है, जिसके कारण किसानों को काफी कम भाव में धान बेचना पड़ रहा है. तीन वर्षों से मंदी झेल रहे राइस मिल संचालक बैंकों का कर्ज़ लौटा नहीं पा रहे हैं, जिससे बैंकों की ओर से उन्हें नोटिस भेजी जा रही है.

पैकेज की मांग

अधिकतर राइस मिलों में आज भी पुरानी मशीनें होने से पिसाई के कारण चावल की टूट अधिक होती है. पॉलिशिंग नहीं होने से यहां के चावल का दर्ज़ा काफ़ी कम आंका जाता है. इससे यहां के चावल को काफी कम भाव मिलता है. विदर्भ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने चौथी दुनिया को बताया कि चावल को अच्छी पॉलिशिंग करने के लिए लगने वाली मशीनों का ख़र्च क़रीब 70 लाख रुपये हैं. हालांकि गढ़चिरोली ज़िले के क़रीब 25 राइस मिलों में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग होता है. यहां के चावल की मुंबई, पुणे आदि शहरों में अच्छी मांग है, लेकिन अधिकतर मिल मालिकों की माली हालत इतनी खराब है कि वे आधुनिकीकरण का इतना बड़ा ख़र्चा वहन नहीं कर सकते हैं. अग्रवाल ने कहा कि इसे देखते हुए एसोसिएशन पिछले तीन वर्षों से सरकार से राइस मिलों को पैकेज देने की मांग कर रहा है, ताकि वे इस समस्या से बाहर निकल सकें, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही. उन्होंने बताया कि धान की पिसाई के बाद जो बच जाता है, उससे खाद्य तेल निर्माण करने का कारखाना गोंदिया ज़िले के आमगांव में शुरू किया गया है. इससे न सिर्फ किसानों को, बल्कि राइस मिल मालिकों को भी फायदा मिल रहा है, लेकिन यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है. धान की भूसी से शराब तैयार करने की दिशा में शोध शुरू था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, ताकि राइस मिल मालिकों और धान उत्पादक किसानों को लाभ मिल सके.

feedback@chauthiduniya.com

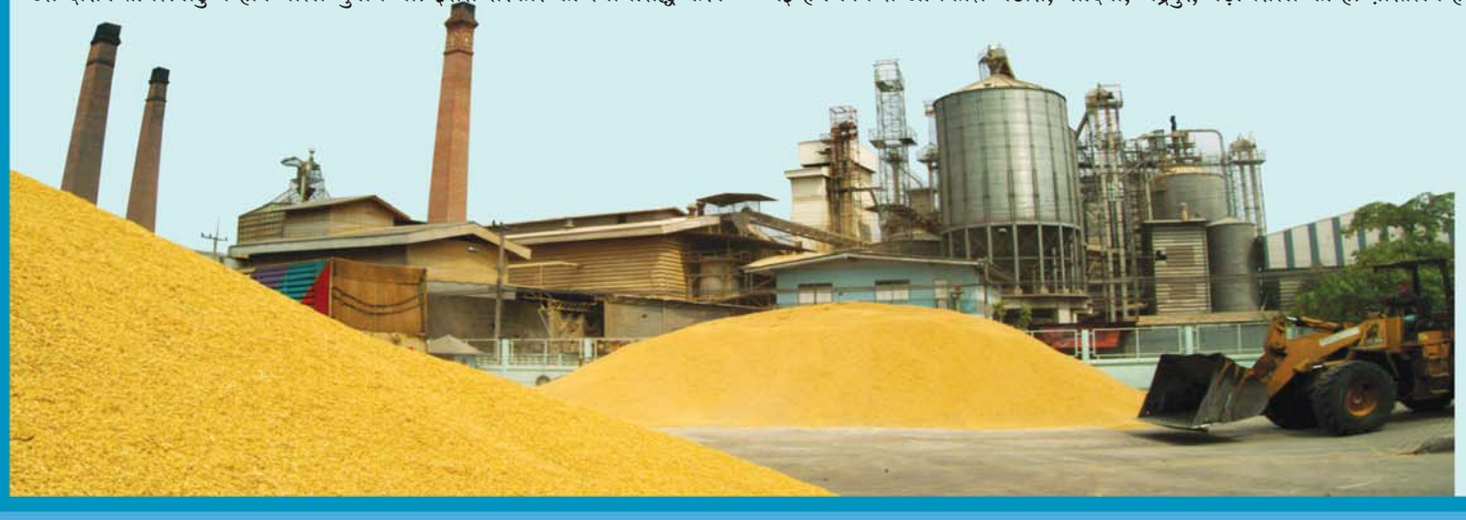

यह तो सर्वविदित है कि आतंकवादी दहशत फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. उन्हें इसकी ज़रा भी परवाह नहीं रहती कि उनके सामने बच्चा है या मरीज़.

आखिर आपकी सरकार किस दिशा की ओर जा रही है? इस स्थिति में भी आपकी सरकार की बेशर्मी यह है कि आपके किए गए कार्यों के आधार पर जनता आपकी पार्टी को चुनाव में विजय का हार पहनाये.

महाराष्ट्र हलचल

नांदेड़ ज़िले की धर्माबाद नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचारार्थ आयोजित सभा में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और सांसद भास्करराव पाटिल खतगांवकर का सत्कार करते हुए विधायक वसंत चव्हाण, विधायक अमर राजुरकर, विधायक ओमप्रकाश पोकर्णा, मुन्ना अब्बास आदि.

मुंबई में शिवसेना नेता मनोहर जोशी के जन्मदिन पर आयोजित अमृत महोत्सव में रिपब्लिकन नेता रामदास अठावले, सेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, राकांपा नेता शरद पवार, भाजपाध्यक्ष नितिन गडकरी की मौजूदगी में बाबासाहब पुरंदरे जोशी व श्रीमती अनघा जोशी का सत्कार करते हुए.

मुंबई में निवेश के लिए इंडो-जर्मन चेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन का एक शिष्टमंडल सिडको के अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव से उनके नरीमन प्वॉइंट स्थित कार्यालय में मुलाकात करते हुए.

उमरी नगरपालिका चुनाव में राकांपा उम्मीदवारों के पक्ष में रैली संबोधित करते गृहमंत्री आर.आर. पाटिल और मंचासीन पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड़ पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल, पूर्व विधायक बापूसाहब कोरठेकर व अन्य.

पुणे में 26वीं अंतरराष्ट्रीय मैराथन स्पर्धा का उद्घाटन करते वन मंत्री पतंगराव कदम, महिला व बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड़ और अभिनेत्री अमृता खानविलकर. इस मौके पर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल व्यवहारे, पूर्व मंत्री रमेश बागवे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अभय छाजेड़, अभिनेता आदिनाथ कोठारे, शरद रणपिसे और प्रभा ओझा भी उपस्थित रहे.

आगामी महानगर पालिका चुनाव के संबंध में उद्योग मंत्री नारायण राणे के आवास पर हुई बैठक में मौजूद सार्वजनिक लोकनिर्माण मंत्री छगन भुजबल, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह, सांसद गुरुदास कामत, पालकमंत्री जयंत पाटिल, वस्त्रोद्योग मंत्री नसीम खान, मुंबई राकांपा के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा, मंत्री वर्षा गायकवाड़, राज्यमंत्री सचिन अहीर और मुंबई मनपा में विपक्ष के नेता राजहंस सिंह.

धामणगांव रेलवे नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस-रिपाइं प्रत्याशियों के पक्ष में सभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और मंचासीन कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, राज्यमंत्री राजेंद्र मुलक, सांसद दत्ता मेघे, डॉ. राजेंद्र गवई, विधायक वीरेंद्र जगताप, विधायक रावसाहब शेखावत, विधायक मस्के, वसुधा देशमुख, बबलू देशमुख व अन्य.

अनुदान लूटने वाली
संस्थाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं

राजेश नागदेव

राज्य में लाखों बोगस छात्रों के होने का पता चलने पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा सहित अन्य कई मंत्रियों ने घोषणा की थी कि इसके लिए ज़िम्मेदार संस्था संचालकों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उसके बाद बड़े ज़ोर-शोर से पूरे राज्य में 3 से 5 अक्टूबर के दरम्यान सभी स्कूलों में छात्रों की जांच-पड़ताल का गणना की गई और उनके हाथों वोटिंग इंक से निशान लगाए गए. इस छात्र गणना के बाद यह पता चला कि लाखों की संख्या में बोगस छात्र पाए गए और कुछ बोगस संस्थाओं का भी पता चला, लेकिन जांच के पश्चात उन संस्थाओं के विरुद्ध सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया. ऐसा ग़ैर-क़ानूनी कार्य करने वाली संस्थाओं के ख़िलाफ़ आख़िर कार्रवाई करने में क्यों हिचक रही है सरकार? शिक्षा मंत्रालय ने छात्र गणना के दौरान कुल कितने छात्र बोगस पाए गए, इसके आंकड़े क्यों जाहिर नहीं किए हैं? सरकार के इस रवैये से कदाचार में लिप्त शिक्षण संस्थाओं को अभयदान मिल गया है. ये बेपरवाह होकर अपना गोरखधंधा पुनः संचालित कर रही हैं. साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए तथ्य उजागर हो रहे हैं.

ग़ौरतलब है कि छात्र गणना की पड़ताल के दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों को लगाया गया था. इन अधिकारियों को स्कूलों की जांच रिपोर्ट तैयार कर ज़िलाधिकारियों को सौंपनी थी. जांच में अधिकांश स्कूलों में बोगस छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में मिले थे. इस राज्य व्यापी मुहिम में 1 लाख 887 स्कूलों में 20 लाख 70 हज़ार 520 छात्र अनुपस्थित पाए गए थे. ख़ास बात यह है कि राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा ने मंत्रिमंडल की बैठक में जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें बोगस स्कूलों का कहीं ज़िक्र नहीं किया गया है. उन्होंने रिपोर्ट में छात्र जांच के दरम्यान लाखों छात्र-छात्राओं की अनुपस्थिति बता कर हाथ ऊपर कर लिए हैं, लेकिन बोगस स्कूलों का आंकड़ा क्यों नहीं बताया? यह सवाल राज ही बनकर रह गया है. फिर स्कूलों व छात्रों की जांच मुहिम के नाम पर सरकार ने करोड़ों रुपये किसलिए ख़र्च कर दिए? नागपुर शहर के मेडिकल चौक इलाके में स्थित सेंट विंसेंट उच्च प्राथमिक स्कूल प्रबंधन द्वारा 9 बोगस शिक्षकों के नाम से वेतन उठाने के मामले का ख़ुलासा 29 नवंबर को हुआ. यह मामला तब उजागर हुआ, जब शिक्षाधिकारी सोमेश्वर नेताम ने नागपुर के इमामवाड़ा थाने में स्कूल के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई. थाने में दर्ज रिपोर्ट में साफ़ कहा गया है कि वर्ष 1979 से 2010 के बीच मेडिकल चौक स्थित सेंट विंसेंट उच्च प्राथमिक स्कूल ने शासन से धोखाधड़ी कर 5 करोड़ 17 लाख 23 हज़ार 840 रुपये हासिल किए हैं. स्कूल की तत्कालीन मुख्याध्यापिका अल्फांसो, लिपिक इग्नेशियस विंटिन, सहायक शिक्षिका सुमिता ज्ञानेश्वर ठाकरे, चंद्रलेखा बहादुर सिंघल, संध्या अशोक राहुड़े, जोसिमन निकोलस सिल्वेस्टर, सदनमोरे विजय बैस्टियन, सुधी नफीसा अख़्तर बेग, जयश्री इग्नेशियस बैस्टियन, ट्रेजा जेवियर अंबोनी उर्फ ट्रेजा सिल्वेस्टर फ्रांसिस, अरुणा शैलेश माइकल, तत्कालीन शिक्षा निरीक्षक अधिकारी के.एम. चौधरी, एस.टी. केदार, फरकाडे और अर्चना हज़ारे ने मिलकर करोड़ों की इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है. शिक्षाधिकारी नेताम के अनुसार स्कूल की तत्कालीन मुख्याध्यापिका अल्फांसो ने विंसेंट अल्फांसो,

लिपिक इग्नेशियस ने उन सहायक शिक्षकों के नाम हाजिरी रजिस्टर से नहीं हटाये जो इस्तीफ़ा देकर जा चुके थे. इस संबंध में स्कूल प्रबंधन ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भी कोई सूचना नहीं दी. यदि शिक्षा विभाग को इस संबंध में सूचित किया जाता तो नए शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ती. स्कूल प्रबंधन ने शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए स्कूल छोड़ कर गए शिक्षकों के असली नाम वाले और मिलते-जुलते दस्तावेज़ वालों को नियुक्त किया. इस तरह क़रीब 9 बोगस शिक्षकों को 1500 से 2000 रुपये मासिक वेतन पर रख लिया गया था. इन बोगस शिक्षकों के नाम पर स्कूल प्रबंधन फर्ज़ी हस्ताक्षर कर शिक्षकों का वेतन उठा रहा था. इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि वे बच्चों की फीस निर्धारित समय पर हर माह भरते हैं, पर फीस की रसीद उनको नहीं दी जाती है. विशेष बात यह है कि जो शिक्षक स्कूल छोड़ गए उनमें से कई विदेशों में बस गए हैं. इसका मतलब यह है कि सेंट विंसेंट स्कूल पूरी तरह से बोगस है और उसके रिकार्ड बनावटी हैं.

इसके पहले जिस नांदेड़ ज़िले में लाखों बोगस छात्रों के होने का पता चला था, वहीं अब दो बोगस स्कूलों पर वहां के ज़िलाधिकारी श्रीकर परदेशी ने कार्रवाई करने के आदेश दिए. इस कार्रवाई में एक और रोचक तथ्य सामने आया. बैरम पाटिल प्राथमिक शाला, भोपलवाड़ी कलंबर शैक्षणिक संस्था के अध्यक्ष भारती नियुक्ति भोरवाड़े अपनी सगी बहन को स्कूल के रिकार्ड पर शिक्षिका दर्शा कर उसके नाम पर हर माह बैंक में वेतन की रकम जमा की. उनकी इस बोगस शिक्षिका बहन का नाम श्रीमती चंद्रकला निवृत्ति भोरवाड़े है और यह लंदन में रहती है, लेकिन उसकी नौकरी नांदेड़ में बता कर लाखों का वारा-न्यारा संस्था संचालक करता आ रहा है. इसी तरह नांदेड़ ज़िले के ही लिंबगांव में स्थित जूनियर कॉलेज संस्था संचालक विट्ठल सीताराम वाघमारे को वर्ष 2008 में कॉलेज शुरू करने की अनुमति प्राप्त हुई थी. प्रत्यक्ष में कॉलेज शुरू न होते हुए भी छात्र-छात्राओं की उपस्थिति दर्शा कर शिक्षण उपसंचालक के कार्यालय से प्रस्ताव मंज़ूर करा लिया. ग़ौर करने वाली बात यह है कि यहां के शिक्षाधिकारी वाघमारे स्कूल संचालक विट्ठल वाघमारे के भाई हैं और संस्था की कार्यकारिणी के सदस्य हैं. इस तरह शिक्षाधिकारी वाघमारे ने संस्था का कार्यकारिणी सदस्य होने पर खुद की संस्था का प्रस्ताव अनुदान मंज़ूरी के लिए भेजा और मंज़ूर करा लिया.

यह दुस्साहसिक कार्रवाई करने के पश्चात नांदेड़ ज़िलाधिकारी परदेशी ने दोनों बोगस स्कूलों के संचालकों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता धारा 420, 468, 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया है, लेकिन अन्य किसी ज़िले के ज़िलाधिकारी ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया है? इसलिए यह सवाल उठना लाज़िमी है कि छात्र गणना के बाद भी सरकार उन संस्थाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है जहां बड़ी संख्या में बोगस छात्र होने का पता चला था और जो संस्थाएं पूरी तरह सिर्फ़ काग़ज़ों पर संचालित हो रही थीं? इन सारे तथ्यों को देखकर पता चलता है कि राज्य में शिक्षा की किस तरह दुर्दशा है जिसकी ओर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है.

भंडारा ज़िले की रिपोर्ट ग़ायब

छात्र गणना के मामले में भंडारा ज़िले का कारनामा अजब-गजब है. एक ओर जिला शिक्षाधिकारी छात्र गणना की रिपोर्ट ज़िलाधिकारी को भेजने की बात कहते हैं. दूसरी ओर ज़िलाधिकारी का कहना है कि छात्र गणना व जांच की रिपोर्ट अब तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है. दोनों अधिकारियों की बात को सही माना जाए तो सवाल उठता है कि रिपोर्ट गई तो कहां गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने रिपोर्ट ग़ायब करवा दी हो ताकि शिक्षा का बोगस कारोबार करने वालों का बचाव किया जा सके.

छह माह से शिक्षक ग़ायब

नागपुर ज़िले की सावनेर तहसील के तिष्टी गांव में संचालित ज़िला परिषद स्कूल में पिछले 6 माह से शिक्षक नहीं आ रहे थे. इससे आक्रोशित ग्रामवासियों ने स्कूल पर ताला लगा दिया है. ग्रामवासियों के अनुसार तिष्टी गांव स्थित ज़िला परिषद शाला में गरीब परिवारों के 29 बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन पिछले 6 माह से इस ज़िला परिषद स्कूल का शिक्षा से वास्ता नहीं है. ग्रामवासियों का कहना है कि 6 माह पूर्व यहां दो शिक्षक नियुक्त थे. उनमें से एक का स्थानांतरण कहीं और कर दिया गया. दूसरी शिक्षिका बीमार होने का आवेदन देकर छुट्टी पर है. यहां पढ़ने वाले ग़रीब परिवारों के बच्चे हर दिन स्कूल आते हैं, पर पढ़ाने वाला कोई शिक्षक न होने से निराश होकर घर चले जाते हैं. इस संबंध में जब शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से शिकायत करने पर जो व्यवस्था की गई वह बड़ी हास्यास्पद है. शिकायत मिलने के बाद उच्च अधिकारियों ने हर दिन अलग-अलग स्कूल से शिक्षकों को भेजकर तिष्टी स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन प्रतिदिन शिक्षक बदलने का दुष्परिणाम यह हुआ कि चौथी कक्षा के छात्र को पहली के शिक्षक अपने विषय का ज्ञान तक नहीं है. इससे आक्रोशित ग्रामवासियों ने स्थायी शिक्षक नियुक्त न होने तक स्कूल को ताला लगा दिया.

feedback@chauthiduniya.com

बीमारों की सुध नहीं ले रही सरकार

मयूर रंगारी

नागपुर ज़िला मुख्यालय से क़रीब 400 किमी दूर गढ़चिरोली ज़िले के अतिदुर्गम क्षेत्र में सिकलसेल बीमारी से पीड़ित किसी मरीज को यदि तत्काल उपचार की ज़रूरत है तो राज्य सरकार के नियम के अनुसार वह उसे नागपुर के सरकारी अस्पताल से मिलेगा. फिर चाहे वह रास्ते में मरे या तड़पे उससे आम आदमी के साथ वाली इस राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं है. ऐसा भी नहीं है कि उसे नागपुर आने पर पूरी सुविधाएं मिलेगी ही. पूरी संभावना है कि यहां भी उसे लताड़ कर भगा दिया जाएगा. ऐसे में आखिर आम आदमी करे तो क्या करे? जिस बीमारी से प्रभावितों की संख्या राज्य के 20 ज़िलों में 30 लाख से भी अधिक हैं, उनके बारे में सरकार गंभीर नहीं है. यहां तक की महाराष्ट्र लोकायुक्त के अप्रैल 2011 में इस संबंध में दिए आदेश को भी सरकार ने कचरे की टोकरी में डाल दिया है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार वर्ष 2006 से अब तक राज्य सरकार को सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रम के लिए लगभग 52 करोड़ रुपये दे चुकी है.

महाराष्ट्र लोकायुक्त की भी अहमियत नहीं

देश में जन लोकपाल क़ानून को लेकर कांग्रेस कितनी गंभीर है, इसका एक उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है. महाराष्ट्र में सिकलसेल बीमारी से पीड़ित लाखों मरीज़ों के लिए महाराष्ट्र लोकायुक्त पी.बी. गायकवाड़ ने राज्य सरकार को 2 अप्रैल 2011 में काफी महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं, लेकिन छह महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र को वर्ष 2006 से अब तक लगभग 52 करोड़ रुपये दिए हैं. लोकायुक्त गायकवाड़ ने एनआरएचएम द्वारा दर्शाए गए 6 दिशा-निर्देशों के साथ-साथ सिकलसेल मरीज़ों को और भी सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश दिए हैं. इसके तहत हीमोग्लोबिन से संबंधित सभी प्रकार की जांच प्रभावित ज़िलों के ज़िला अस्पतालों में होनी चाहिए. राज्य सरकार ने नागपुर के दो, यवतमाल, अकोला, नांदेड़, औरंगाबाद, धुलिया, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई में 4.50 करोड़ रुपये की मशीनें मुहैया कराई हैं. जानकारी के अनुसार ये मशीनें अधिकतर अस्पतालों में धूल खा रही हैं.

मरीज़ों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं

लोकायुक्त ने साफ़ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के जरिए सिकलसेल प्रभावित 20 ज़िलों में घर-घर जाकर लोगों के सर्वेक्षण का काम पूर्ण करे. इसके आधार पर वह विश्लेषण करे कि सिकलसेल बीमारी का राज्य में वर्तमान में क्या प्रभाव है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक किसी भी तरह के सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं किया है. ऐसे में मुख्यमंत्री भी यह जानकारी नहीं दे सकते कि उनके राज्य में आखिर सिकलसेल पीड़ित मरीज़ों की संख्या कितनी है. सिकलसेल बीमारी से पीड़ित मरीज़ को साधारणतः ब्रेन, आंख, लंग, दिल, लीवर, स्पीनल, किडनी में परेशानियां होती हैं. आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार गर्भवती महिला और छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लिए एक कार्यक्रम बनाए, जिसके तहत वे बीमार हो या न हो प्रभावित सभी ज़िला अस्पतालों में उनकी समय-समय पर पूरी जांच हो सके. यदि जांच में कुछ गड़बड़ी सामने आती है तो उनका तुरंत उपचार हो. उनका हेल्थ कार्ड बने और उसमें जांच एवं उपचार की समय-समय पर एंट्री हो.

डे केयर सेंटर बनाएं

लोकायुक्त ने अपने आदेश में साफ़ तौर पर हर ज़िला अस्पताल में डे केयर सेंटर बनाने के लिए कहा है. इनमें पीड़ित मरीज़ को भर्ती कर उनका तुरंत उपचार शुरू किया जा सके. नागपुर शहर के डागा अस्पताल में एक डे केयर सेंटर शुरू किया गया है, लेकिन इस अस्पताल में केवल महिलाओं का उपचार होता है. ऐसे में नागपुर ज़िले के पुरुष मरीज़ों का उपचार कहां होगा? कुछ ज़िलों में डे केयर सेंटर में केवल 2 बेड ही है. ऐसे में यदि अधिक मरीज़ आते हैं तो उनका अस्पताल प्रशासन कैसे उपचार देगा? लोकायुक्त ने सरकार को सिकलसेल बीमारी का टी.वी., अखबार, लोककला आदि प्रसार माध्यमों के जरिए व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार करने के भी आदेश दिए हैं, लेकिन इस पर भी अमल नहीं हो पा रहा है.

सही दिशा में हो शोध

आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग बीमारी के संबंध में सही दिशा में शोध करे. मसलन यदि एक परिवार में दो भाई है, लेकिन इनमें से केवल एक को ही सिकलसेल है या दोनों को सिकलसेल है, लेकिन एक को ही तकलीफ़ है तो इसके कारणों की जांच करे और उसके उपाय तलाशे जांए. इसके उलट राज्य सरकार अब तक सर्वेक्षण का काम नहीं कर पाई है. सिकलसेल के मरीज़ों और उसके साथ एक व्यक्ति को उपचार के लिए ज़िला अस्पताल तक आने हेतु सरकारी बस का पास देने के आदेश लोकायुक्त ने दिए हैं. सिकलसेल बीमारी से संबंधित सभी मुद्दों को देखने के लिए एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरह सिकलसेल कंट्रोल सोसाइटी बनाने के भी आदेश है. सरकार का कहना है कि दोनों प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि पिछले 10 वर्षों से ये मांगें प्रलंबित है, लेकिन सरकार अब भी उन पर केवल विचार ही कर रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि किसी गंभीर प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए सरकार को क्या 10 वर्षों का समय भी कम है? लोकायुक्त ने इन मुद्दों पर अमल के लिए राज्य सरकार को 19 जुलाई 2011 तक का समय दिया था.

कहां ख़र्च हुए 52 करोड़ रुपये

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर, वर्धा, भंडारा, गढ़चिरोली, चंद्रपुर, गोंदिया, अमरावती, यवतमाल, अकोला, वाशिम, बुलढाना, धुलिया, नंदुरबार, जलगांव, औरंगाबाद, रायगढ़, नासिक, ठाणे और नांदेड़ ज़िलों में सिकलसेल से पीड़ित मरीज पाए गए हैं. अब इनमें मराठवाड़ा के हिंगोली ज़िले को भी शामिल किया गया है. सिकलसेल बीमारी से संबंधित कोई सर्वेक्षण नहीं होने से इससे पीड़ितों की सटीक संख्या नहीं बताई जा सकती, लेकिन अनुमानित तौर पर यहां सिकलसेल बीमारी से प्रभावितों की संख्या 30 लाख से भी अधिक बताई जाती है. बीमारी को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने एनआरएचएम के जरिए राज्य सरकार को वर्ष 2006 से अब तक 52 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं. इन रुपयों का आखिर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया? कहां-कहां यह राशि ख़र्च की गई? यदि ये रुपये सिकलसेल से पीड़ित मरीज़ों पर ख़र्च किए गए, तो उसके परिणाम क्यों नहीं दिख रहे? इसका कोई लेखा-जोखा राज्य सरकार के पास नहीं है. वहीं दूसरी ओर गुजरात और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने इसके लिए अलग से 30 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अपने बजट से दी है.

क्या बीमारी है सिकलसेल

सामान्य व्यक्ति के खून में लाल रक्त कोशिकाएं गोल आकार की होती हैं, लेकिन सिकलसेल बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में इनका आकार सिकल यानी हसिए जैसा होता है. ये कोशिकाएं कम ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं. पीड़ित के शरीर में हिमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मरीज़ों को खून देना पड़ता है. एएस पैटर्न के व्यक्ति को सिकलसेल वाहक कहते हैं. जो सामान्य जीवन जीते हैं. उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती. वहीं एसएस पैटर्न के व्यक्ति को सिकलसेल पीड़ित कहा जाता है. इसे ब्रेन, आंख, लंग, दिल, लीवर, स्पीनल, किडनी में अक्सर तकलीफ़ होती है. शादी के पहले लड़का-लड़की को खून की जांच करानी चाहिए. गर्भावस्था में भी जांच से होने वाले बच्चे को सिकलसेल है या नहीं पता लगाया जा सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

आतंकवादियों के निशाने पर स्कूल

आतंकवादी मुंबई आने वाले विदेशी नागरिकों, वीवीआईपी व्यक्ति या सेलिब्रिटी व्यक्ति के साथ ही उन स्कूलों को भी निशाना बना सकते हैं, जिनमें उक्त व्यक्तियों के बच्चे पढ़ने जाते हैं. ऐसे सभी स्कूलों की सुरक्षा को लेकर सरकार अब गंभीर होती जा रही है. सभी स्कूलों में चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार ने कड़े क़दम उठाने का निर्णय लिया है. खुफिया एजेंसियों द्वारा आतंकवादी हमलों की आशंका पर ग़ौर करें तो आतंकवादियों का अगला निशाना राज्य की कई मशहूर स्कूल ही हैं. खास कर वे जहां वीवीआईपी और सेलिब्रिटी के बच्चे पढ़ने जाते हैं. हालांकि यह आशंका तीन वर्ष पूर्व ही जताई गई थी, लेकिन राज्य सरकार अब नींद से जागी है. राज्य सरकार ने इन स्कूलों के साथ-साथ राज्य की सभी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्णय लिया है. पुलिस विभाग मुंबई से इस काम की शुरुआत कर चुका है.

यह तो सर्वविदित है कि आतंकवादी दहशत फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. उन्हें इसकी ज़रा भी परवाह नहीं रहती कि उनके सामने बच्चा है या मरीज़. उनका मुख्य उद्देश्य होता आतंक मचाना और भारत में हिंसा कर उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना. इसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं. 26/11 के हमले से यह बात साबित हो चुकी है. इसलिए आतंकवादी स्कूलों में हमला कर अपनी मांगों को मनवाने के लिए बच्चों को बंधक बना सकते हैं, क्योंकि स्कूल व वहां पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं. इसलिए स्कूलों को आतंकवादी आसानी से निशाना बना सकते हैं. ऐसे में राज्य में जब कभी भी आतंकवादी हमला होने की आशंका बनी रहती है तो स्कूलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बढ़ जाती है.

मुंबई पर जब आतंकवादियों ने 26/11 का हमला किया था, उसके बाद से ही राज्य की स्कूलों पर आतंकवादी हमला होने की आशंका व्यक्त की जा रही है. इस घटना को तीन वर्ष बीत चुके हैं. तभी सभी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट करने का भी निर्णय राज्य सरकार ने लिया था. इतना गंभीर विषय होने के बावजूद यह निर्णय भी तीन वर्षों तक अधर में लटका रहा. अब कहीं जाकर इस काम के लिए पुलिस सक्रिय हो गई है. उल्लेखनीय है कि वीवीआईपी और सेलिब्रिटी के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, उन पर हमेशा सुरक्षा विभाग की नज़र रहती है, लेकिन आतंकवादियों के किसी भी हद तक जाने की आशंका गुप्तचर विभाग द्वारा बार-बार व्यक्त करने से केंद्र ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है. राज्य की सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य शिक्षा मंडल की स्कूलों के संबंध में केंद्रीय गृहमंत्रालय ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सुरक्षा शाखा के पुलिस उपायुक्त के पास स्कूल सुरक्षा संबंधी नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई है. मुंबई की प्रमुख स्कूलों की सुरक्षा के संबंध में इन निर्देशों को लागू कराने की दिशा में काम शुरू हो चुका है. जल्द ही राज्य के अन्य ज़िलों में भी यह काम शुरू किया जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से स्कूलों की सुरक्षा के संबंध में देश के सभी पुलिस प्रमुख, शिक्षा विभाग के उपसंचालक, प्रधान सचिव आदि को पत्र भेजे गए हैं. मुंबई में स्थित सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य शिक्षा मंडल की प्रमुख 40 स्कूलों की सुरक्षा को लेकर वहां के संचालक, व्यवस्थापकीय मंडल और प्राचार्यों/मुख्याध्यापकों से मिलकर सभी दिशा-निर्देशों को लागू किया जा रहा है. हालांकि इनमें से कई मुद्दों पर अधिकतर स्कूल पहले से ही अमल कर रहे हैं. शाला व्यवस्थापन की ओर से सुरक्षा के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों पर अमल हो रहा है अथवा नहीं इसकी जांच हर महीने की जाएगी. इसमें कुछ भी कमी पाई जाने पर संबंधित स्कूलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं. ख़ैर यह अच्छी बात है कि राज्य सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नज़र आ रही है.

सुरक्षा के दिशा-निर्देश

- सभी स्कूलों के परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य हो.
- स्कूलों की सुरक्षा दीवारें ऊंची होनी चाहिए.
- स्कूल के अंदर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जांच करने, उससे उसका पहचान पत्र मांगना.
- स्कूल शुरू करने और बंद करने के पूर्व सुरक्षा रक्षक द्वारा स्कूल की सुरक्षा दीवार की अच्छे से जांच करना.
- स्कूल के मुख्य द्वार पर खड़े सुरक्षा रक्षक और मुख्याध्यापक की सीधी बात हो सके, इसके लिए इंटरकॉम की व्यवस्था करना.
- आपातकालीन स्थिति में विद्यार्थियों को तुरंत सूचना दी जा सके, इसके लिए अनाउंसमेंट और अलार्म सिस्टम तैयार करना.
- रात के समय स्कूल परिसर में उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए.
- सुरक्षा दीवार से लगे पेड़ों की टहनियां समय-समय पर काटने, जिससे कोई अवैध रूप से प्रवेश न कर सके.
- स्कूल शुरू रहते समय सभी गेट बंद रखना चाहिए.
- स्कूल बस के चालक और परिचालकों के साथ-साथ सभी शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के बारे में पूरी जानकारी अनिवार्य रूप से एकत्र करना चाहिए.
- सभी प्रमुख स्कूलों के सुरक्षा का ऑडिट समय-समय पर करना

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ये क्या हो रहा है...

सरकार से दरकार

मुख्यमंत्री जी आपके राज्य में यह क्या हो रहा है. आपकी चुनावी सभा में एक कपास उत्पादक किसान ने आपके समक्ष ज़हर पीकर अपनी इहलीला समाप्त करने की कोशिश की. आखिर आपकी सरकार से जनता का मोह क्यों भंग हो गया है? कभी कोई निराश जन मंत्रालय में जाकर आत्महत्या करने का प्रयास करता है, तो कभी किसी अधिकारी के कार्यालय के सामने. अब आपकी सभा में भी निराशा में डूबे किसान अपना जीवन ख़त्म करने का दुस्साहसिक कदम उठाने लगे हैं. आखिर सरकार को हो क्या गया है? जब तक किसी बात को या समस्या को लेकर दो-चार लोगों की जान न चली जाए, चारों ओर से आलोचना न होने लगे तब तक सरकार बहरी क्यों बनी रहती है? जब आपकी चुनावी प्रचार सभा में किसान आत्महत्या करने लगे तो अगली चुनावी सभा में आपने तुरंत शीतकानील सत्र में कपास उत्पादकों को प्रति एकड़ के हिसाब से राहत पैकेज दिए जाने का संकेत देना शुरू कर दिया है. अभी धान व सोयाबीन उत्पादकों के संबंध में मुख्यमंत्री जी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं. ऐसा लगता है कि एक-दो धान व सोयाबीन उत्पादकों द्वारा जब तक आपकी सभा में अपने जीवन को समाप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक उनको राहत देने का विचार आपके मन में नहीं आएगा! इसलिए तो कपास उत्पादक किसान द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने के बाद आपने कपास उत्पादकों को पैकेज देने का संकेत दिया है, लेकिन धान व सोयाबीन किसानों को भुला दिया, जबकि राज्य में कपास के साथ ही धान व सोयाबीन उत्पादक भी अपनी उपज का उचित भाव पाने के लिए आंदोलनरत हैं. माना की आपकी सरकार बहुत बिजी है. शीतकालीन सत्र सिर पर है. राज्य में आचार संहिता लगी है. पूरी की पूरी सरकार चुनावी प्रचार के लिए राज्य भर में नगर-नगर में घूम रही हैं. मंत्री झंडा ऊंचा रहे हमारा की तर्ज पर पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे है. कांग्रेस का हाथ ग़रीब के साथ और राष्ट्रवादी कांग्रेस की टिक-टिक करती घड़ी करे समय से जनता का काम वगैरह-वगैरह नारे लगवाये जा रहे हैं, लेकिन ग़रीब कपास, धान और सोयाबीन किसान परेशान हैं. उनकी सुनने वाली सरकार न राजधानी मुंबई में है और न ही उप राजधानी नागपुर में. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री लाव-लश्कर के साथ चुनावी प्रचार में लगे हैं. इन हालात में जनता जाए तो कहां जाए. जब मंत्री-संतरी के पास जनता की बातें सुनने का वक्त नहीं है, काम रुके हुए हैं. समस्याओं का समाधान हो नहीं रहा है. लिहाज़ा राज के नागरिकों के मन में आपकी सरकार के प्रति निराशा बढ़ती जा रही है. उसकी नज़र में आपके मंत्री खुदगर्ज़ हैं. अफसर निकम्मे हैं. वे अपनी ओर से जनता को वर्तमान नियम-क़ायदों के तहत राहत पहुंचाने का रास्ता निकालने की बजाय उलटा उसका शोषण करते हैं. यही वह वजह है जिसके कारण अपनी मांग को मनवाने के लिए विवश होकर एक किसान, एक युवक को आत्महत्या करने जैसा जघन्य कदम उठाना पड़ता है. आखिर आपकी सरकार किस दिशा की ओर जा रही है? इस स्थिति में भी आपकी सरकार की बेशर्मी यह है कि आपके किए गए कार्यों के आधार पर जनता आपकी पार्टी को चुनाव में विजय का हार पहनाये. आप ही एक आम नागरिक के तौर पर बताइए कि क्या आप निकृष्ट, अपाहिज सरकार का समर्थन करेंगे जो जनता की अपेक्षा में खरी न उतरती हो? यदि नहीं तो आपकी पार्टी को भी जनता से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

नियोजन बैठक में मार्गदर्शन करते गढ़चिरोली ज़िला परिषद के अध्यक्ष रवींद्र ओल्लालवार, अशोक पोरेड्डीवार, श्रीकांत ओल्लालवार आदि.

कपास का प्रति क्विंटल 6,500 हज़ार रुपये का भाव देने की मांग का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपते हुए यवतमाल ज़िले के किसान.

चंद्रपुर के चांदा क्लब ग्राउंड में संत रमेशभाई ओझा के प्रवचन कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों लोग. इंसेट में संत रमेशभाई ओझा.

आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के चयन के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इच्छुक उम्मीदवारों की परीक्षा ली. मुंबई में परीक्षा देते हुए इच्छुक उम्मीदवार.

बेटी बचाओ अभियान के तहत नागपुर शहर में निकाली गई जनजागृति रैली में शामिल विद्यार्थियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि

गोंदिया ज़िले की अर्जुनी में राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम अभियान रैली में शामिल शिक्षिकाएं, विद्यार्थी व महिलाएं.

नगर पालिका चुनाव में राकांपा के उम्मीदवारों के प्रचारार्थ भंडारा ज़िले की पवनी तहसील में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल और मंचासीन विधायक राजेंद्र जैन, पूर्व राज्यमंत्री विलास श्रृंगारवार, ज़िला बैंक के अध्यक्ष सुनील फुंडे व अन्य.

यवतमाल के राजस्व भवन में नगरपालिका चुनाव में तैनात होने वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हुए अधिकारी राऊत व अतुल पंत.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 19 दिसंबर–25 दिसंबर 2011

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

ग़रीब आदमी की क़ानून के मकड़जाल में उलझ कर न्याय पाने के लिए सरकारी कार्यालयों से लेकर मंत्रालय व न्यायालय के चक्कर लगाते-लगाते उम्र गुजर जाती है.

ज़मीन घोटाला
बिल्डर-ठेकेदार और प्रशासन का गठजोड़

आलोक मिश्रा

राज्य का शासन-प्रशासन किसके लिए होता है? संभवत: सभी का उत्तर होगा- जनहित में कार्य करने के लिए, लेकिन राज्य के अमरावती वासियों का जबाव इससे जुदा है. उनके अनुसार ज़िला प्रशासन बिल्डरों के लिए है. अमरावती में घटित 0.39 आर ज़मीन घोटाले से तो यही ज़ाहिर होता है. असलियत तो यही है कि आम आदमी के लिए सारे नियम-क़ानून लागू हो जाते हैं, लेकिन बिल्डरों, ठेकेदारों उद्योगपतियों और धन्नासेठों के लिए शासन-प्रशासन क़ानून को धता बताकर सारे नियम शिथिल कर देता है या उसे नज़रअंदाज कर देता है. यही वजह है कि भ्रष्टाचार तेज़ी से पनपता है. सही कहा है गोस्वामी तुलसीदास ने कि समरथ को नाहीं दोष गोसाईं. मंत्री से संतरी तक सामर्थ्यवानों के ग़ैर-क़ानूनी कार्यों को नियमित करने तक के लिए क़ानून तक में बदलाव करने के लिए सरकार पर दबाव डालने लगते हैं. वहीं ग़रीब आदमी की उम्र क़ानून के मकड़जाल में उलझ कर न्याय पाने के लिए सरकारी कार्यालयों से लेकर मंत्रालय व न्यायालय के चक्कर लगाते-लगाते उम्र गुजर जाती है. इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है लवासा लेक सिटी का प्रकरण, जिसे हर नियम-क़ायदे का उल्लंघन करने के बाद भी राज्य से लेकर केंद्रीय मंत्री तक उसके निर्माण को मंजूरी दिए जाने की वकालत करते नज़र आए. अब लवासा की तरह ही अमरावती ज़िले में 500 करोड़ रुपये से अधिक के 0.39 आर ज़मीन घोटाले मामले में भी शासन-प्रशासन व राजनेताओं का रवैया भी लवासा मामले की तरह है. अब तक जो हुआ ठीक है, आगे से ग़लती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस घोटाले में कलेक्टर से लेकर मनपा आयुक्त व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सहित कनिष्ठ कर्मचारी लिप्त हैं. बिल्डरों से ज़िले के राजनेताओं के धनिष्ठ संबंध हैं. इस मामले मे सबसे मज़ेदार बात यह है कि अधिकांश गोलमाल पति (मनपा आयुक्त) और पत्नी (कलेक्टर) की जोड़ी ने किया है.

अमरावती ज़िले में क़रीब पिछले 2005 से ज़िला व महानगर पालिका प्रशासन से मिलीभगत कर बिल्डरों द्वारा 0.39 आर ज़मीन घोटाला किया जा रहा था. इसमें तब और तेज़ी आई जब मियां-बीबी की जोड़ी के हाथों ने ज़िला व मनपा प्रशासन की बागडोर संभाली. अकेले कलेक्टर क्रृचा बागला और मनपा आयुक्त नवीन सोना (दोनों पति-पत्नी हैं) के ही कार्यकाल में क़रीब 60 से अधिक मामलों को सारे नियम-क़ायदों की अनदेखी कर मंज़ूरी दी गई है. इस तथ्य का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है. कलेक्टर व मनपा आयुक्त की सहमति के बिना 357 लेआउटों में बिल्डर तक़रीबन 17,85000 चौरस फुट ज़मीन का वारा-न्यारा करके शासन को करोड़ों का चूना नहीं लगाया जा सकता था. सिर्फ़ सरकार को ही चूना नहीं लगाया है, बल्कि हज़ारों उन ज़मीन लेने वालों के साथ धोखाधड़ी की जो अपनी गाढ़ी कमाई से अपने घर का सपना संजोये थे, लेकिन मियां-बीबी (कलेक्टर-मनपा आयुक्त) की जोड़ी ने आम लोगों के इस सपने को खंडित कर दिया. उन्होंने खास लोगों के हितों को तवज्जो देना जायज समझा, जबकि उनका कर्तव्य था कि ज़मीन के टुकड़े कर 0.39 आर के तहत किए गए प्रावधानों के नाजायज़ तरीके से उपयोग करने को रोका जाए, लेकिन उक्त जोड़ी ने सारे नियम क़ायदों को नज़रअंदाज कर बिल्डरों को लाभ पहुंचाते रहे. इस घोटाले में नगर रचना विभाग के अधिकारी भी दोषी हैं.

क्रृचा वागला, ज़िलाधिकारी, अमरावती

नवीन कुमार सोना, मनपा आयुक्त

शफीक राजा, सामाजिक कार्यकर्ता

दिगांबर लुंगारे, सहायक संचालक

सुजाता कडू, सहायक संचालक

दरअसल मुंबई ज़मीन धारण के टुकड़े करने पर प्रतिबंध लगाने बाबत व उसके एकीकरण करने बाबत अधिनियम 1947 के तहत 0.40 आर यानी 40 हज़ार चौरस फुट या उससे अधिक ज़मीन पर ही लेआउट को मंज़ूरी दी जाती है, जिसके तहत एम्युनिटी के तौर पर खेल के मैदान, बगीचे आदि के लिए 10 प्रतिशत चौरस फुट का ओपन स्पेस छोड़ना नियमत: अनिवार्य है, लेकिन 0.39 आर लेआउट पर 10 प्रतिशत की खुली जगह छोड़ने की अनिवार्यता ख़त्म हो जाती है. इसी का लाभ उठाकर अमरावती के बिल्डरों व डेवलपरों ने लेआउट को टुकड़ों में दर्शाकर 0.39 आर की मंज़ूरी करवा ली. आश्चर्य की बात यह है कि महानगर पालिका के रचना विभाग ने भी आसानी से धड़ाधड़ मंज़ूरी देता चला गया. परिणामत: बिल्डरों ने जहां इसका लाभ उठाकर अपनी तिजोरियां भरीं, वहीं ऐसे 357 लेआउटों मे रहने वाले लोगों को खेल के मैदान, बाग-बगीचों आदि जैसी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है. सरकार को स्टाम्प ड्यूटी से मिलने वाली करोड़ों की राशि का नुक़सान अलग से हुआ है. वर्ष 2005 से जारी इस घोटाले का सिलसिला सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से लगातार चलता रहा है. इस पर रोक लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया. जब क्रृचा बागला कलक्टर बनकर और उनके पति नवीन सोना मनपा आयुक्त बनकर आए तो उनसे अमरावती वासियों को अपेक्षा थी कि इस घोटाले को दोनों मिलकर रोकेंगे, लेकिन हुआ एकदम उलटा. दोनों के अमरावती में पदस्थ होने के बाद इस गोरखधंधे में और तेज़ी आ गई. इस पूरे मामले में अमरावती शहर व ग्रामीण के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों की भूमिका भी संदेह के घेरे में हैं.

ज़मीन घोटाले के इस प्रकरण को विधायक रवि राणा और डॉ. अनिल बोंडे ने विधानमंडल के वर्षाकालीन सत्र में भी उठाया था. इस पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने जांच कराने की घोषणा की थी. उसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के नगर विकास मंत्रालय के मुख्य सचिव टी.सी. बेंजामिन द्वारा गठित विशेष चार सदस्यीय समिति 0.39 आर ज़मीन घोटाले की जांच करने आयी. इस चार सदस्यीय समिति में यवतमाल नगर रचना विभाग के सहसंचालक जे.एम. धूत, नासिक के श्रीधर दाभाड़े, नागपुर के ए.एल सिसोदिया और पुणे के एस.बी. बारई शामिल थे. इस चार सदस्यीय समिति की जांच में भी कलेक्टर क्रृचा बागले, मनपा आयुक्त नवीन सोना सहित नगर रचना विभाग को दोषी पाया गया था. सितंबर माह में समिति ने जांच रिपोर्ट नगर विकास मंत्रालय के मुख्य सचिव को सौंप दी है, लेकिन रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. जांच समिति के अमरावती आने के पहले मुख्यमंत्री कार्यालय, मुंबई से नगर रचना विभाग के चार सहायक संचालकों को निलंबित करने का आदेश आया था जिसे भी दबा दिया गया. जिन लोगों पर निलंबन की कार्रवाई की जानी थी उनमें से कुछ का स्थानांतरण अन्यत्र ज़िले में कर दिया गया.

मायनॉरिटीज डेवलमेंट सोसायटी ऑफ विदर्भ, अमरावती के अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता शफीक राजा ने जब इस घोटाले की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत जो दस्तावेज़ प्रशासन से प्राप्त किए उनके अनुसार वर्तमान कलेक्टर व मनपा आयुक्त के समय में ही 60 से 80 मामलों को मंज़ूरी दिए जाने की बात साफ़ हो जाती है. शफीक राजा का कहना इस प्रकरण में हमने अमरावती के सिटी कोतवाली, गाडगेनगर, राजापेठ, फ्रेजरपुरा, बड़नेरा और खोलापुरी थाने में एफआईआर दर्ज़ करा दी है. एफआईआर में कलेक्टर श्रीमती क्रृचा बागला, मनपा आयुक्त नवीन कुमार सोना सहित रचना नगर रचना विभाग के सहायक संचालक दिगांबर लुंगारे, सहायक संचालक श्रीमती सुजाता कडू, सहायक संचालक सु.पु मेहेर, इस घोटाले के दरम्यान ज़मीन के टुकड़े करके ख़रीदी-बिक्री करने देने वाले अमरावती के शहर व ग्रामीण के सब रजिस्टार और इस समय के दौरान ज़मीन के टुकड़ों का सातबारा बनाने वाले पटवारियों को आरोपित किया गया है. इसके अलावा इस पूरे प्रकरण में पूर्व कलेक्टर पुरुषोत्तम भापकर और पूर्व मनपा आयुक्त उदय राठौर को भी ज़िम्मेदार माना जा रहा है. भापकर वर्तमान में औरंगाबाद मनपा के आयुक्त पद पर पदस्थ हैं. सबसे अधिक मामले उदय राठौर के मनपा आयुक्त रहने के दौरान हुए हैं. इस 0.39 आर मामले में सबसे मुख्य भूमिका नगर रचना विभाग के अधिकारियों की है जो बिल्डरों को ज़मीन से अधिक से अधिक कमाई करने की राह बताते हैं. उनके मुताबिक शिकायत की कॉपी पुलिस आयुक्त को भी दी है. पुलिस आयुक्त ने कहा था कि इस मामले पर जो भी दोषी हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वह कलेक्टर हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, लेकिन उसके दो दिन बाद ही उनके स्वर बदल गए. कहने लगे कि जब नगर विकास मंत्रालय द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट मिलेगी तब कार्रवाई करेंगे. ऐसा लगता है कि वे भी बिल्डर लॉबी के दबाव में आ गए हैं. इसलिए वे अपने बयान से पलट गए हैं.

राजनीति भी शुरू

इस ज़मीन घोटाले के मामले में राजनीति भी शुरू हो गई. घोटाले से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बिल्डरों का पक्ष राजनेता भी ले रहे हैं. ज़िले के विधायक इस मामले में बंटे हुए हैं. जहां राष्ट्रपति के विधायक पुत्र राजेंद्र शेखावत उर्फ राव साहब का रुख पूरी तरह से बिल्डरों के पक्ष में है, वहीं विधायक रवि राणा मामले की गंभीरता से जांच करने के पक्ष में हैं. शेखावत का मानना है कि 0.39 आर मामले में जो भी ग़लतियां हुई हैं उनको छोड़ दिया जाए और यह ध्यान रखा जाए कि इस तरह की पुन: ग़लती न हो. दूसरी ओर राणा दोषियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की बात करते हैं. यह भी आशंका जताई जा रही है कि सरकार राजनीतिक दबाव के चलते ही दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रही है.

पूरे राज्य में घोटाले की आशंका

ज़मीन सौदों के जानकारों का कहना है कि 0.39 आर जैसे ज़मीन घोटाले पूरे राज्य में होने की आशंका है. विदर्भ के अकोला, नागपुर, चंद्रपुर, यवतमाल जैसे शहरों में भी काफी संख्या में लेआउट डाले जा रहे हैं. यहां भी बिल्डर-ठेकेदारों द्वारा 0.39 आर के प्रावधान का सहारा अपनी तिजोरियों को भरने के लिए किया जाता है. इससे राज्य में सभी प्रकार के लेआउटों के सौदों की जांच यदि की जाती है तो अरबों का घोटाला सामने आ सकता है.

आरटीआई से हुआ खुलासा

क्रमांक	बिल्डर का नाम	मौजा	ज़मीन सर्वेक्रमांक
1.	मंगेश राजेंद्र चर्जन	रहाटगांव	176/ 4
2.	प्रल्हाद किसनजी चर्जन	रहाटगांव	176/ 3
3.	प्रशांत नंदकिशोर राठी	रहाटगांव	160/ 2 अ
4.	अभिजीत दिनकर पांडे	रहाटगांव	7/ 2 (गांव)
5.	नेहा कृष्णराव पाटिल	रहाटगांव	165/ 3
6.	ज्ञानेश्वर शंकरराव हिवसे	रहाटगांव	130/3 पैकी
7.	सौ.संगीता प्रफुल्ल कडु	रहाटगांव	130/3 पैकी
8.	अशोक कुमार रतनलाल जी सोनी	रहाटगांव	186/2 पैकी
9.	जयसिंह महावीर सिंह ठाकुर	रहाटगांव	185/1 अ भाग
10.	हेमंत कुमार रामनिवास जी व्यास	रहाटगांव	186/ 1 ब

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No.RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

दीप्ति नवल के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में उन्होंने एक वृद्ध सेक्स वर्कर का किरदार निभाया है, जो 12 वर्षीय बच्चे की मां है.

twitter facebook

सोशल नेटवर्किंग साइट्स और फिल्मी सितारे

रीतिका सोनाली

एक छोटे एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान पसलियों में चोट लग गई...अंदर कुछ नुक़सान हुआ है. सांस लेने में परेशानी हो रही है. रात के तीन बज रहे हैं...कौन बनेगा करोड़पति का एपिसोड शूट करके घर लौट रहा हूं...सुबह जल्दी उठकर फिल्म की शूटिंग पर जाना है...

ऐसे कई संदेश हैं, जो फिल्मी सितारे ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपडेट करते रहते हैं. कई लोगों का मानना है कि ये संदेश बेमतलब होते हैं और इन्हें पढ़ना समय की बर्बादी है. फिल्मी सितारों की दिनचर्या से किसे क्या मतलब? वह क्या खा रहा है, यह जानकर हमें क्या करना है? वह कब सोने जा रहा है, यह जानकर ज्ञान में तो कोई वृद्धि नहीं हो रही है. लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ये संदेश केवल सितारों के बारे में जानकारी ही नहीं देते, बल्कि प्रेरणाप्रद भी हो सकते हैं. जगज़ाहिर है, जितनी लोकप्रियता फिल्मी सितारों की है, उतनी किसी और की नहीं. इसका अंदाज़ा इनके फॉलोअर्स की संख्या देखकर लगाया जा सकता है. इनमें से ज़्यादातर युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके हाथ में मोबाइल या लैपटॉप होता है. इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या बहुत है. जल्द ही भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल वाले देशों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर आ जाएगा. युवा वर्ग फिल्मों का शौक़ीन है, इसलिए सेलिब्रिटीज ब्लॉग और ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं.

युवा अपने प्रिय सितारे के इस कदर दीवाने रहते हैं कि उन्हें उनके बारे में हर पल की ख़बर रखना पसंद है. अपनी बातचीत में वे इसका उल्लेख करते हैं. आम नज़रिया यह है कि फिल्मी सितारों द्वारा ट्विट करने से उनका ही लाभ होता है, बैठे-ठाले प्रचार हो जाता है. इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब वे ट्वीट करते हैं कि वे रात के तीन बजे या देर रात काम करके घर लौट रहे हैं तो उनके हज़ारों प्रशंसकों तक यह बात पहुंच जाती है. पल भर के लिए सोचकर देखा जाए तो ख़ूबसूरत और लैविश दिखने वाले ये सितारे कितनी मशक्कत के बाद कोई मुक़ाम हासिल करते हैं और अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं. इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के संदेशों का युवाओं पर काफी असर होता है. सिर्फ़ यही नहीं, इन ट्विट के ज़रिए सेलिब्रिटीज को समझने, उनकी सोच जानने में मदद मिलती है.

देश की प्रमुख घटनाओं के बारे में भी कुछ कलाकार ट्विट कर अपनी राय देते हैं. चाहे वह अन्ना हजारे का आंदोलन हो या भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन. किसी भी तरह की घटना पर किसी सेलिब्रिटी की प्रतिक्रिया ट्विट के माध्यम से उसके प्रशंसकों तक पहुंचती है तो वे खासकर युवा वर्ग उसमें दिलचस्पी लेकर सार्थक भूमिका निभाने का प्रयास करता है. अपनी राय जताकर युवा वर्ग सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है. उसे अपनी नैतिक ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है, गुमराह और गुमनाम होते युवा वर्ग की चेतना का विकास होता है. कई बार ट्विटर के ज़रिए कलाकार बड़ी अच्छी बातें बताते हैं. जैसे कि साथी गायकों या संगीतकारों के जन्मदिन या पुण्यतिथि पर लता जी उन्हें याद करती हैं. कुछ ऐसी बातें बताती हैं, जो किसी को नहीं मालूम होतीं. अमिताभ अक्सर ऐसी बातें बताते हैं, जो उनसे किसी ने पूछी न हों. उन्होंने अपने दादा बनने की बात ट्विट करके ही सभी को बताई थी.

हालांकि यह भी ग़लत नहीं है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए करते हैं. अब इंडस्ट्री की हॉट गर्ल मानी जाने वाली पूनम पांडेय को ही लीजिए. उन्होंने जबसे ट्विटर पर अपना एकाउंट खोला है, तबसे वह सेमी न्यूड तस्वीरें पोस्ट करने की वजह से चर्चा में रहती हैं. लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वह अपनी एक हॉट पिक्चर ज़रूर पोस्ट करती है. पूनम ने ट्विटर को पब्लिसिटी पाने का प्लेटफॉर्म बना लिया है, लेकिन ऐसी हस्तियां अपवाद स्वरूप हैं. इन सब चीजों से लोगों को लुभाने की एक सीमा है, लोग बहुत ज़्यादा वक़्त तक यह सब पसंद नहीं करते. इसका पता चलता है, फॉलोअर्स की संख्या देखकर. हर चीज के साथ उसकी अच्छाई और बुराई दोनों ही जुड़ी होती हैं. यह तो हमें सोचना-समझना है कि किसे स्वीकार करना है और किसे अस्वीकार.

ritika@chauthiduniya.com

हिंदी फिल्में मुंबई तक सीमित नहीं

कई फिल्मों में अभिनय कर चुके अरविंद टाइटलर का नाम ताजनगरी आगरा में काफी जाना-पहचाना है. कृष्णा तेरे देश में, एक रात का मेहमान, साया, द शैडो, तीसरी चाल एवं ताजमहल जैसी फिल्मों के अलावा टीवी धारावाहिक तफ्तीश और भोजपुरी एलबम नाचे मयूरी में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके अरविंद से पिछले दिनों एक लंबी बातचीत हुई. पेश हैं मुख्य अंश:-

आजकल आप लगातार फिल्में कर रहे हैं....

मुझे कला के क्षेत्र में काफी समय हो गया है. पहले मैं शौकिया तौर पर फिल्मों से जुड़ा हुआ था, मगर अब इसे अपना करियर बना लिया है. इस वक़्त मेरे पास चार-पांच फिल्में हैं, जिनमें एक भोजपुरी फिल्म भी शामिल है.

आप सिर्फ़ खलनायक का रोल करना क्यों पसंद करते हैं?

यह सच नहीं है. दरअसल, कलाकार की एक छवि बन जाती है. मेरी शुरुआत खलनायक के सपोर्टिंग रोल के साथ हुई थी. अब मैं मुख्य खलनायक का रोल कर रहा हूं. ऐसी भूमिकाएं मुझे सूट करती हैं. वैसे मैं हर तरह की भूमिकाएं कर सकता हूं. कलाकार सिर्फ़ कलाकार होता है.

अभिनय का शौक कैसे हुआ?

मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था. पिता जी चाहते थे कि बड़ा होकर मैं आईपीएस अफसर बनूं, मगर मेरी मां ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. मां के आशीर्वाद और मेरे शौक ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया.

हिंदी फिल्मों के लिए आप मुंबई क्यों नहीं गए?

हिंदी फिल्मों का दायरा अब मुंबई तक सीमित नहीं है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष अनेक फिल्मों की शूटिंग होती है. इस दिशा में नोएडा और आगरा अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं.

अभिनय के क्षेत्र में सफलता का सूत्र क्या है?

सफलता का कोई तयशुदा फॉर्मूला नहीं होता. काफी लोग अभिनय करने मुंबई जाते हैं, लेकिन उन्हें मौक़ा नहीं मिल पाता. मैंने भी संघर्ष किया, लेकिन फिल्मों में अभिनय के लिए मुंबई का रुख नहीं किया. मैंने सोच लिया था कि पहले पहचान बनाऊंगा, उसके बाद करियर को आगे बढ़ाना है. मेरे पास ऑफर मुंबई से भी आ चुका है, बात बनी तो आप मुझे वहां भी काम करते हुए देखेंगे.

भविष्य की क्या योजनाएं हैं?

योजनाएं तो बहुत सारी हैं, पर उन्हें अमलीजामा पहनाना आसान नहीं है. फिल्म बनाने की योजना है, लेकिन पता नहीं, वह दिन कब आएगा.

अमिताभ आकाश
feedback@chauthiduniya.com

मनीषा की दूसरी पारी

एक छोटी सी लव स्टोरी से सुर्ख़ियों में आई मनीषा कोइराला अब बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं. उनकी फिल्म दो पैसे की धूप चार आने की बारिश अगले साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आठ मार्च को रिलीज हो रही है. ख़बर है कि वह अपनी इस फिल्म के प्रचार के सिलसिले में दो महीने के लिए मुंबई आ रही हैं. यहां वह सेक्स वर्करों के साथ कुछ समय बिताएंगी.

दीप्ति नवल के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में उन्होंने एक वृद्ध सेक्स वर्कर का किरदार निभाया है, जो 12 वर्षीय बच्चे की मां है. कुछ समय पहले तक उनके वैवाहिक जीवन में दरार की ख़बरें आ रही थीं, बात तलाक तक पहुंच चुकी थी. शायद फिल्मों में फिर से सक्रिय होने को लेकर उनके पति सम्राट दहल नाख़ुश हैं. मुंबई आने को लेकर भी उनके पति ने कई सवाल किए थे. हम तो यही कहेंगे मनीषा पहले आप अपने परिवार पर ध्यान दें, उसके बाद अपने करियर पर.

अनीता राज की वापसी

बहुत से लोग सोचते होंगे कि आख़िर अनीता राज कहां गईं. चक्कू मार दूंगी...डायलॉग हिट कराने वाली यह तारिका अब कहां है और क्या करती है, ऐसे सवाल दिल में आना लाज़िमी है, क्योंकि 1982 में उन्होंने फिल्म प्रेम गीत से डेब्यू किया था और रातोंरात स्टार बन गई थीं. 1992 में उन्होंने सुनील हिंगोरानी से शादी की थी. इस समय वह मुंबई में ऑप्टिकल स्टोर में पति का सहयोग करती हैं. उनका बेटा 20 वर्ष का है और अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है. फिल्मों में वापसी के संबंध में पूछने पर वह अक्सर कहती थीं कि यदि अच्छा रोल मिले तो काम ज़रूर करना चाहूंगी. प्रशंसकों के लिए एक अच्छी ख़बर है कि अस्सी के दशक की ख़ूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक अनीता राज भी अन्य वरिष्ठ अभिनेत्रियों की तरह बॉलीवुड में वापसी करने जा रही हैं. ख़बर है कि वह समीर कार्णिक की फिल्म चार दिन की चांदनी से वापसी कर रही हैं. फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक हीरोइन बेस्ड फिल्म है. अर्जुन हिंगोरानी के पुत्र सुनील हिंगोरानी से शादी करने के बाद अनीता फिल्मों से दूर हो गई थीं. अनीता राज के पास इस समय वक़्त है, इसलिए वह फिल्मों में वापसी कर रही हैं. उन्हें देखने वाले कहते हैं कि वह आज भी पहले की तरह जवान और सुंदर दिखाई देती हैं. उन्हें 2007 में थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन फिल्म में सितारों की भीड़ थी. इसलिए अनीता ने उसमें काम करने से इंकार कर दिया था. बकौल अनीता, फिल्म चार दिन की चांदनी में उनके लिए करने को बहुत कुछ है. अनीता राज नौकर बीवी का और गुलामी जैसी हिट फिल्मों में अपने सशक्त अभिनय के लिए आज भी याद की जाती हैं.

फिल्म प्रीव्यू

डॉन-2

एक्सेल एंटरटेनमेंट और रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्देशक फरहान अख्तर लेकर आ रहे हैं डॉन-2. निर्माताओं में फरहान के अलावा रितेश सिधवानी और शाहरुख खान भी हैं. संगीत दिया है शंकर-एहसान-लॉय ने. कलाकार हैं शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, बोमन ईरानी, ओम पुरी एवं कुणाल कपूर. पांच साल पहले पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल में डॉन (शाहरुख खान) ने ख़ुद पुलिस को उलझा दिया और उनकी नाक के नीचे से चलता बना. पुलिस जिसे पान चबाने वाला सीधा-सादा विजय समझ रही थी, दरअसल वह डॉन था. एक बार फिर चोर-पुलिस के खेल में डॉन ने पुलिस को मात दी. रोमा (प्रियंका चोपड़ा), जिसे डॉन जंगली बिल्ली कहकर पुकारता है, अभी भी अपने भाई रमेश की हत्या का बदला डॉन से लेना चाहती है. वह डॉन जैसे दिखने वाले विजय के प्यार के चक्कर में पड़ गई और यह जानकर चकित रह गई कि वह विजय नहीं, डॉन है. अब वह इंटरपोल में शामिल हो चुकी है और डॉन को पकड़ने की योजना का अहम हिस्सा है. एशिया पर डॉन अपना दबदबा बना चुका है, उसकी नज़र अब यूरोप पर है. कुआलालंपुर से उसका एक्शन अब बर्लिन शिफ्ट हो गया है. यूरोप में वह किसी भी क़ीमत पर अपना दबदबा बनाना चाहता है. इसके लिए वह अपने रास्ते में आने वाले हर शख़्स को हटाने के पहले सोचेगा भी नहीं. पुलिस और डॉन की इस लुका-छिपी का मज़ा फिर देखने को मिलेगा डॉन 2 में. फरहान को ऑल राउंडर कहा जा सकता है. अभिनय, लेखन, गायन एवं निर्देशन यानी वह सब कुछ सफलतापूर्वक कर लेते हैं. बतौर निर्देशक उनकी फिल्म पांच वर्ष बाद आ रही है. उन्होंने डॉन-द चेज़ बिगिंस अगेन का सीक्वल डॉन-2 बनाई. पिछली फिल्म रीमेक थी और इस बार डॉन-2 में मौलिक कहानी देखने को मिलेगी. दिल चाहता है (2001), लक्ष्य (2004) और डॉन (2006) जैसी फिल्में बना चुके फरहान को अच्छी समझ है. डॉन-2 के ट्रेलर्स सराहे जा रहे हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें ज़बरदस्त एक्शन और रोमांच देखने को मिलेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 19 दिसंबर–25 दिसंबर 2011

www.chauthiduniya.com

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

मायावती और लोकायुक्त की साठगांठ

अजय कुमार

बसपा सरकार की मुखिया और उनके मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं. क़रीब दो दर्जन मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, लेकिन इसमें से चंद चेहरे ही ऐसे निकले जिन्हें भ्रष्टाचार के कारण लालबत्ती गंवानी पड़ी. हाल ही में एक और मंत्री से लोकायुक्त जांच में दोषी साबित होने के बाद जबरन त्यागपत्र ले लिया गया है. लालबत्ती गंवाने वाले वह पांचवें मंत्री थे. लोग और ख़ासकर बसपाई इस बात से खुश हैं कि बहनजी न्याय की देवी बन गई हैं. वह किसी ऐसे नेता के पास लालबत्ती नहीं देखना चाहती हैं जो भ्रष्ट है लेकिन राजनीतिक पंडित परदे के पीछे कोई और खेल चलने की बात कहते हैं. उनका मानना है कि जो कुछ हो रहा है, वह प्री–प्लान है. अगर ऐसा न होता तो मायावती सरकार के कई बड़े नाम जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के सबसे अधिक आरोप लगे हैं, वे लोकायुक्त की पहुंच से दूर नहीं होते. कहा तो यहां तक जा रहा है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ही कुछ मंत्रियों को लोकायुक्त की जांच के बहाने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया हैं, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे. जबकि लोकायुक्त ने कई बड़ों को छुआ नहीं हैं और कई मंत्री लोकायुक्त की जांच में दोषी करार दिए जाने के बाद भी मायावती सरकार की शोभा बढ़ा रहे हैं.

हाल ही में अंबेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री रतनलाल अहिरवार के ऊपर ग्रामसभा की ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़े, पद एवं विधायक क्षेत्र विकास निधि के दुरूपयोग की शिकायत लोकायुक्त जांच में सच साबित हुई हैं, जिसके बाद जांच में दोषी भ्रष्ट मंत्री रतनलाल अहिरवार से मुख्यमंत्री मायावती ने इस्तीफ़ा लेकर राज्यपाल के पास भिजवा दिया जो मंजूर भी हो गया. मंत्री पद गंवाने वालों में रतनलाल का नंबर पांचवा हो गया है. इससे पहले रंगनाथ मिश्र, राजेश त्रिपाठी, अवधपाल सिंह यादव तथा बादशाह सिंह को मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी. रतनलाल का विभाग अंबेडकर ग्रामसभा पंचायती राज मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को दे दिया गया हैं. सवाल यह उठ रहा है कि इससे पहले भी लोकायुक्त जांच में बसपा के कई माननीय दोषी साबित हो चुके हैं फिर उनके ऊपर क्यों मुख्यमंत्री का विश्वास बना हुआ हैं? सबसे पहला नाम बेसिक शिक्षा मंत्री धर्म सिंह सैनी का आता है, जो डायट नियुक्तियों मे धांधलियों के लिए लोकायुक्त जांच में दोषी भी साबित हुए थे. मुख्यमंत्री ने उन्हें केवल चेतावनी देकर बख्श दिया, जबकि बेसिक शिक्षा मंत्री का भ्रष्टाचार बेसिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान में साफ़ तौर पर दिखाई दे रहा हैं, जहां अरबों के घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है. नौनिहालों की शिक्षा के भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे धर्म सिंह सैनी को मायावती द्वारा कब का मंत्रिमंडल से निकालकर बाहर कर देना चाहिए था. इसी प्रकार सीतापुर से बसपा सांसद तथा लहरपुर पालिका अध्यक्ष कैसर जहां का नाम भी कम बदनाम नहीं हैं. उनके ऊपर करोड़ों के फौव्वारा घोटाले का आरोप लोकायुक्त जांच में साबित हो चुका है. इसके बावजूद सांसद कैसर जहां बसपा की शान बनी हैं. यहां बता देना ज़रूरी है कि लोकायुक्त ने कैसर जहां की तरह ही तमाम नगर पालिका अध्यक्षों, चेयरमैन्स के भ्रष्टाचार की जांच भी की थी और उन्हें दोषी पाया था.

बहरहाल मायावती सरकार की कार्यशैली को जानने और समझने वाले जानते हैं कि उनके राज में भ्रष्टाचार तो दूर एक सिपाही तक का तबादला कोई नेता या मंत्री नहीं करा सकता है. फिर इतने बड़े घोटाले के बारे में तो सोचना ही गुनाह है. पांच–पांच मंत्रियों की बलि लेने वाले लोकायुक्त को उच्च शिक्षा मंत्री राकेशधर त्रिपाठी और डेढ़ दर्जन कमाऊ महक़मों के इकलौते मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भ्रष्टाचार नज़र नहीं आता, यह बात विपक्ष के गले नहीं उतरती. समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव कहते हैं कि बसपा सरकार में भ्रष्टाचार की जड़ें ऊपर से फल फुल रही हैं और भ्रष्टाचार के नाम पर बलि का बकरा नीचे वालों को बनाया जा रहा है. एक तरफ़ वह मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को हटाती हैं तो दूसरी तरफ़ मायावती उनकी जगह उन्हीं के भतीजे को उम्मीदवार घोषित कर देती हैं. यह दोहरी राजनीति जनता जानती और समझती है. त्रिपाठी के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की शिकायतें प्रदेश के प्रत्येक कोने में सुनने को मिल जाएंगी लेकिन लोकायुक्त लाचार हैं कि कोई गवाह नहीं मिल रहा. ऐसे ही कई मंत्रियों पर लोकायुक्त इसी लिए कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी शिकायत करने के लिए कोई आगे ही नहीं आ रहा है. ऐसा लगता है कि विरोधी ठीक कह रहे हैं कि लोकायुक्त और मुख्यमंत्री मिल कर नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं. अब तो बहुजन समाज पार्टी के भाई लोग भी दबी जुबान से कहने लगे हैं कि मायावती को जिस मंत्री की छुट्टी करानी होती है, वह उसके ख़िलाफ़ लोकायुक्त का सहारा लेती हैं. लोकायुक्त वाकई कद्दावर और भ्रष्टाचार विरोधी होते तो फिर कर्नाटक के संतोष हेगड़े की तरह सीधे मुख्यमंत्री पर ही कार्रवाई करते. आख़िर भ्रष्टाचार की कितनी कहानियां सुनने के लिए रही हैं. उत्तर प्रदेश में पोंटी चड्ढा और जेपी ग्रुप पर बहिन जी की मेहरबानियों की ही पड़ताल करा ली जाए तो उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ जाएगा.

मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता का पैसा पत्थरों पर बहा रही हैं, वह किसी से छिपी नहीं है. उनके ख़िलाफ़ तमाम आवाज़ें उठीं, लेकिन उन्हें दबा दिया गया. मायावती वोट बैंक मजबूत करने के चक्कर में लोकतंत्र का गला घोटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. कई अहम फ़ैसलों का वह सिर्फ़ इसलिए विरोध कर देती हैं कि कहीं उनका वोटर नाराज़ न हो जाएं. चाहें बात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हो, प्रदेश के बंटवारे की या फिर बुंदेलखंड पर सियासत की. मायावती सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए कर रही हैं. लोकायुक्त की बात को भी वह उतना ही मानती हैं, जिससे उनको फ़ायदा होता है. मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे में आए मंत्रियों के ख़िलाफ़ ही क़दम नहीं उठा रही हैं, बल्कि ऐसे नेताओं और विधायकों के भी पेंच कस रही हैं जिनकी छवि विवादित है. कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो क़रीब 40 वर्तमान विधायकों का टिकट काटने का मन बना चुकी हैं, लेकिन इसका ख़ुलासा इस लिए नहीं किया जा रहा है कि कहीं उनकी सरकार पर संकट के बादल न आ जाएं. बसपा सुप्रीमो को पता है कि विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा होगा, इस लिए वह भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं. ऐसे भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए वह अपनी स्टाइल से काम कर रही हैं, कभी लोकायुक्त उनके लिए सहारा बनते हैं तो कभी स्वयं फ़ैसले लेती हैं. खैर, मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त की जांच और सिफ़ारिशों के बहाने अपने कुछ मंत्रियों को जिस तत्परता से हटा कर उनके ख़िलाफ़ जांच के आदेश दिए हैं, इसमें उनकी प्रशासनिक क्षमता कम, बेताबी ज़्यादा नज़र आ रही हैं. वह तमाम तरीक़ों से अपनी पार्टी और सरकार की छवि सुधारने में जुटी हैं, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दोबारा अपनी दावेदारी पेश कर सकें. सवाल यह भी पूछें जा रहे हैं कि ऐसे दाग़ी नेताओं को लालबत्ती दी ही क्यों गई जिनकी छवि साफ़–सुथरी नहीं थी, भले ही वह चुनाव जीत कर आए हों. चार साल तक मलाई मार चुके बसपा मंत्रियों के लोकायुक्त के दायरे या अन्य मामलों में फंसते ही बहिनजी ने उन्हें काटने के लिए कंधे पर कुल्हाड़ी रख ली है.

feedback@chauthiduniya.com

नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी लोकायुक्त के घेरे में

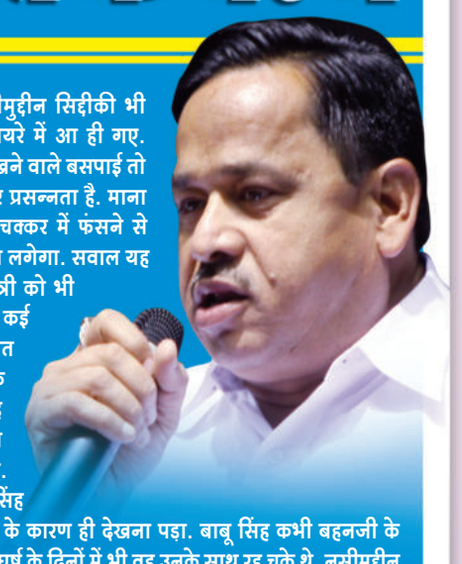

मायावती के सबसे क़रीबी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी आख़िरकार लोकायुक्त जांच के दायरे में आ ही गए. सिद्दीकी के फंसने से उनसे खुन्नस रखने वाले बसपाई तो खुश हैं ही, विपक्षी दलों में भी अपार प्रसन्नता है. माना यह जा रहा है कि नसीमुद्दीन के लोकायुक्त के चक्कर में फंसने से मायावती को राजनीतिक रूप से काफ़ी बढ़ा झटका लगेगा. सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या बहनजी अपने इस चहेते मंत्री को भी ठीक वैसे बाहर का रास्ता दिखाएंगी जैसे की पूर्व में कई नेताओं को दिखाया गया था. बुंदेलखंड की सियासत से निखर कर बाहर आए सिद्दीकी पर मुसीबत के बादल मंडराने की ख़बर मिलते ही बाबू सिंह कुशवाहा ख़ेमा कुछ ज़्यादा ही खुश है. बाबू सिंह का ख़ेमा नसीमुद्दीन के कारण लंबे समय से आहत था. राजनीतिक हलकों में यह चर्चा आम थी कि बाबू सिंह कुशवाहा को बसपा से बाहर का रास्ता नसीमुद्दीन के कारण ही देखना पड़ा. बाबू सिंह कभी बहनजी के सबसे वफ़ादार लोगों में थे, मान्यवर कांशीराम के संघर्ष के दिनों में भी वह उनके साथ रह चुके थे. नसीमुद्दीन और कुशवाहा एक ही ज़िले बांदा से आते थे. दोनों बहनजी के क़रीबी थे, लेकिन राजनीतिक और व्यापारिक महत्वाकांक्षा ने दोनों को कट्टर दुश्मन बना दिया था. बहरहाल, कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की लोकायुक्त से की गई शिकायत के आधार पर जांच शुरू हो गई है. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका (बांदा)को लोकायुक्त ने नजूल भूमि के सभी क़ब्ज़ेदारों की सूची के साथ तलब किया था. सूची के साथ तीन नाम ऐसे भी है, जिनका पूरा विवरण साक्ष्यों के साथ मांगा गया था. समाजसेवी आशीष सागर ने लोकायुक्त के यहां प्रदेश के कद्दावर मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन के ऊपर नजूल भूमि पर क़ब्ज़े, पहाड़ और मौरंग खनन के पट्टे क़रीबी व रिश्तेदारों को देने व अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गये थे. लोकायुक्त कार्यालय से ईओ नगर पालिका के पास पत्र भेजकर उक्त जानकारी मांगी गई थी. पत्र में कहा गया था कि नुरूल अमीन रऊफ सिद्दीकी और अमीरूद्दीन की नजूल भूमि से संबंधित पूरे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं. लोकायुक्त कार्यालय से नजूल के सभी क़ब्ज़ेदारों की सूची व तीन आरोपित लोगों के साक्ष्य सहित दस्तावेज मांगे गए थे. उप-जिलाधिकारी व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका(बांदा) अमित सिंह भी इस बात से इंकार नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ लोकायुक्त ने बुलाया था. उक्त अधिकारियों का कहना था कि लोकायुक्त के पत्र के अनुसार दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं जिन्हें शीघ्र से शीघ्र लोकायुक्त का सौंप दिया जाएगा.

संजय सक्सेना
feedback@chauthiduniya.com